भारत सरकार
भारत का विधि आयोग

प्रथम इत्तिला रिपोर्ट के ऑनलाइन पंजीकरण के लिए दंण्ड प्रक्रिया संहिता, 1973 की धारा 154 में संशोधन

रिपोर्ट संख्या 282

सितम्बर, 2023

22वें विधि आयोग का गठन दिनांक 21 फरवरी, 2020 के राजपत्र अधिसूचना फा.सं 45021/1/2018-प्रशासन- III (एलए) द्वारा भारत सरकार, विधि और न्याय मंत्रालय, विधि कार्यविभाग, नई दिल्ली द्वारा तीन वर्ष की अवधि के लिए किया गया था। 22वें विधि आयोग का कार्यकाल दिनांक 22 फ़रवरी, 2023 के आदेश संख्या फा.सं 60011/225/2022-प्रशा.111 (एलए) द्वारा विस्तारित किया गया। विधि आयोग में एक अध्यक्ष, तीन पूर्णकालिक सदस्य, सदस्य सचिव, दो पदेन सदस्य और दो अंश कालिक सदस्य होते हैं।

अध्यक्ष

माननीय न्यायमूर्ति ऋतुराज अवस्थी

पूर्ण कालिक सदस्य

माननीय न्यायमूर्ति के.टी. शंकरन
डॉ. आनंद पालीवाल
प्रो. डी. पी. वर्मा

सदस्य सचिव

श्री के. बिस्वाल

पदेन सदस्य

डॉ. नितेन चंद्रा, सचिव, विधि कार्य विभाग
डॉ. रीटा वशिष्ठ, सचिव, विधायी विभाग

अंश कालिक सदस्य

श्री एम. करुणानिधि
प्रो. (डॉ.) राका आर्या

विधि अधिकारी

श्रीमती वर्षा चंद्रा, संयुक्त सचिव एवं विधि अधिकारी
श्री अतुल कुमार गुप्ता, उप विधि अधिकारी

विधि परामर्शदाता

श्री ऋषि मिश्रा
श्री गौरव यादव
श्री शुभांग चतुर्वेदी
श्री दविंदर सिंह
श्रीमती प्रिया राठी
श्रीमती रुचिका यादव

विधि आयोग का पता: दूसरा एवं चौथा तल, 'बी' विंग, लोक नायक भवन,
खान मार्केट नई दिल्ली- 1 10003.
यह रिपोर्ट https://lawcommissionofindia.nic.in/ पर उपलब्ध है।
©भारत के विधि आयोग, भारत सरकार के पास सर्वाधिकार सुरक्षित

Justice Ritu Raj Awasthi
(Former Chief Justice of High Court of Karnataka)
Chairperson
22nd Law Commission of India

न्यायमूर्ति ऋतु राज अवस्थी
(सेवानिवृत्त मुख्य न्यायाधीश, कर्नाटका उच्च न्यायालय)
अध्यक्ष
भारत के 22वें विधि आयोग

आज़ादी का अमृत महोत्सव

अ.शा.सं 6(3)324/2018-एलसी(एलएस) दिनांक: 27 सितम्बर, 2023

माननीय अर्जुन राम मेघवाल,

नमस्कार।

मुझे आपको भारत के विधि आयोग की ओर से **"प्रथम इत्तिला रिपोर्ट के ऑनलाइन पंजीकरण के लिए दंड प्रक्रिया संहिता, 1973 की धारा 154 में संशोधन" रिपोर्टसंख्या 282** प्रेषित करते हुए अत्यंत हर्ष हो रहा है। विधि आयोग को भारत सरकार के गृह मंत्रालय से जून, 2018 में एक पत्र प्राप्त हुआ थाजिसके माध्यम सेआयोग से दंड प्रक्रिया संहिता, 1973 (सीआरपीसी) की धारा 154 में संशोधन की व्यवहार्यता का अध्ययन करने का अनुरोध किया गया था ताकि एफआईआर के ऑनलाइन पंजीकरण को क्रियान्वित किया जा सके। यह संदर्भ 6 से 8 जनवरी, 2018 तक बीएसएफ अकादमी, टेकनपुर, मध्य प्रदेश में आयोजित डीजीपी/आईजीपी सम्मेलन-2017 से सामने आया, जिसमें यह सुझाव दिया गया था कि एफआईआर के ऑनलाइन पंजीकरण को क्रियान्वित करने के लिए सीआरपीसी की धारा 154 में संशोधन किया जाना चाहिए।

भारत के 21वें विधि आयोग ने 20 जुलाई, 2018 को सभी उच्च न्यायालयों के मुख्य न्यायाधीशों को पत्र लिखकर उनसे अनुरोध किया कि वे अपने अधिकार क्षेत्र में न्यायिक अधिकारियों से इस विषय पर अपनी लिखित दलीलें प्रेषित करें। इसके बाद 06 अगस्त, 2018 को विभिन्न राज्यों के पुलिस अधिकारियों के साथ एक सत्र आयोजित किया गया। आयोग को उपरोक्त पर जबरदस्त प्रतिक्रिया मिली। ज्यादातर प्रतिक्रियाएं एफआईआर के ऑनलाइन पंजीकरण के लिए धारा 154 में संशोधन के पक्ष में थीं। प्रतिक्रियाओं में इस तरह की योजना से जुड़े गुण, दोष और आवश्यकताओं जैसे आईटी अवसंरचना, पुलिस कर्मियों के साथ-साथ नागरिकों की डिजिटल साक्षरता और शिकायतकर्ता के सत्यापन, आरोपी को जानकारी, अन्य कानूनों में आवश्यक संशोधन जैसे प्रक्रियात्मक पहलुओं पर भी प्रकाश डाला गया।

उपरोक्त को आगे बढ़ाते हुए, 22वें विधि आयोग ने इस संदर्भ को लिया और भारत में एफआईआर के ऑनलाइन पंजीकरण और इसके कामकाज से संबंधित कानून का व्यापक अध्ययन किया, जिसमें डिजिटल युग में इसकी उत्पत्ति और विकास का अध्ययन किया गया। आयोग ने औपनिवेशिक और स्वतंत्र भारत दोनों में एफआईआर दर्ज करने के इतिहास और इस विषय पर माननीय सर्वोच्च न्यायालय और माननीय उच्च न्यायालयों के विभिन्न

कार्यालय का पता: कमरा नंबर 405, चौथी मंजिल, 'बी विंग, लोक नायक भवन, खान मार्केट, नई दिल्ली-110003
Office Address: Room No. 405, 4th Floor, 'B'Wing, Lok Nayak Bhawan, Khan Market, New Delhi-110003
निवास: बंगलानंबर8, तीस जनवरी मार्ग, नई दिल्ली110011-
Residence: BungalowNo. 8, Tees JanuaryMarg, New Delhi-110011email:rituraj.awasthi@gov.in Tel :011-24654951(D),24340202, 24340203

Justice Ritu Raj Awasthi
(Former Chief Justice of High Court of Karnataka)
Chairperson
22nd Law Commission of India

न्यायमूर्ति ऋतु राज अवस्थी
(सेवानिवृत्त मुख्य न्यायाधीश, कर्नाटका उच्च न्यायालय)
अध्यक्ष
भारत के 22वें विधि आयोग

निर्णयों का भी विश्लेषण किया। इसके अतिरिक्त, 22वें विधि आयोग ने पुलिस सुधारों में शामिल संस्थाओं, अर्थात् राष्ट्रीय अपराध अभिलेख ब्यूरो और पुलिस अनुसंधान एवं विकास ब्यूरो के साथ व्यापक परामर्श किया। इसके अलावा, आयोग ने शिक्षाविदों, अधिवक्ताओं, वरिष्ठ पुलिस अधिकारियों आदि के साथ व्यापक विचार-विमर्श भी किया।

इसलिए, आयोग का विचार है कि ई-एफआईआर का पंजीकरण चरणबद्ध तरीके से किया जाए, जिसकी उन अपराधों से हो जिनमें तीन साल तक के कारावास का प्रावधान हो। इस से संबंधित हितधारक प्रस्तावित प्रणाली की प्रभावकारिता का परीक्षणकर सकेंगे, और साथ ही, इस तरह की सुविधा के संभावित दुरुपयोग को कम से कम किया जा सकेगा। यदि यह पाया जाता है कि प्रस्तावित प्रणाली वास्तव में प्रभावी ढंग से काम कर रही है, तो बाद के संशोधनों के माध्यम से इसका दायरा बढ़ाया जा सकता है। आयोग का मानना है कि ई-एफआईआर के पंजीकरण की सुविधा के लिए एक केंद्रीकृत राष्ट्रीय पोर्टल बनाया जाए। आयोग ने इस रिपोर्ट में इसे कार्यान्वित करने के लिए एक प्रक्रिया का सुझाव दिया है।

आयोग की राय है कि ई-एफआईआर के पंजीकरण को सामर्थ्यकारी बनाने से एफआईआर के पंजीकरण में देरी के लंबे समय से जारी समस्या का समाधान किया जा सकेगा, जिससे नागरिक वास्तविक समय में अपराधों की रिपोर्ट कर सकेंगे। इसके अलावा, यह कदम भारत सरकार की राष्ट्रीय ई-शासन योजना के अनुरूप भी होगा। उपरोक्त को ध्यान में रखते हुए, यह रिपोर्ट आपके अवलोकन हेतु सादर प्रस्तुत है।

सादर,

भवदीय,

हस्ताक्षर

(न्यायमूर्ति ऋतुराज अवस्थी)

श्रीअर्जुन राम मेघवाल
माननीय राज्य मंत्री (स्वतंत्र प्रभार),
विधि एवं न्याय मंत्रालय, भारत सरकार,
शास्त्री भवन, नई दिल्ली-110001

कार्यालय का पता: कमरा नंबर 405, चौथी मंजिल, 'बी विंग, लोक नायक भवन, खान मार्केट, नई दिल्ली-110003
Office Address: Room No. 405, 4th Floor, 'B'Wing, Lok Nayak Bhawan, Khan Market, New Delhi-110003
निवास: बंगलानंबर8, तीस जनवरी मार्ग, नई दिल्ली110011-
Residence: BungalowNo. 8, Tees JanuaryMarg, New Delhi-110011email:rituraj.awasthi@gov.in Tel:011-24654951(D),24340202, 24340203

स्वीकृति

विधि आयोग को भारत सरकार के गृह मंत्रालय से जून, 2018 का एक पत्र प्राप्त हुआ था जिसके माध्यम से आयोग से दंड प्रक्रिया संहिता, 1973 की धारा 154 में संशोधन की व्यवहार्यता का अध्ययन करने का अनुरोध किया गया था, ताकि प्रथम इत्तिला रिपोर्ट के ऑनलाइन पंजीकरण को व्यवहारिक बनाया जा सके। विधि आयोग ने संबंधित सरकारी विभागों और पुलिस सुधारों के क्षेत्र में लगी संस्थाओं के साथ विस्तृत चर्चा की। आयोग ने शिक्षाविदों, विद्वानों, न्यायाधीशों, अधिवक्ताओं, वरिष्ठ पुलिस अधिकारियों आदि के साथ भी पर्याप्त परामर्श किया। विषय से जुड़ी वैधताओं और जमीनी वास्तविकताओं के रूप में मौजूद व्यावहारिक कठिनाइयों के बारे में अध्ययन किया। हम ऐसे सभी लोगों को उनकी अति आवश्यक सलाह के लिए बहुत आभारी हैं।

22वां विधि आयोग विशेष रूप से निम्नलिखित व्यक्तियों/संगठनों के प्रति अपना हार्दिक आभार व्यक्त करता है, जिन्होंने वर्तमान विषय पर अपनी बहुमूल्य अंतर्दृष्टि, टिप्पणियां और प्रस्तुतियाँ प्रस्तुत करने के लिए अपना बहुमूल्य समय निकालाः

1. पुलिस अनुसंधान और विकास ब्यूरो
2. राष्ट्रीय अपराध रिकॉर्ड ब्यूरो
3. श्री आशुतोष पांडे, आईपीएस, एडीजी राज्य विशेष कार्य दल, उत्तर प्रदेश
4. श्री अनीश गुप्ता, आईआरएस (सी एंड आईटी) अतिरिक्त आयुक्त
5. श्री एम. नागेश्वर राव, आईपीएस (सेवानिवृत्त)) पूर्व निदेशक, केन्द्रिय अन्वेषण ब्यूरो
6. श्री सिद्धार्थ लूथरा, वरिष्ठ अधिवक्ता, उच्चतम न्यायालय
7. प्रो. (डॉ.) एन. के. चक्रवर्ती, कुलपति, पश्चिम बंगाल राष्ट्रीय न्यायिक विज्ञान विश्वविद्यालय, कोलकाता
8. डॉ. कुमार अस्कंद पांडे, एसोसिएट प्रोफेसर (विधि) डॉ. राम मनोहर लोहिया राष्ट्रीय विधि विश्वविद्यालय, लखनऊ

सलाहकार के रूप में कार्य करने वाले श्री **ऋषि मिश्रा, श्री गौरव यादव, श्री शुभांग चतुर्वेदी, श्री देविंदर सिंह, सुश्री प्रिया राठी और सुश्री रुचिका यादव** द्वारा इस रिपोर्ट को तैयार करने में प्रदान की गई सराहनीय सहायता को आयोग कृतज्ञतापूर्वक ज्ञापित करताहै। हम शोध करने और इस रिपोर्ट के मसौदे में सहायता देने में उनके सत्यनिष्ठ प्रयासों के लिए उनकी सराहना करते हैं।

विषय-वस्तु

क्र. सं.	शीर्षक	पृष्ठ सं.
1.	परिचय	7
	क. आयोग के लिए संदर्भ	7
	ख. वर्ष 2018 में 21वें विधि आयोग द्वारा किए गए परामर्श	7
	ग. वर्ष 2023 में 22 वें विधि आयोग द्वारा किए गए परामर्श	7
2.	प्रथम इत्तिला रिपोर्ट से संबंधित प्रावधान	16
	क. दंड प्रक्रिया संहिता, 1973 की धारा 154 का परिचय	16
	ख. दंड प्रक्रिया संहिता के तहत एफआईआर के प्रावधान का विकास	17
	ग. धारा 154 के लाभ एवं महत्व	19
	घ. प्रथम इत्तिला रिपोर्ट के संबंध में कुछ अन्य प्रावधान	19
3.	ई-एफआईआर के पंजीकरण की मांग	21
	क. विभिन्न आयोगों एवं समितियों की रिपोर्टें	21
	ख. शिकायत और एफआईआर में अंतर	27
4.	सरकार की ई-गवर्नेंस पहल	30
	(क) सीसीटीएनएस का प्रारम्भ	30
	(ख) सीसीटीएनएस आर्कीटेक्चर	32
	(ग) सीसीटीएनएस शिकायत पंजीकरण प्रक्रिया	33
	(घ) सी. सी. टी. एन. एस. के कार्यान्वयन की वर्तमान स्थिति	33
	(ङ) राज्यों के वेब पोर्टल पर ई-एफआईआर की लॉजिंग	34
5.	एफआईआर के पंजीकरण पर संबंधित न्यायिक प्रावधान	36
	(क) यौल्ला बार एशोसिएशन बनाम भारत संघ	36
	(ख) ललिता कुमारी बनाम उत्तर प्रदेश राज्य	38
	(ग) अपने स्वयं के समावेदनों पर न्यायालय बनाम राज्य	38
	(घ) ताजिन्दर सिंह एवं अन्य बनाम भारत संघ एवं अन्य	40
	(ङ) अरनेश कुमार बनाम बिहार राज्य एवं अन्य	40
	(च) सतेन्दर कुमार एन्तिल बनाम केन्द्रिय अन्वेषण ब्यूरो एवं अन्य	43
6.	निष्कर्ष	45
7.	अनुशंसाएं	51
	क. जिन संज्ञेय अपराधों में आरोपी ज्ञात नहीं है, उन सभी अपराधों के लिए ई-एफआईआर के पंजीकरण की अनुमति दी जाएगी।	51

	ख. 03 साल तक की सजा के प्रावधान वाले संज्ञेय अपराधों में ई-एफआईआर के पंजीकरण की अनुमति दी जाएगी।	51
	ग. राज्यों को अपराधों की सूची का विस्तार करने की शक्ति होगी।	52
	घ. ई-एफआईआर का पंजीकरण सभी अपराधों पर कार्यान्वित नहीं होगा।	52
	ङ. ई-शिकायत की अनुमति/या सभी गैर-संज्ञेय अपराधों के लिए होगी।	53
	च. इत्तिलाकर्ता/शिकायतकर्ता का सत्यापन और झूठी जानकारी के लिए सजा।	53
	छ. पक्षों की गोपनीयता सुनिश्चित की जानी चाहिए।	54
	ज. क्षमता निर्माण को महत्व दिया जाए।	54
	झ. विविध सिफारिशें।	55
	उपाबंध क: ई-एफआईआर पंजीकरण की प्रक्रिया	57
	उपाबंधख: केंद्रीय राष्ट्रीय पोर्टल	59

संक्षेपाक्षरों की सूची

एडीजी	अतिरिक्त पुलिस महा निदेशक
एप	एप्लीकेशन
एटीएम	ओटोमेटेड टेलर मशीन
बीपीआरएन्डडी	पुलिस अनुसंधान एवं विकास ब्यूरो
बीएसएफ	सीमासुरक्षाबल
सीबीआई	केंद्रीय जाँचब्यूरो
सीसीटीएनएस	अपराध और आपराधिक ट्रैकिंग नेटवर्क और प्रणालियाँ
सीसीटीवी	क्लोज्ड सर्किटटेलीविजन
सीआईपीए	सामान्यएकीकृतपुलिस एप्लीकेशन
सीपीग्राम	केंद्रीकृत लोक शिकायत निवारण और निगरानी प्रणाली
अपराधी	अपराधी
सीआरपीसी	दंड प्रक्रिया संहिता, 1973
डीएआरपीजी	प्रशासनिक सुधार और लोक शिकायत विभाग
दिल्ली एनसीआर	राष्टीय राजधानी क्षेत्र दिल्ली
डीजीपी	पुलिस महानिदेशक
डॉ.	डॉक्टर
डीवाईएसपी	पुलिस उप अधिक्षक
ईओ	जाँच अधिकारी
ईटीसी	*आदि*
एफआईआर	प्रथम इत्तिला रिपोर्ट
सरकार	सरकार
एचपी	हिमाचलप्रदेश

जे.सी.जे.एस	अंतर-संचालित दांडिक न्याय प्रणाली
आईसीटी	सूचना एवं संचार तकनीकी
आईडी	पहचान
आईईए	भारतीय साक्ष्य अधिनियम, 1872
आईजीपी	पुलिस महानिरीक्षक
आईपीसी	भारतीय दंड संहिता, 1860
आईपीएस	भारतीय पुलिस सेवा
आईआरएस	भारतीय राजस्व सेवा
आईटी	सूचना प्रौद्योगिकी
जेएडके	जम्मू कश्मीर
केवाईसी	अपने ग्राहक को जानें
एमएचए	गृह मंत्रालय
एमआईएस	प्रबंधकी सूचना प्रणाली
एमपी	मध्यप्रदेश
एनसीआरबी	राष्ट्रीयअपराधअभिलेखब्यूरो
एनसीआरपी	राष्ट्रीयसाइबरअपराध रिपोर्टिंग पोर्टल
एनडीपीएस	स्वापक औषधियां और मन प्रभावी पदार्थ
निकनेट	राष्ट्रीयसूचना विज्ञानकेंद्रनेटवर्क
एनपीसी	राष्ट्रीयपुलिस आयोग
ओ.टी.पी	वन टाईम पासवर्ड
पैन	स्थायीखातासंख्या
पैरा	पैराग्राफ
पीसीआर	पुलिसनियंत्रण कक्ष
पीएच.डी.	डॉक्टरेट ऑफ फिलोसिफी
पीएम	प्रधान मंत्री
पॉक्सो	यौन अपराधों से बच्चों का संरक्षण
रिटायर्ड	सेवानिवृत्त
सैक	अनुभाग

एसआईटी	विशेषजाँच दल
एससी	सुप्रीम कोर्ट
एससीसी	सुप्रीम कोर्टके मामले
एसडीसी	राज्यडेटाकेंद्र
एसएचओ	स्टेशन हाऊस अधिकारी
एसओपी	मानक क्रियाशील प्रक्रिया
यूपी	उत्तरप्रदेश
यूटी	केन्द्र शासित प्रदेश
वर्सेज	बनाम
डब्ल्यू.ई.एफ	से प्रभावी
डब्ल्यू.आर.टी	के संबंध में

1. परिचय

क. भारत के विधि आयोग के लिए संदर्भ

1.1 गृह मंत्रालय ने दिनांक 05 जुलाई, 2018 के पत्र के माध्यम से विधि आयोग से "एफआईआर के ऑनलाइन पंजीकरण को सामर्थ्यकारी बनाने के लिए सीआरपीसी की धारा 154 में संशोधन" पर विचार करने का अनुरोध किया गया था। यह विषय दिनांक 6 से 8 जनवरी, 2018 तक बीएसएफ अकादमी, टेकनपुर, मध्य प्रदेश में आयोजित राज्यों के डीजीपी/आईजीपी के एक सम्मेलन में उठाया गया था तथा यह विषय देश के माननीय प्रधानमंत्री जी के संबोधन में भी शामिल था।

ख. वर्ष 2018 तक 21वें विधि आयोग द्वारा किए गए परामर्श

1.2. भारत के 21वें विधि आयोग ने 20 जुलाई 2018 को सभी उच्च न्यायालयों के मुख्य न्यायाधीशों को पत्र लिखकर उनसे अपने अधिकार क्षेत्र में न्यायिक अधिकारियों से इस विषय पर अपनी लिखित राय भेजने का अनुरोध करने को कहा। उपरोक्त के जवाब में, आयोग को उत्साहवर्धक प्रतिक्रिया मिली।ज्यादातर ई-एफआईआर के पंजीकरण के लिए धारा 154 में संशोधन करने के पक्ष में थे। उपरोक्त के अतिरिक्त अधिकतर नेइस योजना से जुड़े गुणों और अवगुणों जैसे आईटी अवसंरचना, पुलिस कर्मियों के साथ-साथ नागरिकों की डिजिटल साक्षरता और शिकायतकर्ता के सत्यापन, अभियुक्त को जानकारी, अन्य विधानों में आवश्यक संशोधन आदि जैसे प्रक्रियात्मक पहलुओं पर प्रकाश डाला। आयोग को 06 अगस्त, 2018 को आयोजित सत्र से भी प्रतिक्रियाएं मिलीं, जिसमें विभिन्न राज्यों के पुलिस अधिकारी शामिल थे।

ग. वर्ष 2023 में 22वें विधि आयोग द्वारा किए गए परामर्श

1.3. आयोग ने इस रिपोर्ट को तैयार करने के लिए निम्नलिखित के साथ परामर्श किया:

1. **पुलिस अनुसंधान और विकास ब्यूरोः** 13 जून, 2023 को बीपीआरएन्डडी के एक प्रतिनिधि के साथ एक बैठक आयोजित की गई थी, जिसमें आयोग को सूचित किया गया था कि बीपीआरएन्डडी पुलिस सुधारों से संबंधित अनुसंधान के लिए उत्तरदायी है और आईपीसी, सीआरपीसी, एनडीपीएस आदि जैसे कानूनों की समीक्षा करता है। बीपीआरएन्डडी ने आयोग को यह भी सूचित किया कि सीआरपीसी, आईपीसी और आईईए सहित आपराधिक कानूनों के प्रावधानों की समीक्षा के लिए एक समिति का गठन किया गया था और समिति ने गृह मंत्रालय को सिफारिशें प्रस्तुत की थीं। उक्त सिफारिशें, ई-एफआईआर को पंजीकृत करने की अनुमति देते हुए, इसके लिए अपराधों की कोई सूची प्रदान नहीं करती हैं। इसके अतिरिक्त, दिनांक 22 मई 2023[1] के पत्राचार के अनुसार, बीपीआरएंडडी ने आयोग को सूचित किया कि आठ राज्यों (दिल्ली, गुजरात, कर्नाटक, मध्य प्रदेश, ओडिशा, राजस्थान, उत्तर प्रदेश और उत्तराखंड) ने एनसीआरबी की सीसीटीएनएस परियोजना के

1. [1] पत्र संख्या जे2/3I/2022-आडी (ई-14061) दिनांक 22 मई 2023 को पुलिस अनुसंधान और विकास ब्यूरो से प्राप्त।

तहत ई-एफआईआर का पंजीकरण कार्यान्वित किया है। इसमें आगे कहा गया है कि जावा और माइक्रोसॉफ्ट दोनों में स्रोत कोड, ई-एफआईआर मॉड्यूल के एसओपी के साथ एनसीआरबी वेबसाइट के नोडल अधिकारी अनुभाग के तहत उपलब्ध कराए गए हैं। चूंकि पुलिस राज्य का एक विषय है, इसलिए राज्यों/केंद्र शासित प्रदेशों को ई-एफआईआर मॉड्यूल डाउनलोड करने और कार्यान्वित करने के लिए सूचित और अनुरोध किया गया था। इसके अलावा, 3 अगस्त, 2023 के अपने पत्र में, बीपीआरएंडडी ने विधि आयोग को सूचित किया कि प्रस्तावित संशोधन गृह मंत्रालय को प्रस्तुत किए गए थे और यह गृह मंत्रालय के विचाराधीन है। बीपीआरएंडडी ने 8 नवंबर, 2019 को गृह मंत्रालय को संबोधित एक पत्र भी प्रस्तुत किया, जिसमें उपर्युक्त कानूनों की समीक्षा के उद्देश्य से उप-समितियों के गठन के बारे में विवरण दिया गया है और सीआरपीसी पर उप-समिति ने सीआरपीसी पर प्रस्तावित संशोधन गृह मंत्रालय को प्रस्तुत किए हैं।

2. **राष्ट्रीय अपराध रिकॉर्ड ब्यूरोः** एनसीआरबी और विधि आयोग के बीच 13 जून, 2023 को एक बैठक आयोजित की गई थी, जिसमें एनसीआरबी ने आयोग को सूचित किया कि सीसीटीएनएस पोर्टल नौ क्षेत्रों (खोई और पाई गई वस्तुओं, किरायेदारों/नौकरों का सत्यापन, लापता व्यक्ति/बच्चों की रिपोर्ट, अज्ञात शव आदि) में ऑनलाइन सेवाएं प्रदान कर रहा है और उन आठ राज्यों (दिल्ली, गुजरात, कर्नाटक, मध्य प्रदेश, ओडिशा, राजस्थान, उत्तर प्रदेश और उत्तराखंड)में वर्तमान स्थिति के बारे में भी सूचित किया जो ई-एफआईआर पंजीकृत कर रहे हैं।

   एनसीआरबी से उपर्युक्त आठ राज्यों जो कि ई-एफआईआर की अनुमति दे रहे हैं, से उक्त के दुरुपयोग के अतिरिक्त वर्तमान में प्रगति डैशबोर्ड के नवीनतम डेटा प्रदान करने के लिए कहा गया था।

   16 अगस्त 2023 को दिए गए अपने जवाब में, एनसीआरबी ने निम्नलिखित बिंदुओं को प्रगणित किया:

क. सभी राज्यों में साइबर-अपराध के कामकाज की प्रभावशीलता की जांचः एनसीआरबी को गृह मंत्रालय द्वारा राष्ट्रीय साइबर अपराध रिपोर्टिंग पोर्टल (एनसीआरपी) के संचालन और अनुरक्षण की जिम्मेदारी सौंपी गई है। नागरिक इस पोर्टल पर किसी भी श्रेणी के साइबर अपराध के संबंध में ऑनलाइन शिकायतें दर्ज कर सकते हैं, जिन्हें उचित कार्रवाई करने के लिए पोर्टल के माध्यम से संबंधित राज्यों या केंद्र शासित प्रदेशों को भेज दिया जाता है। 1 जुलाई, 2023 तक, एनसीआरपी पर 24,74,813 शिकायतें दर्ज की गई हैं और उन सभी को उचित कार्रवाई करने के लिए संबंधित राज्यों/केंद्र शासित प्रदेशों को भेज दिया गया है।

ख. वर्तमान में ई-एफआईआर सुविधा की अनुमति देने वाले राज्यों से दुरुपयोग का डेटाः वर्तमान में ई-एफआईआर सुविधा की अनुमति देने वाले आठ राज्यों (दिल्ली, गुजरात, कर्नाटक, मध्य प्रदेश, ओडिशा, राजस्थान, उत्तर प्रदेश और उत्तराखंड) से दुरुपयोग पर डेटा के संबंध में यह बताया गया था कि एनसीआरबी के पास इस बिंदु पर कोई जानकारी नहीं है और नागरिकों द्वारा इस सुविधा के दुरुपयोग पर कोई भी प्रतिक्रिया केवल संबंधित राज्यों द्वारा दी जा सकती है।

ग. प्रगति डैशबोर्ड के नवीनतम आंकड़े (मई 2023 तक)

1 जून, 2023 तक की स्थिति

I.पुलिस स्टेशनों की कुल संख्या:16,677

मई -2023

• दिसंबर - 21

2. पुलिस स्टेशनों की कुल संख्या जहाँ सी. सी. टी. एन. एस.एप्लीकेशन अभिनियोजित किया गया है:

16,666

3. पुलिस स्टेशनों की संख्या जहाँ नेटवर्किंग कनेक्टिविटी उपलब्ध है:

16,618

1. **प्रो. (डॉ.) एन.के. चक्रवर्ती, कुलपति, पश्चिम बंगाल राष्ट्रीय न्यायिक विज्ञानविश्वविद्यालयः** प्रो. एन.के.चक्रवर्तीके साथवीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से 14 जून, 2023 को परामर्श आयोजित किया गया था, जिसमें उन्होंने इस विषय पर अपने विचार प्रस्तुत किए और सुझाव दिया कि लोगों को न्याय तक पहुंच प्रदान करने के लिए संज्ञेय अपराधों के मामलों में ई-एफआईआर दर्ज करने की अनुमति दी जाए। उन्होंने यह भी सुझाव दिया कि झूठे ई-एफआईआर के पंजीकरण के दुरुपयोग से बचने के लिए आईपीसी की धारा 182 को और अधिक कठोर बनाने सहित सख्त उपाय किए जाने चाहिए।

2. **डॉ. कुमार अस्कंद पांडे, एसोसिएट प्रोफेसर, डॉ. राम मनोहर लोहिया राष्ट्रीय विधि विश्वविद्यालय, लखनऊः** डॉ. के.ए. पांडे ने 14 जून, 2023 को वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से आयोग के समक्ष अपने विचार प्रस्तुत किए और सुझाव दिया कि 3 साल तक की सजा वाले संज्ञेय अपराधों के मामलों में ई-एफआईआर के पंजीकरण की अनुमति दी जा सकती है। डॉ. पांडे ने

दुरुपयोग की संभावना पर भी ध्यान दिया और सुझाव दिया कि इसे रोकने के लिए उपाय किए जाएं।

प्रोफेसरों ने अपनी लिखित तर्क भी साथ में प्रदान कीं, जो इस प्रकार हैं: -

I. इसमें कोई संदेह नहीं हो सकता कि डिजिटल इंडिया का सपना तब तक अधूरा रहेगा जब तक कि सूचना और संचार प्रौद्योगिकी दांडिक न्याय तक पहुँच के लिए आवश्यक नहीं बन जाता। पूरे देश में एक ऐसा समर्पित ऑनलाइन पोर्टलशुरू किया जाना चाहिए, जहां कोई पीड़ित या कोई अन्य व्यक्ति अपराध के बारे में जानकारी साझा करसके। हालांकि, यह अधिकतम तीन साल के कारावास वाले संज्ञेय अपराधों तक ही सीमित होना चाहिए।

II. इसके अतिरिक्त, चूंकि वर्तमान कानून में सूचना देने वाले को ऑनलाइन जानकारी के आधार पर प्रथम इत्तिला रिपोर्ट दर्ज होने के बाद एफआईआर (या तो हस्ताक्षर या अंगूठे का निशान लगाकर) पर हस्ताक्षर करना आवश्यक होता है, इसलिए सूचना देने वाले को हस्ताक्षर करने के लिए संबंधित पुलिस स्टेशन जाना होता है। उपरोक्त को ध्यान में रखते हुए यह विचार है कि ऑनलाइन सुविधा की केवल सीमित उपयोगिता होगी जो बिना समय गंवाए पुलिस के साथ जानकारी साझा कर रही है। इस से यह भी सुनिश्चित होगा कि पुलिस को सौंपी गई ऑनलाइन जानकारी में संज्ञेय अपराध के प्रकटीकरण के सभी मामलों में पुलिस अनिवार्य रूप से प्रथम इत्तिला रिपोर्ट दर्ज करे।

III. ऑनलाइन पोर्टल के माध्यम से पुलिस के साथ जानकारी साझा करते समय पीड़ित/मुखबिर संज्ञेय और गैर-संज्ञेय दोनों अपराधों से संबंधित जानकारी साझा कर सकता है, पुलिस उन सभी मामलों में प्रथम इत्तिला रिपोर्ट दर्ज करने के लिए बाध्य होगी जहां ऑनलाइन जानकारी संज्ञेय अपराध की जानकारी देती है। यह निर्णय लेने में किसी अन्य मानदंड की आवश्यकता नहीं है कि किस ऑनलाइन जानकारी को एफआईआर में परिवर्तित किया जाना चाहिए।

IV. ऑनलाइन सुविधा के दुरुपयोग को रोकने के लिए, यह सुझाव दिया जाता है कि ऐसे मामलों मेंसजा न्यूनतम एक वर्ष से अधिकतम तीन वर्ष का कारावास होना चाहिए और एक लाख रुपये तक के जुर्माने का प्रावधान भी किया जा सकता है।

V. भारत जैसे देश में भारी डिजिटल विभाजन को देखते हुए, यह भी सुझाव दिया जाता है कि एनएलयू/लॉ स्कूलों/महाविद्यालयों/विश्वविद्यालयों में कानूनी सेवा क्लीनिकों को इस ऑनलाइन क्रांति को लाने में उत्प्रेरक और सहायक के रूप में कार्य करना चाहिए।

5. श्री सिद्धार्थ लूथरा, वरिष्ठ अधिवक्ताः

श्री सिद्धार्थ लूथरा ने अपनी प्रतिक्रिया में निम्नलिखित मुद्दों का उल्लेख कियाः -

I. चूंकि संज्ञेय मामलों के लिए प्रथम इत्तिला रिपोर्ट अनिवार्य रूप से दर्ज की जानी चाहिए, यदि किसी बेगुनाह व्यक्ति के विरुद्ध दर्ज की जाती है, तो उसको मुकदमे से बचने की बहुत कम संभावना होगी एवंउसे गिरफ्तारी, जांच और संभवतः मुकदमे का सामना करना पड़ेगा जहां वह अपनी बेगुनाही साबित करना चाहता है।

II. ई-एफआईआर का पंजीकरण आकर्षक प्रतीत होता है लेकिन इसमें अनाम शिकायतों सहित मौखिक और लिखित जानकारी शामिल होगी। यदि एफआईआर दर्ज की जाती है और जांच

होती है, तो यह व्यक्ति की स्वतंत्रता को प्रभावित कर सकता है, क्योंकि भारत में (पुलिस) प्रथा आम तौर पर गिरफ्तार करने की है। और माननीय सर्वोच्च न्यायालय के कई फैसलों के बावजूद, गिरफ्तारी भारत में सीबीआई को छोडकर एक सन्नियम है। अरनेश कुमार बनाम बिहार राज्य[2] के मामले में दिए गए निर्देशों के अनुसार 7 साल से अधिक की सजा वाले अपराधों में अपवंचित किया जा सकता है।

III. आम लोगों से संबंधित एक अन्य कठिनाई है जो अपराधों के घटकों से अनजान हैं और इसलिए संज्ञेय अपराधों को इंगित करने या विभिन्न प्रकार के अपराधों के बीच अंतर को समझने में सक्षम न हो सकें।

IV. एफआईआर दर्ज करने के लिए अपनाई जाने वाली प्रक्रिया के संबंध में अन्य देशों की तुलना में, उन्होंने सुझाव दिया कि हालांकि कुछ क्षेत्राधिकार निर्दिष्ट अपराधों के संबंध में ई-शिकायतों को दर्ज करने की अनुमति देते हैं, हमें सिविल लॉ वाले देशों और निर्णयज विधि वाले देशों की दांडिक न्याय प्रणाली के बीच अंतर को ध्यान में रखना चाहिए। सिविल लॉ वाले देश एक जांच और अभियोजन प्रणाली का पालन करते हैं, जबकि यह निर्णयज विधि वाले देशों में प्रतिकूल है। निर्दोषिता की उपधारणा का अनुमान निर्णयज विधि न्यायशास्त्र का एक महत्वपूर्ण हिस्सा है और एक एफआईआर किसी व्यक्ति को आरोपी के रूप में नहीं, बल्कि केवल एक संदिग्ध के रूप में मानने का आधार है।

V. आयोग को अपने सुझावों में, श्री. लूथरा ने सुझाव दिया कि चूंकि (सर्वप्रथम) यह निर्धारित करने की शक्ति कि कोई संज्ञेय या गैर-संज्ञेय अपराध हुआ है अथवा नहीं, इस पर निर्णय लेने का अधिकार पुलिस के पास निहित है इसलिएकेस डायरी में अपराध को इलेक्ट्रॉनिक रूप से दर्ज करने का प्रावधान शुरू करने के लिए संहिता में संशोधन करना उचित होगा।केवल यदि समयबद्ध जांच में या शिकायत/सूचना को पढ़ने पर कोई संज्ञेय अपराध पाया जाता है तो ही एफआईआर के रिकॉर्डिंग के लिए रखी गई पुस्तक में एफआईआर की जानी चाहिए और औपचारिक जांच शुरु होनी चाहिए। इससे यह सुनिश्चित होगा कि दुर्भाग्य से भी प्रथम इत्तिला रिपोर्ट दर्ज करने के चरण में, जो कि जांच शुरु करने के लिए एक महत्वपूर्ण बिंदु है, किसी भी प्रकार की कोई गलती नहीं हो।

6. श्री आशुतोष पांडे, आईपीएस, एडीजी राज्य एसआईटी, उत्तर प्रदेशः

विधि आयोग ने श्री आशुतोष पांडे से निम्नलिखित बिंदुओं के संबंध में मूल्यवान सुझाव प्राप्त किए, जिन पर उन्होंने निम्नलिखित टिप्पणियां प्रस्तुत कीः -

I. उत्तर प्रदेश राज्य में ई-एफआईआर के पंजीकरण की वर्तमान स्थिति और कार्यान्वयन पर, उन्होंने सीसीटीएनएस ऐप और यूपीकॉप ऐप के कामकाज के बारे में जानकारी दी।

II. ई-एफआईआर के पंजीकरण की स्थिति और इसके दुरुपयोग के बारे में बताते हुए उन्होंने बताया कि उत्तर प्रदेश में प्रत्येक वर्ष लगभग एक लाख ई-एफआईआर पंजीकृत होते हैं और झूठे आरोप पत्रों और अंतिम रिपोर्टों का पृथक्करण नहीं किया जा रहा है। इसके अलावा, उन्होंने उल्लेख किया कि चूंकि सामान्य एफआईआर और ई-एफआईआर के बीच कोई अंतर नहीं है, इसलिए जांच के दौरान कोई पूर्वाग्रह नहीं है। इसके अलावा, ऑनलाइन दर्ज किए गए मामलों की अधिकतम संख्या मुख्य रूप से साइबर धोखाधड़ी, वाहन चोरी, चोरी और सेंधमारी के हैं।

[2] (2014) 8 SCC 273

III. मुख्य रूप से संज्ञेय अपराध जिनके लिए अधिकतम सजा 3 साल तक की कारावास है यथामहिलाओं के खिलाफ अपराध जैसे यौन उत्पीड़न, दहेज संबंधी अपराध आदि को अपराधों की अधिक श्रेणी के मामलों को ई-एफआईआर के माध्यम से पंजीकृत करने के मुद्दे के संबंध में, उन्होंने सकारात्मक लेकिन सावधानी के साथ जवाब दिया कि यदि उन मामलों में इसकी अनुमति दी जाती है जहां आरोपी ज्ञात है, तो यह झूठे पंजीकरण द्वारा घोर दुरुपयोग का कारण बनेगा, क्योंकि किसी को फंसाने से जनता, मीडिया और राजनीतिक नेताओं द्वारा शोर मचाया जाएगा। इसका उपयोग बलात्कार और अन्य गंभीर अपराधों की पीड़ितों के खिलाफ क्रॉस एफआईआर और नकली एफआईआर दर्ज करने के लिए किया जा सकता है ताकि समझौता किया जा सके।

IV. इस ऑनलाइन प्रणाली को अपनाने और उपयोग करने में आने वाली चुनौतियों और इसके दुरुपयोग को रोकने के लिए उठाए गए कदमों के संबंध में, उन्होंने बताया कि दिल्ली-एनसीआर क्षेत्र के संबंध में पुलिस चुनौतियां मुख्य रूप से अधिकार क्षेत्र के संबंध में थीं जिनमें अधिकतर संख्या वाहन चोरी की फर्जी घटनाओं आदि से संबंधित थीं। उनके द्वारा एक अन्य चुनौती का उल्लेख किया गया जिसमेंई-एफआईआर को रूट करते समय किसी भी विसंगतियों की जांच करने के लिए लखनऊ में मुख्यालय वाले ई-थाना में संबंधित कर्मियों को प्रशिक्षित करना था।

V. डिजिटल रिपोर्टिंग प्रक्रिया में डेटा सुरक्षा और गोपनीयता सुनिश्चित करने के लिए किए जा रहे उपायों के बारे में उन्होंने आयोग को सूचित किया कि एनआईसी द्वारा डेटा सुरक्षा संबंधी सरोकारों का ध्यान रखा जा रहा है।

VI. उन्होंने आगे कहा कि ई-एफआईआर के पंजीकरण की शुरुआत से पाए जाने वाले लाभों को पुलिस बल और जनता के लिए विभाजित किया जा सकता है। उन्होंने बताया कि जनता के लिए, लाभ बहुत अधिक हैं क्योंकि यह प्रक्रिया उन्हें पुलिस स्टेशन में सभी परेशानियों से बचाती है जो अंततः उनका कीमती समय बचाती है। इसके अलावा, विशेष रूप से चोरी के वाहनों के मामलों में जल्दी और समय पर प्रथम इत्तिला रिपोर्ट दर्ज करने से बीमा दावे प्राप्त करने और वाहनों की वसूली में मदद मिलती है। पुलिस के संबंध में, इसने पुलिस स्टेशन में भीड़ को कम करने में मदद की और शिकायतकर्ता अपनी शिकायतों की समय पर स्थिति ऑनलाइन भी देख सकते हैं।

VII. ई-एफआईआर के पंजीकरण के दायरे को और बेहतर बनाने और विस्तारित करने के लिए भविष्य की किसी भी योजना का प्रस्ताव करते हुए उन्होंने सुझाव दिया कि क्या इससे निपटने के लिए पर्याप्त बुनियादी ढांचा और कार्यबल है, उन्होंने सुझाव दिया कि प्राप्त प्रतिक्रिया और प्रौद्योगिकी में सुधार के आधार पर लोगों की आकांक्षाओं और अपेक्षाओं को पूरा करने के लिए सॉफ्टवेयर को नियमित रूप से अद्यतन और सुधार की आवश्यकता है।

VIII. ई-एफआईआर दाखिल करने के लिए सुविधा के दुरुपयोग की संभावना पर, उन्होंने सुझाव दिया कि सॉफ्टवेयर में विभिन्न प्रावधान करके दुरुपयोग को रोका जा सकता है, लेकिन जनता द्वारा इसके लाभों की अत्यधिक सराहना की जाती है और यह दांडिक न्याय प्रणाली के सुचारू और प्रभावी संचालन के लिए समय की आवश्यकता है।

7. श्री अनीश गुप्ता, आईआरएसः

श्री अनीश गुप्ता, आईआरएस ने ई-एफआईआर पंजीकरण की शुरुआत के संबंध में आर्थिक अपराधों से संबंधित मुद्दों पर जोर दिया। उन्होंने इस तथ्य पर जोर दिया कि आर्थिक अपराधों को एक अलग आधार पर माना जाता है और इसे चोरी, चोरी हुए दस्तावेजों या वैवाहिक विवादों जैसे अन्य अपराधों

के बराबर नहीं माना जा सकता है। इसके अलावा, एक आर्थिक अपराध की उत्पत्ति के साथ-साथ इसका प्रभाव दूर-दूर तक होता है, और यह केवल विशिष्ट व्यक्ति या समूह तक ही सीमित नहीं है और एनसीआरबी, गृह मंत्रालय, भारत सरकार द्वारा गिने गए कई आर्थिक अपराध विशेष कानूनों द्वारा शासित होते हैं, जिनमें अनिवार्य रूप से संबंधित मंच के समक्ष प्रथम इत्तिला रिपोर्ट/शिकायत दर्ज करने की प्रक्रिया शामिल होती है। इसके अलावा, दंड प्रक्रिया संहिता, 1973 की धारा 4 के साथ पठित धारा 5 में कहा गया है कि विशेष विधानों के प्रावधान दंड प्रक्रिया संहिता, 1973 के सामान्य प्रावधानों पर प्रबल होंगे और इसलिए, वे दंड प्रक्रिया संहिता की धारा 154 द्वारा शासित नहीं हैं। वास्तव में, इनमें से कई विशेष अधिनियमों में, एफ.आई.आर को विभिन्न रूपों से जाना जाता है और यह अध्ययन के फोकस क्षेत्र से बाहर हो सकता है।

उन्होंने सुझाव दिया कि विभिन्न कारणों से आर्थिक अपराधों के लिए ई-एफआईआर दर्ज करने की अनुमति देना संभव नहीं हो सकता है, जिनमें से कुछ निम्नलिखित हैं: -

क. आर्थिक अपराध वाणिज्यिक प्रकृति के होने के कारण इनमें अनिवार्य रूप से प्रारंभिक जांच की आवश्यकता होती है, ताकि प्रथम इत्तिला रिपोर्ट/शिकायत यथासंभव व्यापक हो सके, ताकि न्यायिक मंचों की जांच का सामना किया जा सके, जैसा कि माननीय सर्वोच्च न्यायालय द्वारा ललिता कुमारी बनाम उत्तर प्रदेश सरकार एवं अन्य[3] के ऐतिहासिक फैसले में पुष्टि की गई थी।

ख. आर्थिक अपराधों में शामिल अभियुक्त अक्सर प्रभावशाली होते हैं, जिनका प्रतिनिधित्व प्रतिष्ठित वकीलों द्वारा किया जाता है, जिससे यह महत्वपूर्ण हो जाता है कि शिकायत ठोस, सटीक और कानूनी रूप से सटीक हो। इन अनूठी विशेषताओं को ई-एफआईआर में शामिल करना मुश्किल हो सकता है।

ग. उन्होंने दिल्ली उच्च न्यायालय के तेजिंन्दर सिंह एवं अन्य बनाम भारत संघ[4] के एक मामलेका भी उल्लेख किया। जिसमें, न्यायिक मंचों ने, सामान्य रूप से, सभी अपराधों के लिए ई-एफआईआर के पंजीकरण के दायरे को बढ़ाने का विरोध किया है।

घ. उपर्युक्त बिंदुओं और कानूनी के साथ-साथ व्यावहारिक बाधाओं के आधार पर, उन्होंने कहा कि किसी भी आर्थिक अपराध के लिए ई-एफआईआर का पंजीकरण शुरू नहीं किया जा सकता है, क्योंकि यह प्रतिरक्षा और अभियोजन दोनों के लिए हानिकारक होगा।

8. श्री एम. नागेश्वर राव, आईपीएस (सेवानिवृत्त) पूर्व निदेशक, सीबीआईः

श्री एम. नागेश्वर राव आईपीएस (सेवानिवृत्त) पूर्व निदेशक, सीबीआई ने सबसे पहले इस मुद्दे के समाजशास्त्रीय संदर्भ पर जोर दिया कि प्रथम इत्तिला रिपोर्ट के ऑनलाइन पंजीकरण की मांग वास्तव में अकेले नागरिकों का तत्काल पुलिस के हस्तक्षेप के लिए एक आरता नादम (उपयोगी सुविधा) है, क्योंकि पीड़ित के पास कोई पारिवारिक या समुदाय के स्तर से सहायता अथवा सहयोग नहीं रहता है, और अक्सर, प्रथम इत्तिला रिपोर्ट दर्ज करने के लिए पास के पुलिस स्टेशन तक जाने वाला भी कोई नहीं होता है। दूसरा, सैद्धांतिक रूप से ई-एफआईआर के पंजीकरण के प्रस्ताव का

[3] (2014) 2 एससीसी1

[4] तेजीन्दर सिंह एवं अन्य बनाम भारत संघ 2019 एससीसी ऑनलाईन दिल्ली 12143

समर्थन करते हुए, अन्य बातों के साथ-साथ, उन्होंने निम्नलिखित सरोकारों को उठाया, जो उनके अनुसार, विचार करने की आवश्यकता हैः

I. ई-एफआईआर के पंजीकरण से पंजीकृत एफआईआर (आपराधिक मामलों) की संख्या में वृद्धि होगी और अपराधों के पंजीकरण (एफआईआर) में वृद्धि हमेशा एक राजनीतिक रूप से संवेदनशील मामला होता है।

II. कभी-कभी, गुस्से में स्थिति के कारण यदि पुलिस द्वारा त्वरित कार्रवाई नहीं की जाती है तो छोटे अपराध, गैर-संज्ञेय अपराध या गैर-आपराधिक प्रकृति के मुद्दे भी अतिशयोक्तिपूर्ण तरीके से बढा चढा कर पेश किए जाते हैं और गंभीर अपराधों के रूप में रिपोर्ट किए जाते हैं। इस से मीडिया या सार्वजनिक आक्रोश उत्तपन्न होने की संभावना निरंतर बनी रहती है।

III. उन्होंने आगे सुझाव दिया कि ललिता कुमारी[5] के मामले पर निर्णय में माननीय उच्चतम न्यायालय द्वारा दिए गए निर्देशों का इस तरह से पालन किया जा सकता है कि इलेक्ट्रॉनिक माध्यमों से प्राप्त सूचना को उस सूचक सूची में जोड़ा जा सके (जैसा कि उक्त निर्णय के पैरा 111 (vi) में दिया गया है) ताकि ई-एफआईआर के पंजीकरण के बारे में सरोकारों को दूर किया जा सके। तदनुसार, उन्होंने आगे सुझाव दिया कि इलेक्ट्रॉनिक मोड के माध्यम से सूचना प्राप्त होने पर प्रारंभिक जांच रिपोर्ट के पंजीकरण के लिए सीआरपीसी की धारा 154 के तहत एक उप-धारा डाली जा सकती है, जिसकी जांच एक पुलिस अधिकारी द्वारा 24 घंटे के भीतर की जानी चाहिए।

[5] (2014)2 एससीसी 1

2. एफआईआर से संबंधित प्रावधान

क. *दंड प्रक्रिया संहिता, 1973 की धारा 154 का परिचय।*

2.1. दंड प्रक्रिया संहिता की धारा 154 यह विनियमित करती है कि संज्ञेय अपराध के बारे में पहली जानकारी कैसे दर्ज की जाती है। वर्तमान ढांचा वर्षों की अवधि में कई आयोगों, समितियों और न्यायालयों द्वारा किए गए व्यापक कार्य का परिणाम है।

2.2 इत्तिला देने वाले के दृष्टिकोण से प्रथम इत्तिला रिपोर्ट का मुख्य उद्देश्य आपराधिक कानून के बारे में समावेदन देना है और जांच अधिकारियों के दृष्टिकोण से, कथित आपराधिक गतिविधि के बारे में जानकारी प्राप्त करना है ताकि दोषी पक्ष का पता लगाने और उसके खिलाफ मामला दर्ज करने के लिए उपयुक्त कदम उठाए जा सकें। प्रथम इत्तिला रिपोर्ट ठोस साक्ष्य का गठन नहीं करती है, हालांकि घटना के बारे में शुरुआती जानकारी देने के रूप में इसके महत्व पर संदेह नहीं किया जा सकता है। हालाँकि, इसका उपयोग केवल भारतीय साक्ष्य अधिनियम की धारा 157 के तहत अपने निर्माता की पुष्टि करने या भारतीय साक्ष्य अधिनियम की धारा 145 के तहत उसका खंडन करने के उद्देश्य से पिछले बयान के रूप में किया जा सकता है। इसका उपयोगअन्य गवाहों की संपुष्टि या खंडन करने के उद्देश्य से नहीं किया जा सकता है।[6] इसमें सही जानकारी होनी चाहिए और इसके माध्यम से संज्ञेय अपराध का खुलासा किया जाना चाहिए।[7]

2.3. दंड प्रक्रिया संहिता के पूर्ववर्ती अधिनियमों में विद्यमान धारा और तत्संवादी उपबंधों पर 5 न्यायाधीशों की संविधान पीठ द्वारा ललिता कुमारी बनाम उत्तर प्रदेश सरकार और अन्य के मामले में विस्तार से चर्चा की गई है।[8] इस पर सुप्रीम कोर्ट ने कहाः

> *"30. 1973 की वर्तमान संहिता की पूर्वगामी 1898 की संहिता है जिसमें जाँच करने के लिए पुलिस की शक्तियों और प्रक्रिया में सारवान परिवर्तन किए गए थे। एक संज्ञेय अपराध के संबंध में प्रथम इत्तिला रिपोर्ट को कम करने के लिएपुलिस की प्रारंभिक शक्तियों को मजिस्ट्रेट के आदेश के बिना एक संज्ञेय अपराध की जांच करने के लिए एक पुलिस स्टेशन के प्रभारी अधिकारी की शक्ति से बदल दिया गया थाचाहे वह सूचना मौखिक रूप से या लिखित रूप में प्राप्त हुई हो। बाद में उसे लिखित रूप में और ऐसी प्रथम इत्तिला रिपोर्टदर्ज करने के लिए राज्य सरकार द्वारा अलग से निर्धारित पुस्तक में दर्ज किया गया हो।*
>
> *31. 1898 की संहिता के माध्यम से जो एक महत्वपूर्ण परिवर्तन हुआ, वह धारा 154 के प्रतिस्थापन के संबंध में था, अर्थात, संज्ञेय अपराध के घटित होने के संबंध में प्रथम इत्तिला रिपोर्ट को विशेष पुस्तक में दर्ज करने की आवश्यकता को कार्यान्वित करने वाला प्रावधान धारा 156, यानी कि वह प्रावधान जो कि पुलिस अधिकारी को संज्ञेय अपराध की जांच करने का अधिकार प्रदान करता था। इस प्रकार, प्रावधानों को कार्यान्वित करने का उद्देश्य स्पष्ट था जो यह सुनिश्चित करता था कि प्रथम इत्तिला रिपोर्ट की रिकॉर्डिंग पुलिस द्वारा किसी भी*

[6] शेख हासिब बनाम बिहार राज्य (1912)4 एससीसी 773.

[7] ललिता कुमारी बनाम उत्तर प्रदेश सरकार (2014) 2 एससीसी 1।

[8] पूर्वोक्त

जांच का शुरुआती बिंदु होनी चाहिए।जांच की समीचीनता के हित में, चूंकि जांच शुरू करने के लिए मजिस्ट्रेट से अनुमति प्राप्त करने की कोई संरक्षा नहीं थी, इसलिए इत्तीला देने वाले के हस्ताक्षर/मुहर के साथ उनकी पुस्तकों में प्रथम इत्तिला रिपोर्ट दर्ज करने की उक्त प्रक्रिया पुलिस द्वारा जांच शक्तियों के अत्यधिक, दुर्भावनापूर्ण और अवैध प्रयोग के खिलाफ "अत्यंत मूल्यवान" सुरक्षा प्रदान करेगी।

ख. दंड प्रक्रिया संहिता के तहत एफआईआर के प्रावधान का विकास।

2.4. संहिता की धारा 154 की ऐतिहासिक पृष्ठभूमि 1861 से 2013 तक निम्नलिखित चरणों का प्रतिनिधित्व करती प्रतीत होती है:

1. दंड प्रक्रिया संहिता, 1861

"139. शिकायत आदि का लिखित रूप में होना - पुलिस स्टेशन के प्रभारी अधिकारी को प्रत्येक शिकायत या सूचना को लिखित रूप में दी जाएगी और उसका सार राज्य सरकारद्वारा निर्धारित ऐसे प्रपत्र में अधिकारी द्वारा रखी जाने वाली एक डायरी में दर्ज किया जाएगा।

2. दंड प्रक्रिया संहिता, 1872

"112. लिखित रूप में पुलिस को शिकायत करें। पुलिस चौकी के प्रभारी अधिकारी को दी जाने वाली प्रत्येक शिकायत को लिखित रूप में प्रस्तुत किया जाएगा और इसे बनाने वाले व्यक्ति द्वारा हस्ताक्षरित, सील या चिह्नित किया जाएगा और इसका सार राज्य सरकार द्वारा निर्धारित पुस्तक में ऐसे अधिकारी द्वारा दर्ज किया जाएगा।[9]

3. दंड प्रक्रिया संहिता, 1882

*"154. **सूचना संज्ञेय मामले हैं।** - संज्ञेय अपराध के होने से संबंधित प्रत्येक सूचना यदि किसी पुलिस-स्टेशन के प्रभारी अधिकारी को मौखिक रूप से दी जाती है, तो उसे उसके द्वारा या उसके निर्देश के तहत लिखित में दर्ज किया जाएगा, और सूचना देने वाले के समक्ष पढ़ा जाएगा और ऐसी प्रत्येक जानकारी, चाहे वह लिखित रूप में दी गई हो या लेखबद्ध की गई हो, उसे देने वाले व्यक्ति द्वारा हस्ताक्षरित की जाएगी, और उसका सार उस पुस्तक में दर्ज किया जाएगा जिसे ऐसे प्रपत्र द्वारा रखा जाएगा जो राज्य सरकार इस संबंध में विहित करे।*

4. दंड प्रक्रिया संहिता, 1898

*"154. **सूचना संज्ञेय मामले हैं।** - किसी संज्ञेय अपराध के होने से संबंधित प्रत्येक सूचना, यदि मौखिक रूप से किसी पुलिस-स्टेशन के प्रभारी अधिकारी को दी जाती है, तो उसके द्वारा या उसके निर्देश के तहत लिखित रूप में लेखबद्ध की जाएगी, और सूचना देने वाले के समक्ष पढ़ी जाएगी; और ऐसी प्रत्येक जानकारी, चाहे लिखित रूप में दी गई हो या लिखित रूप में लेखबद्ध किया गया हो, इसे देने वाले व्यक्ति द्वारा हस्ताक्षरित की जाएगी, और उसका सार ऐसे*

[9] दंड प्रक्रिया संहिता (1872 का अधिनियम संख्या X), एस. 112

अधिकारी द्वारा रखे जाने वाली पुस्तक में दर्ज किया जाएगा जो राज्य सरकार इस संबंध में विहित करे।

2.5. स्वतंत्रता के बाद, भारत की संसद ने दंड प्रक्रिया संहिता का पुनर्गठन किया और नए कोड यथा दंड प्रक्रिया संहिता, 1973 की धारा 154 के तहत एफआईआर के पंजीकरण से संबंधित प्रावधान के लिए प्रदान किया, जिसे आपराधिक कानून (संशोधन) अधिनियम, 2013 द्वारा आगे संशोधित किया गया था जो कि निम्नानुसार हैः

5. दंड प्रक्रिया संहिता, 1973

*"154. **संज्ञेय मामलों में सूचना-**(1) संज्ञेय अपराध करने से संबंधित प्रत्येक सूचना, यदि किसी पुलिस थाने के प्रभारी अधिकारी को मौखिक रूप से दी जाती है, तो उसे उसके द्वारा या उसके निर्देश के तहत लिखित रूप में दर्ज किया जाएगा और सूचना देने वाले के समक्ष पढ़ा जाएगा; और ऐसी प्रत्येक जानकारी, चाहे लिखित रूप में दी गई हो या लिखित रूप में दर्ज की गई हो, उसे देने वाले व्यक्ति द्वारा हस्ताक्षरित की जाएगी, और उसका सार ऐसे अधिकारी द्वारा रखे जाने वाली पुस्तक में ऐसे प्रपत्र में दर्ज किया जाएगा जो राज्य सरकार इस संबंध में विहित करे।*

परतुं यदि सूचना उस महिला द्वारा दी गई है जिसके खिलाफ भारतीय दंड संहिता (1860 का 45) की धारा 326क, धारा 326ख, धारा 354, धारा 354क, धारा 354ख, धारा 354ग, धारा 354घ, धारा 376, धारा 376क, धारा 376ख, धारा 376ग, धारा 376घ, धारा 376ङ या धारा 509 के तहत अपराध करने या प्रयास करने का आरोप है, तो ऐसी जानकारी किसी महिला पुलिस अधिकारी या किसी महिला अधिकारी द्वारा ही दर्ज की जाएगी:

परंतु और यह कि -

(क) उस स्थिति में जब किसी अस्थायी या स्थायी रूप से मानसिक या शारीरिक रूप से अक्षम व्यक्ति के खिलाफ भारतीय दंड संहिता (1860 का 45) के तहत धारा 354, धारा 354क, धारा 354ख, धारा 354ग, धारा 354घ, धारा 376, धारा 376क, धारा 376ख, धारा 376ग, धारा 376घ, धारा 376ङ या धारा 509 के तहत अपराध किया गया हो या प्रयास किया गया हो तो ऐसी जानकारी पुलिस अधिकारी द्वारा मामलानुसार ऐसे अपराध की रिपोर्ट करने वाले व्यक्ति के निवास पर या ऐसे व्यक्ति की पसंद के एक सुविधाजनक स्थान परदुभाषिया या विशेष शिक्षक की उपस्थिति में दर्ज की जाएगी;

(ख) ऐसी जानकारी की रिकॉर्डिंग की वीडियोग्राफी की जाएगी;

(ग) पुलिस अधिकारी यथाशीघ्र धारा 164 की उपधारा (5क) के खंड (क) के तहत न्यायिक मजिस्ट्रेट द्वारा व्यक्ति का बयान दर्ज करवाया जाएगा।

(2) उप-धारा (1) के तहत दर्ज की गई जानकारी की एक प्रति सूचना देने वाले को तुरंत निःशुल्क दी जाएगी।

(3) उपधारा (1) में निर्दिष्ट सूचना को अभिलिखित करने के लिए किसी पुलिस थाने के प्रभारी अधिकारी की ओर से इनकार किए जाने से व्यथित कोई व्यक्ति ऐसी सूचना का सार लिखित रूप में और डाक द्वारा संबंधित पुलिस अधीक्षक को भेज सकता है, जिसका यदि समाधान हो जाता है कि ऐसी सूचना से संज्ञेय अपराध होने का खुलासा होता है तो वह या तो स्वयं मामले की जाँच करेगा या इस संहिता द्वारा उपबंधित रीति से अपने अधीनस्थ किसी पुलिस अधिकारी द्वारा जाँच

किए जाने का निर्देश देगा और ऐसे अधिकारी को उस अपराध के संबंध में पुलिस थाने के प्रभारी अधिकारी की सभी शक्तियाँ होंगी।

ग. धारा 154 के लाभ और महत्व

2.6. एफआईआर को पंजीकृत करने की बाध्यता के अंतर्निहित लाभ हैं और इस पर ललिता कुमारी[10] के मामले में निर्णय के पैरा 88 में निम्नानुसार जोर दिया गया हैः

> *(क) यह पीड़ित के लिए 'न्याय तक पहुँच' की दिशा में पहला कदम है। (ख) यह विधि सम्मत शासन को उतना ही बनाए रखता है जितना कि आम व्यक्ति राज्य की जानकारी में संज्ञेय अपराध को सामने लाता है।*
> *(ग) यह त्वरित जाँच और कभी-कभी अपराध की रोकथाम की सुविधा भी प्रदान करता है। दोनों ही मामलों में, यह केवल विधि सम्मत शासन को प्रभावशील बनाता है।*
> *(घ) यह आपराधिक मामलों में छल साधन की संभावना को कम करता है और 'पूर्व-दिनांकित' प्रथम इत्तिला रिपोर्ट या जानबूझकर विलंबित प्रथम इत्तिला रिपोर्ट की घटनाओं को कम करता है।*

घ. एफआईआर के संबंध में संहिता में कुछ अन्य प्रावधान

2.7. एफआईआर से संबंधित कुछ प्रावधानों पर एक नज़र डालना आवश्यक है, दंड प्रक्रिया संहिता, 1973 की धारा 2 के तहत दी गई परिभाषाओं को निम्नानुसार प्रगणन किया गया हैः

> *"संज्ञेय अपराध" का अर्थ है एक अपराध जिसके लिए और "संज्ञेय मामले" का अर्थ है एक ऐसा मामला जिसमें, एक पुलिस अधिकारी, पहली अनुसूची के अनुसार या फिलहाल कार्यान्वित किसी अन्य कानून के तहत, वारंट के बिना गिरफ्तार कर सकता है।*[11]

> *"गैर-संज्ञेय अपराध का मतलब एक ऐसा अपराध है जिसके लिए, और "गैर-संज्ञेय मामले" का मतलब एक ऐसा मामला है जिसमें एक पुलिस अधिकारी के पास बिना वारंट के गिरफ्तार करने का कोई अधिकार नहीं है।"*[12]

[10] 2014) 2 एससीसी 1
[11] दंड प्रक्रिया संहिता
[12] पूर्वोक्त 2(1)

2.8 संहिता की धारा 155 गैर-संज्ञेय मामलों और ऐसे मामलों की जांच के बारे में जानकारी से संबंधित है जो निम्नानुसार हैः

155. गैर-संज्ञेय मामलों और ऐसे मामलों के अन्वेषण के बारे में जानकारी-

(1) जब किसी पुलिस स्टेशन के प्रभारी अधिकारी को किसी गैर-संज्ञेय अपराध के होने की जानकारी ऐसे स्टेशन की सीमा के भीतर दी जाती है, तो वह इसकी सूचना को राज्य सरकार द्वारा विहित पुस्तक में जानकारी का सार दर्ज करेगा या दर्ज करवाएगा और इत्तिला देने वाले को मजिस्ट्रेट के पास भेज सकता है।

(2) कोई भी पुलिस अधिकारी मजिस्ट्रेट के आदेश के बिना किसी गैर-संज्ञेय मामले की जांच नहीं करेगा, जिसे ऐसे मामले की सुनवाई करने या मामले/या मुकदमे को करने की शक्ति है।

(3) ऐसा आदेश प्राप्त करने वाला कोई भी पुलिस अधिकारी जाँच के संबंध में (वारंट के बिना गिरफ्तार करने की शक्ति को छोड़कर) उन्हीं शक्तियों का प्रयोग कर सकता है जैसे कि पुलिस स्टेशन का प्रभारी अधिकारी संज्ञेय मामले में कर सकता है।

(4) जहां कोई मामला दो या दो से अधिक अपराधों से संबंधित है, जिनमें से कम से कम एक संज्ञेय अपराध है, तो मामले को संज्ञेय मामला माना जाएगा, चाहे दूसरा मामला गैर-संज्ञेय हो।

3. ई-एफआईआर के पंजीकरण की मांग

क. विभिन्न आयोगों एवं समितियों की रिपोर्टें

3.1. लोक प्रशासन प्रणाली में सुधार के लिए एक विस्तृत खाका तैयार करने के लिए 2005 में दूसरे प्रशासनिक सुधार आयोग का गठन किया गया था। आयोग ने अन्य बातों के साथ-साथ ई-गवर्नेंस को बढ़ावा देने के संबंध में भी अपने सुझाव दिए। आयोग का विचार था कि 2020 तक सभी स्तरों पर नागरिक-सरकार के बीच संपर्क को ई-गवर्नेंस मोड में बदलने के अंतिम उद्देश्य के साथ भारत सरकार द्वारा एक स्पष्ट रुप रेखा तैयार की जानी चाहिए। आयोग ने ई-गवर्नेंस की प्रसुविधाओं को भी रेखांकित किया। इसकी 11वीं रिपोर्ट[13] का पैरा 2.5 इस प्रकार हैः

2.5 ई-गवर्नेंस के लाभ

2.5.1 अंत में, ई-गवर्नेंस का लक्ष्य शासन में सुधार लाना है, जो सूचना और संचार प्रौद्योगिकी के रचनात्मक उपयोग द्वारा इसे सुकर बनाता है। यह उम्मीद की जाती है कि इससे निम्नलिखित परिणाम होंगेः

i. नागरिकों के लिए सूचना और गुणवत्तापूर्ण सेवाओं तक बेहतर पहुंचः सूचना और संचार प्रौद्योगिकी शासन के विभिन्न पहलुओं पर वास्तविक समय पर और विश्वसनीय जानकारी उपलब्ध कराएगी। प्रारंभिक चरण में शासन के सरल पहलुओं जैसे प्रपत्र, कानून, नियम, प्रक्रिया आदि के संबंध में जानकारी उपलब्ध कराई जाएगी। बाद में विस्तृत रिपोर्ट (प्रदर्शन रिपोर्ट सहित) सार्वजनिक डेटाबेस, निर्णय लेने की प्रक्रियाओं आदि सहित विस्तृत जानकारी देने वाली सेवाओं को इसमें जोडा जाएगा। सेवाओं के संबंध में, बैक-एंड प्रक्रियाओं के स्वचालन द्वारा समर्थित सार्वजनिक सेवाओं की ऑनलाइन और एक ही स्थान पर सभी सुविधाओं तक पहुंच के परिणामस्वरूप समय, प्रयास और धन की बचत होगी। ई-गवर्नेंस का अंतिम उद्देश्य जीवन-चक्र दृष्टिकोण अपनाकर नागरिकों तक पहुंच स्थापित करना है, यानी नागरिकों को सार्वजनिक सेवाएं प्रदान करना, जिनकी जन्म से मृत्यु तक किसी आम नागरिक को आवश्यकता होती है।

II. सरकार में सरलता, दक्षता और जवाबदेही: विस्तृत कार्य प्रक्रिया पुनर्रचना के साथ शासन में सूचना एवं संचार प्रौद्योगिकी के अनुप्रयोग से जटिल प्रक्रियाओं का सरलीकरण होगा, अनावश्यक प्रक्रियाओं से छुटकारा मिलेगा, संरचनाओं में सरलीकरण होगा और प्रतिमानों और विनियमों में बदलाव आएगा। अंतिम परिणाम सरकार के कामकाज का सरलीकरण होगा, निर्णय लेने की क्षमताओं में वृद्धि होगी और सम्पूर्ण सरकार की दक्षता में वृद्धि होगी - ये सभी एक अधिक जवाबदेह सरकारी मशीनरी के समग्र वातावरण में योगदान देंगे। इसके परिणामस्वरूप, सभी क्षेत्रों में उत्पादकता और दक्षता में वृद्धि होगी।

[13] दूसरा प्रशासनिक सुधार आयोग, भारत सरकार, 11वीं "ई-गवर्नेंस को बढ़ावा देने पर रिपोर्ट: आगे बढ़ने का स्मार्ट तरीका" 12 (प्रशासनिक सुधार और लोक शिकायत विभाग, दिसंबर 2008)।

III. शासन की विस्तारित पहुंच: संचार प्रौद्योगिकी के तेजी से विकास और शासन में इसे अपनाने से सरकारी मशीनरी को नागरिकों के दरवाजे तक लाने में मदद मिलेगी। टेलीफोन नेटवर्क का विस्तार, मोबाइल टेलीफोन में तेजी से प्रगति, इंटरनेट का प्रसार और अन्य संचार बुनियादी ढांचे को मजबूत करने से सरकार द्वारा प्रदान की जाने वाली बड़ी संख्या में सेवाओं की डिलीवरी आसान हो जाएगी। सरकार की पहुंच में यह वृद्धि-स्थानिक और जनसांख्यिकीय दोनों-शासन की प्रक्रिया में नागरिकों की बेहतर भागीदारी को भी सक्षम बनाएगी।"

3.2. दूसरे प्रशासनिक सुधार आयोग ने अपनी 12वीं रिपोर्ट[14] में केंद्रीकृत लोक शिकायत निवारण और निगरानी प्रणाली (सीपीग्राम) पर निम्नानुसार एक टिप्पणी की:

"7.5.1 प्रशासनिक सुधार और लोक शिकायत विभाग ने जनता से शिकायतें प्राप्त करने, निवारण करने और निगरानी करने के लिए 2007 में सीपीग्राम लॉन्च किया। सीपीग्राम किसी भी भौगोलिक स्थान से 'ऑनलाइन' शिकायत दर्ज करने की सुविधा प्रदान करता है। यह नागरिकों को अपनी शिकायत पर संबंधित विभागों द्वारा की जा रही कार्रवाई पर ऑनलाइन नजर रखने की सुविधा प्रदान करता है, और डीएआरपीजी को शिकायत की निगरानी करने में भी सक्षम बनाता है। सीपीग्राम एक वेब-सक्षम एप्लिकेशन है और इसे मंत्रालयों/विभागों/संगठनों द्वारा इंटरनेट कनेक्शन और इंटरनेट ब्राउज़र का उपयोग करके पर्सनल कम्प्यूटर के माध्यम से उपयोग किया जा सकता है। नागरिक www.pgportal.nic.in पोर्टल के माध्यम से सरकारी तंत्र तक ऑनलाइन पहुंच सकते हैं। चूंकि विकसित प्रणाली हाल ही में लॉन्च की गई है, इसलिए अन्य मंत्रालयों/विभागों द्वारा इसकी प्रभावकारिता और प्रतिक्रिया का परीक्षण किया जाना बाकी है। हालाँकि, यह प्रणाली एक आधुनिक तकनीक का बेहतरीन उपयोग है।

7.5.2 आयोग का विचार है कि राज्य और जिला स्तर पर एक समान प्रणाली स्थापित की जानी चाहिए क्योंकि विकेन्द्रीकृत प्रणाली से एक ओर बड़ी संख्या में नागरिकों को लाभ होगा और दूसरी ओर क्षेत्रीय कार्यालयों की प्रभावशीलता में सुधार करने में भी मदद मिलेगी। इसी तरह की अवधारणाएँ पहले ही कई राज्यों में आज़माई जा चुकी हैं। उदाहरण के लिएउत्तर प्रदेश में लोकवाणी।"

3.3. इसके अलावा, दूसरे प्रशासनिक सुधार आयोग ने अपनी 5वीं रिपोर्ट[15] में एफआईआर दर्ज करने के संबंध में सिफारिश की और राष्ट्रीय पुलिस आयोग (1980) द्वारा की गई सिफारिशों को निम्नानुसार दोहराया:

"7.5.1.11 ***सिफ़ारिशें:***

ङ. एफआईआर के पंजीकरण को स्थानीय स्तर पर नागरिकों के लिए अनुकूल बनाया जाना चाहिए। जनता तक पुलिस स्टेशनों की पहुंच में सुधार के लिए

[14] दूसरा प्रशासनिक सुधार आयोग, भारत सरकार, नागरिक केंद्रीय प्रशासन पर 12वीं रिपोर्ट" (प्रशासनिक सुधार और लोक शिकायत विभाग, फरवरी 2009)।

[15] द्वितीय प्रशासनिक सुधार आयोग, भारत सरकार। सार्वजनिक व्यवस्था पर "5वीं" रिपोर्ट" 172(प्रशासनिक सुधार और लोक शिकायत विभाग, जून 2007)।

प्रौद्योगिकी का उपयोग किया जाना चाहिए। इस संबंध में कॉल सेंटर और सार्वजनिक कियोस्क स्थापित करना संभावित विकल्प हैं।

च. कदाचार को रोकने, पारदर्शिता सुनिश्चित करने और पुलिस को अधिक नागरिक-अनुकूल बनाने के लिए पुलिस स्टेशनों को सीसीटीवी कैमरों से लैस किया जाना चाहिए। इसे पांच साल की समय सीमा के भीतर सभी पुलिस स्टेशनों में कार्यान्वित किया जा सकता है।

छ. राष्ट्रीय पुलिस आयोग के सुझाव के अनुसार सीआरपीसी में संशोधन किया जाना चाहिए।

ज. पुलिस स्टेशनों के प्रदर्शन का मूल्यांकन सफलतापूर्वक पता लगाए गए और मुकदमा चलाए गए मामलों के आधार पर किया जाना चाहिए, न कि दर्ज मामलों की संख्या के आधार पर। 'मामलों को दबाने' की व्यापक रूप से प्रचलित कदाचार को खत्म करने के लिए यह आवश्यक है।

7.5.1.4 आयोग का मानना है कि चूंकि एफआईआर दर्ज करना दांडिक न्याय प्रणाली में पहला कदम है और जब तक पंजीकरण प्रक्रिया में कमियों को ठीक नहीं किया जाता है, अन्य सुधारों का, विशेषकर बाद के चरणों में, सीमित प्रभाव होगा। इसलिए, एक ऐसी प्रणाली विकसित करनी होगी जिसमें एफआईआर का पंजीकरण पूरी तरह से पारदर्शी हो और एफआईआर दर्ज करने से इनकार करने की घटनाएं समाप्त हो जाएं।

7.5.1.9 जैसा कि राष्ट्रीय पुलिस आयोग (एनपीसी) (1980) ने नोट किया है। एफआईआर में कई अदालती फैसले दिए गए हैं, जो एफआईआर में किसी भी मुख्य तथ्य की चूक को अनुचित महत्व देने की प्रवृत्ति रखते हैं, भले ही ऐसी चूक शिकायतकर्ता की परेशान या भ्रमित मनःस्थिति के कारण हुई हो। परिणामस्वरूप, एनपीसी के अनुसार, अदालतों द्वारा एफआईआर पर लगाए गए अत्यधिक साक्ष्यों के कारण अतिरिक्त विवरण प्राप्त करने के लिए पुलिस अधिकारी एफ आई आर में देरी कर कदाचार करते हैं। इसलिए उपरोक्त स्थिति के समाधान के लिए एनपीसी ने सीआरपीसी की धारा 154 में निम्नलिखित संशोधन करने की सिफारिश की:

• पुलिस को अतिरिक्त विवरण और स्पष्टीकरण प्राप्त करने के लिए इत्तिला देने वाले से पूछताछ करने की अनुमति दी जानी चाहिए;

• यह स्पष्ट किया जाना चाहिए कि एफ आई आर दर्ज करना अनिवार्य है, चाहे कथित अपराध पुलिस स्टेशन के अधिकार क्षेत्र में हुआ हो या नहीं; और

• पुलिस स्टेशन की घट कइ काइयों जैसे पुलिसचौकियों आदि को भी एफ आई आर दर्ज करने की अनुमति दें।''

3.4. भारत के विधि आयोग ने अपनी 239वीं रिपोर्ट[16] जिसका शीर्षक 'प्रभावशाली सार्वजनिक हस्तियों के खिलाफ आपराधिक मामलों की शीघ्र जांच और सुनवाई' (मार्च 2012 में प्रस्तुत) में दांडिक न्याय में तेजी लाने के लिए दो महत्वपूर्ण कदमों का उल्लेख किया है जो इस प्रकार हैं:

"(क) पुलिस स्टेशनों के स्तर पर प्रौद्योगिकी का अभिनियोजन।

(ख) दंड न्यायालयों के बुनियादी ढांचे को मजबूत करना और उसमें सुविधाओं और सुख-सुविधाओं का उन्नयन करना।

इन कदमों को उचित योजना बनाकर चरणबद्ध तरीके से उठाया जाना चाहिए।

[16] भारत का विधि आयोग, "239" प्रभावशाली सार्वजनिक हस्तियों के खिलाफ आपराधिक मामलों की त्वरित जांच और सुनवाई पर रिपोर्ट" 31 (मार्च, 2012)

क. पुलिस स्टेशनों पर प्रौद्योगिकी का अभिनियोजन: *(क) एफआईआर दर्ज करना: यह पाया गया है कि कई लोगों के बरी होने का कारण देरी, समय से पहले जानकारी देना और एफआईआर में घटना के आवश्यक विवरण का अभाव है। पुलिस स्टेशनों में उपलब्ध सभी लैंडलाइनों की अनिवार्य और स्वचालित रिकॉर्डिंग प्रदान करके इस एक कारक को समाप्त किया जा सकता है। पुलिस के प्रतिक्रिया समय को कम करने के लिए क्षेत्र में तैनात पुलिस के सभी गश्ती वाहनों में कॉलर और पुलिस स्टेशन ऑपरेटर के बीच टेलीफोन वार्तालाप के स्वचालित रिले का प्रावधान भी होना चाहिए।संदिग्धों/वाहनों/दस्तावेजों आदि के पूर्ववृत्त को मौके पर और तुरंत जानने के लिए गश्ती वाहनों की पुलिस नेटवर्क से भी कनेक्टिविटी होनी चाहिए।*

एफआईआर कंप्यूटर पर दर्ज की जाएं और उन्हें तुरंत ई-मेल द्वारा मजिस्ट्रेट अदालतों को भेजा जाए। ई-मेल के माध्यम से एफआईआर भेजने की प्रथा को कानूनी मान्यता मिलनी चाहिए। इसी प्रकार, धारा 161 के बयानों को भी कंप्यूटर पर रखा जाना चाहिए और संबंधित न्यायालय की वेबसाइट पर पोस्ट किया जाना चाहिए।

(ख) पुलिस स्टेशन: आधुनिकीकरण:(i) सभी अदालतों के साथ लिंक स्थापित करने के लिए सभी पुलिस स्टेशनों की नेटवर्किंग की जानी चाहिए: (ii) पुलिस स्टेशनों पर डिजिटल वीडियोग्राफी स्थापित की जाएगी। एफआईआर/शिकायत प्राप्त करते समय वीडियोग्राफी अनिवार्य की जाए। इस प्रक्रिया से, मुखबिर का प्रारंभिक संस्करण स्पष्ट हो जाएगा। इसी प्रकार अपराध स्थल के निरीक्षण और भौतिक वस्तुओं की बरामदगी के समय वीडियोग्राफीपर जोर दिया जाना चाहिए। (iii) परिप्रश्न कक्ष: प्रत्येक पुलिस स्टेशन को दो कैमरों द्वारा एक साथ ऑडियो-विज़ुअल रिकॉर्डिंग सुविधाओं के साथ सुरक्षित परिप्रश्न कक्ष प्रदान किए जाने चाहिए, एक कैमरा गवाह या संदिग्ध के चेहरे के क्लोज़-अप पर ध्यान केंद्रित करने वाला और दूसरा एक विस्तृत ऐंगलपिक्चर उपलब्ध करवाएगा। यह दिखाने के लिए कि गवाह या संदिग्ध के बयान को प्रभावित करने के लिए कोई जबरदस्ती नहीं की गई है। कानून के अनुसार, सभी संदिग्धों और गवाहों के बयान ऐसे खिड़की रहित परिप्रश्न कक्षों में दर्ज किए जाने चाहिए, जिनकी दो दीवारों पर दर्पण लगे हों। सुरक्षित पूछताछ कक्षों में जांचे गए अभियुक्तों और गवाहों के बयानों को स्वीकार्य मानने का प्रश्न गंभीरता से विचार करने योग्य है।

3.5. न्यायमूर्ति जे.एस. वर्मा[17] की अध्यक्षता में आपराधिक कानून में संशोधन पर समिति की रिपोर्ट ने 'शिकायतों की फाइलिंग और पंजीकरण' की जांच करते हुए निम्नलिखित की सिफारिश की:

> *(क) यह समिति सिफारिश करती है कि दिल्ली महिला आयोग बनाम ललित पांडे और अन्य के मामले में दिल्ली उच्च न्यायालय द्वारा पुलिस के लिए जारी दिशा-निर्देश देश भर में सभी यौन अपराध शिकायतकर्ताओं के संबंध में अनिवार्य और तुरंत पालन किए जाने चाहिए। यह दिल्ली पुलिस द्वारा बलात्कार के मामलों की जांच करते समय पुलिस द्वारा पालन किए जाने वाले दिशानिर्देशों में जारी स्थायी आदेश संख्या 303/2010 के अनुसार है।*

[17] भारत सरकार, "आपराधिक कानून में संशोधन पर समिति की रिपोर्ट" 331 (भारत सरकार, 23 जनवरी 2013)

इनमें से, यह दिशानिर्देश विशेष रूप से महत्वपूर्ण है कि शिकायत/सूचना प्राप्त होने पर ड्यूटी अधिकारी को तुरंत "रेप क्राइसिस सेल" को उसके अधिसूचित हेल्पलाइन नंबर पर सूचित करना चाहिए। रेप क्राइसिस सेल को फिर शिकायतकर्ता को एफआईआर दर्ज करने में कानूनी सहायता प्रदान करने और शिकायतकर्ता को परामर्श प्रदान करने के लिए एक उचित योग्य व्यक्ति को भेजना चाहिए।

(ख) सभी पुलिस स्टेशनों में पुलिस स्टेशन के प्रवेश द्वार, पुलिस कक्ष और पूछताछ कक्ष में सीसीटीवी कैमरे होने चाहिए। सभी पीसीआर वैन में सीसीटीवी भी होने चाहिए।

सीसीटीवी के साथ छेड़छाड़ नहीं की जानी चाहिए और हर महीने एक स्वतंत्र विशेषज्ञ को यह सुनिश्चित करना चाहिए कि सीसीटीवी फुटेज के साथ छेड़छाड़ नहीं की गई है। यह पुलिस स्टेशनों में सुरक्षा सुनिश्चित करने का एक अतिरिक्त तरीका है और शिकायतों से निपटने, एफआईआर दर्ज करने और रिकॉर्ड करने और पुलिस हिरासत में लोगों के साथ किए जाने वाले व्यवहार में उचितका पालन किया जाता है। हम समझते हैं कि यह सभी ग्रामीण क्षेत्रों में संभव नहीं हो सकता है, लेकिन हमारा मानना है कि जहां संभव हो वहां सीसीटीवी लगाए जाने चाहिए।

(ग) प्रत्येक व्यक्ति को किसी भी पुलिस स्टेशन में एफआईआर दर्ज करने में सक्षम होने के अलावा, चाहे जिस अधिकार क्षेत्र में अपराध की लिखित शिकायत की गई हो, प्रत्येक व्यक्ति को एक निर्दिष्ट वेबसाइट पर अपनी शिकायत ऑनलाइन दर्ज करने में भी सक्षम होना चाहिए। इसके बाद एक शिकायत संख्या स्वचालित रूप से उत्पन्न होनी चाहिए ताकि शिकायतकर्ता एफआईआर की स्थिति का पता लगा सके।

वही शिकायत फिर निकटतम पुलिस स्टेशन में जारी की जाएगी, और एक प्रति प्रत्येक जिले में स्थित लोकपाल कार्यालय को भी प्रदान की जाएगी। अभी भी यह माना जाएगा कि कोई भी मामले की प्रथम इत्तिला रिपोर्टअनाम रूप से दर्ज नहीं की जा सकती है, और जिस व्यक्ति ने ऑनलाइन प्रथम इत्तिला रिपोर्ट दर्ज की है, उसे अपनी पहचान और प्रथम इत्तिला रिपोर्ट को सत्यापित करने के लिए निकटतम किसी भी पुलिस स्टेशन जाना होगा। दिल्ली पुलिस के पास पहले से ही ऑनलाइन पंजीकरण और प्रथम इत्तिला रिपोर्ट दर्ज करने की सुविधा है। इस प्रकार के उपायों को अपनाया जाना चाहिए और पूरे देश में कार्यान्वितकिया जाना चाहिए। शिकायतकर्ता को हर समय उपलब्ध करवाने के उद्धेश्य से राष्ट्रीय ऑनलाइन डेटाबेस पर भी एफआईआर दर्ज की जानी चाहिए।

3.6. विभाग-संबंधित संसदीय स्थायी समितियाँ[18], मलिमथ समिति[19] और राष्ट्रीय पुलिस आयोग[20] ने यौन हिंसा और अन्य शिकायतकर्ताओं से संबंधित मुद्दों पर विचार करते हुए पाया कि जब शिकायतकर्ता अपनी शिकायतें लेकर उनके पास जाते हैं तो पुलिस द्वारा उनके साथ उदासीन व्यवहार किया जाता है और कभी-कभी उन्हें परेशान किया जाता है। इस संबंध में, निम्नलिखित सिफारिशें इस प्रकार की जाती हैं:

[18] भारत सरकार, "167वीं विभाग-संबंधित गृह मामलों की संसदीय स्थायी समिति" (राज्य सभा 4 मार्च 2013)।

[19] भारत सरकार, "आपराधिक न्याय प्रणाली के सुधार पर समिति," 78 (गृह मंत्रालय, मार्च 2003)।

[20] भारत सरकार, "राष्ट्रीय पुलिस आयोग की चौथी रिपोर्ट" 4 (राष्ट्रीय पुलिस आयोग, 1980)।

(क.) गृह मामलों पर विभाग-संबंधित संसदीय स्थायी समिति ने आपराधिक कानून (संशोधन) विधेयक, 2012[21] पर अपनी 167वीं रिपोर्ट में निम्नानुसार सिफारिश की:

"5.36.2 समिति का मानना है कि एफआईआर का पंजीकरण अनिवार्य किया जाना चाहिए। समिति का दृढ़ विचार है कि यौन हिंसा पर शिकायतों को दर्ज करने से इनकार करने वाले अधिकारी के खिलाफ कर्तव्य में लापरवाही के लिए सख्त कार्रवाई की जानी चाहिए। समिति यह भी सिफारिश करती है एक बार एफआईआर दर्ज होने के बाद, समयबद्ध जांच सुनिश्चित करने के लिए मामले में जानकारी और आवश्यक निर्देश के लिए इसे उच्च पुलिस अधिकारी को भेजा जाना चाहिए। समिति आगे सिफारिश करती है कि जांच 60 दिनों की अवधि के भीतर की जानी चाहिए और समय पर आरोप पत्र दाखिल किया जाना चाहिए ताकि न्याय मिल सके।"

(ख) गृह मामलों पर विभाग-संबंधित संसदीय स्थायी समिति ने अपनी 189वीं रिपोर्ट[22] में एफआईआर के पंजीकरण में आने वाली समस्याओं की जांच की और सिफारिश की कि सभी एफआईआर दर्ज करने के लिए लचीला तंत्र विकसित किया जाना चाहिए। समिति ने एफआईआर के पंजीकरण के संबंध में 167वीं रिपोर्ट में की गई अपनी सिफारिशों को भी दोहराया।

(ग) शिकायतों के संबंध में, मालिरनाथ समिति[23] ने दांडिक न्याय प्रणाली की जांच करते हुए निम्नानुसार पाया:

"6.7.5 शिकायतकर्ताओं का कहना है कि जब वे अपनी शिकायतें लेकर पुलिस के पास जाते हैं तो उनके साथ उदासीन व्यवहार किया जाता है और तो कभी-कभी उनका उत्पीडन किया जाता है। ऐसी शिकायतें हैं कि पुलिस सत्यता के आधार पर दर्ज नहीं करती है, बल्कि तथ्यों को विकृत कर पेश करती है, जैसा उन्हें सुविधाजनक लगता है। संज्ञेय मामले को गैर-संज्ञेय बना दिया जाता है, और गैर-संज्ञेय को संज्ञेय। कभी-कभी शिकायतकर्ताओं को आरोपी बना दिया जाता है, और उसी के अनुरुप जांच शुरू की जाती है। हालांकि ये कानून द्वारा अनधिकृत हैं और दुर्लभ हैं, फिर भी जब भी ऐसा होता है तो पीड़ित का मोहभंग हो जाता है और वह सिस्टम से ही अन्यसंक्रांत कर लेते हैं।

16.7 प्रथम इत्तिला रिपोर्ट

16.7.1 यह सामान्य जानकारी की बात है कि भारत में महिलाएं अपने प्रियजनों और करीबी लोगों को भी यह बताने में काफी अनिच्छुक हैं कि वे आंशिक रूप से शर्म, उनकोगलत समझने की आशंका और परिणामों के डर के अलावा अपनी गहरे सदमे और भ्रमित स्थिति के कारण बलात्कार की शिकार हुई थीं। इससे अक्सर एफआईआर दर्ज करने में देरी होती है। एफआईआरदर्ज करवाने में अस्पष्टीकृत देरी अक्सर अभियोजन पक्ष के लिए घातक साबित होती है। अतः समिति सुझाव देती है कि ऐसे मामलों में एफआईआर प्रस्तुत करने के लिए एक उचित अवधि निर्धारित करते हुए संहिता में एक उपयुक्त प्रावधान शामिल किया जाए।

---

[21] भारत सरकार, "167वें विभाग-संबंधित गृह मामलों की संसदीय स्थायी समिति" 48 (राज्य सभा 4 मार्च 2013)।

[22] भारत सरकार, दिल्ली पुलिस के कार्यकरण पर 176वीं रिपोर्ट में निहित सिफारिशों/अवलोकनों पर सरकार द्वारा की गई कार्रवाई पर 189वीं रिपोर्ट। (राज्य सभा, दिसम्बर 2015).

[23] भारत सरकार, "आपराधिक न्याय प्रणाली सुधार समिति" 78 (गृह मंत्रालय, मार्च 2003)।

(घ) राष्ट्रीय पुलिस आयोग[24] ने दंड प्रक्रिया संहिता, 1973 के प्रावधानों सहित विभिन्न पुलिस सुधारों की जांच की। रिपोर्ट के पैरा 27.6 में राष्ट्रीय पुलिस आयोग ने धारा 154 में निम्नानुसार संशोधन करने का प्रस्ताव किया है -

"सीआरपीसी की धारा 154 में निम्निलखित संशोधन किए जा सकते हैं- पुलिस स्टेशन के प्रभारी अधिकारी को शिकायतकर्ता से पर्याप्त जानकारी का पता लगाने और इसे निर्धारित फॉर्म में शामिल करने या प्रथम इत्तिला रिपोर्ट दर्ज करने में समर्थ बनाया जा सकता है।

यह स्पष्ट करें कि प्रथम इत्तिला रिपोर्ट का पंजीकरण अनिवार्य है चाहे कथित अपराध पुलिस स्टेशन के अधिकार क्षेत्र में हुआ हो या नहीं; और

पुलिस स्टेशन से जुड़ी इकाइयों में प्रथम-सूचना रिपोर्ट की रिकॉर्डिंग की सुविधा प्रदान करना-उदाहरण के लिएः पोस्ट से बाहर पुलिस स्टेशन या ऐसे अन्य रिपोर्टिंग केंद्रों को नियत समय में उपरोक्त सुविधाएं विकसित की जा सकती हैं। (पैरा 27.6)

(ङ) इसके अलावा, पुलिस सुधारों पर पद्मनाभैया समिति का विचार था कि 150 साल पहले किए गए संज्ञेय और गैर-संज्ञेय अपराधों का वर्तमान वर्गीकरण आज बहुत प्रासंगिक नहीं है।[25]

ख. शिकायत और एफआईआर में अंतर

3.7. दंड प्रक्रिया संहिता, 1973 की धारा 2 (घ) के अधीन परिभाषित **'शिकायत'**[26] निम्नानुसार हैः

"(घ)" *"शिकायत" "से किसी मजिस्ट्रेट को मौखिक रूप से या लिखित रूप में इस संहिता के अधीन कार्रवाई करने की दृष्टि से किया गया कोई आरोप अभिप्रेत है कि किसी व्यक्ति, चाहे वह ज्ञात हो या अज्ञात, ने अपराध किया है, लेकिन इसमें पुलिस रिपोर्ट शामिल नहीं है।"*

स्पष्टीकरण *- किसी मामले में किसी पुलिस अधिकारी द्वारा दी गई रिपोर्ट जो जांच के बाद किसी गैर-संज्ञेय अपराध के होने का खुलासा करती है, उसे शिकायत माना जाएगा और जिस पुलिस अधिकारी द्वारा ऐसी रिपोर्ट की जाती है, उसे शिकायतकर्ता माना जाएगा।*

3.8. **'एफआईआर'** को कहीं भी इस तरह से परिभाषित नहीं किया गया है सिवाय इसके कि संज्ञेय अपराधों से संबंधित 'सूचना' का उल्लेख दंड प्रक्रिया संहिता, 1973 की धारा 154 (I) के तहत किया गया है और यह निम्नानुसार हैः

---

[24] भारत सरकार, "राष्ट्रीय पुलिस आयोग की चौथी रिपोर्ट" (राष्ट्रीय पुलिस आयोग, 1980)

[25] भारत सरकार, "पुलिस सुधारों पर पद्मनाभ समिति की रिपोर्ट" (गृह मंत्रालय। जनवरी 2000)

[26] दंड प्रक्रिया संहिता, 1973 की धारा 2(घ)

*"**154. संज्ञेय मामलों में सूचना**[27]- (1) संज्ञेय अपराध के होने से संबंधित प्रत्येक सूचना, यदि किसी पुलिस थाने के प्रभारी अधिकारी को मौखिक रूप से दी जाती है, तो उसके द्वारा या उसके निर्देश के तहत लिखित रूप में दी जाएगी और सूचना देने वाले के समक्ष पढ़ी जाएगीः और ऐसी प्रत्येक जानकारी, चाहे वह लिखित रूप में दी गई हो या लिखवाई गई हो, उसे देने वाले व्यक्ति द्वारा हस्ताक्षरित की जाएगी और उसका सार ऐसे अधिकारी द्वारा राज्य सरकार द्वारा विहित पुस्तक में दर्ज किया जाएगा।*

[बशर्ते कि यदि सूचना किसी महिला द्वाराभारतीय दंड संहिता की धारा 326क, धारा 326ख, धारा 354, धारा 354क, धारा 354ख, धारा 354ग, धारा 354घ, धारा 376,2[धारा 376क 376कख, धारा 376ख, धारा 376ग, धारा 376ड़घ, धारा 376घख], धारा 376ङ या धारा 509 (1860 का 45)के तहत दी गई है जिसके विरुद्ध कथित रूप से अपराध किया गया हो या प्रयास किया गया हो, तब ऐसी जानकारी किसी महिला पुलिस अधिकारी या किसी महिला अधिकारी द्वारा दर्ज की जाएगीः

परन्तु यह और कि

(क) उस दशा में जिसके विरुद्ध भारतीय दंड संहिता (1860 का 45) की धारा 354, धारा 354क, धारा 354ख, धारा 354ग, धारा 354द, धारा 376 [धारा 376क, धारा 376कख, धारा 376ख, धारा 376ग, धारा 376घख], धारा 376ड़ या धारा 509 के अधीन अपराध किया गया है या करने का प्रयास किया गया है और ऐसा अपराध अस्थायी रूप से या स्थायी रूप से मानसिक या शारीरिक रूप से अक्षम व्यक्ति के विरुद्ध किया गया है, तो ऐसी सूचना एक पुलिस अधिकारी द्वारा ऐसे अपराध की रिपोर्ट करने के इच्छुक व्यक्ति के निवास पर या ऐसे व्यक्ति की पसंद के सुविधाजनक स्थान पर, दुभाषिए या विशेष शिक्षक की उपस्थिति में, जैसा भी मामला हो, दर्ज की जाएगीः

(ख) ऐसी जानकारी की वीडियो रिकॉर्डिंग की जाएगी;

(ग) पुलिस अधिकारी धारा 164 की उप-धारा (5क) के खंड (क) के तहत न्यायिक मजिस्ट्रेट द्वारा दर्ज व्यक्ति का बयान जल्द से जल्द प्राप्त करेगा।

(घ) (2) उपधारा (1) के अधीन अभिलिखित सूचना की एक प्रति सूचना देने वाले को तुरंत निःशुल्क दी जाएगी।

(3) उप-धारा (1) में निर्दिष्ट सूचना को अभिलिखित करने के लिए किसी पुलिस थाने के प्रभारी अधिकारी की ओर से इनकार करने से व्यथित कोई व्यक्ति ऐसी सूचना का सार लिखित रूप में और डाक द्वारा संबंधित पुलिस अधीक्षक को भेज सकता है, जो यदि संतुष्ट हो जाता है कि ऐसी सूचना से संज्ञेय अपराध का खुलासा होता है, तो या तो स्वयं मामले की जाँच करेगा या इस संहिता द्वारा प्रदान की गई रीति से अपने अधीनस्थ किसी पुलिस अधिकारी द्वारा जाँच करने का निर्देश देगा और ऐसे अधिकारी को उस अपराध के संबंध में पुलिस थाने के प्रभारी अधिकारी की सभी शक्तियाँ होंगी।

3.9 इस प्रकार किसी संज्ञेय अपराध के बारे में कोई भी जानकारी, मौखिक या लिखित, पुलिस स्टेशन के प्रभारी अधिकारी द्वारा उस उद्देश्य के लिए लिखी गई पुस्तक में दर्ज की जानी चाहिए। यह जानकारी, जिस पर इत्तिला देने वाले के द्वारा भी हस्ताक्षर किए जाते हैं, प्रथम इत्तिला रिपोर्ट या एफआईआर के रूप में जानी जाती है।

[27] दंड प्रक्रिया संहिता, 1973 की धारा 154

3.10. इसके अलावा, शिकायत एफ़आईआर से इस अर्थ में अलग है कि शिकायत ठोस लेकिन स्पष्ट, सटीक, फिर भी कानूनी है, लेकिन एफ़आईआर एक तकनीकी दस्तावेज़ है जिसे पुलिस द्वारा तैयार किया जाता है जिसे तहरीर के रूप में जाना जाता है जिसमें आपराधिक संहिता के शब्द शामिल होते हैं और इसलिए जहाँ भी एफ़आईआर दर्ज करने की आवश्यकता होती है वहाँ पुलिस के हस्तक्षेप से बचा नहीं जा सकता है।

3.11. इसके अलावा, जैसा कि बीपीआरएंडडी ने अपने पत्र में सुझाव दिया है किऑनलाइन शिकायत को एसएचओ द्वारा जांच अधिकारी द्वारा प्रस्तुत जांच रिपोर्ट के आधार पर प्रथम इत्तिला रिपोर्ट में परिवर्तित किया जा सकता है।[28]

[28] पुलिस अनुसंधान और विकास ब्यूरो से प्राप्त पत्र सं. 32/31/2022-RD (E-14061) दिनांक 22 मई, 2023 ।

4. सरकार की ई-गवर्नेंस पहल

क. सी सी टी एन एस की शुरुआत

4.1. भारत सरकार का डिजिटल इंडिया कार्यक्रम भारत को डिजिटल रूप से सशक्त समाज और ज्ञान अर्थव्यवस्था में बदलने की दृष्टि से शुरू किया गया था। ई-गवर्नेंस को पहली बार राष्ट्रीय उपग्रह-आधारित कंप्यूटर नेटवर्क-1987में निकनेट के शुभारंभ द्वारा प्रदान किया गया था। ई-गवर्नेंस पहल ने 1990 के दशक के मध्य में नागरिक-केंद्रित सेवाओं पर जोर देने के साथ व्यापक क्षेत्रीय अनुप्रयोगों के लिए एक व्यापक आयाम लिया। आने वाले वर्षों में, कम्प्यूटरीकरण के साथ, टेली-कनेक्टिविटी और इंटरनेट कनेक्टिविटी ने केंद्र और राज्य दोनों स्तरों पर बड़ी संख्या में ई-गवर्नेंस पहल की स्थापना की।[29]

4.2 कॉमन इंटीग्रेटेड पुलिस एप्लीकेशन (सीआईपीए) परियोजना 2004-05 में शुरू की गई थी, जिसका उद्देश्य पुलिस स्टेशन को एक इकाई के रूप में लेते हुए अपराध और आपराधिक रिकॉर्ड का डिजिटलीकरण करना था। यह महसूस किया गया कि जांच में सहायता करने और नागरिक सेवाएं प्रदान करने के लिए देश में सभी पुलिस स्टेशनों को आपस में जोड़ने की आवश्यकता है, जिसमें पूर्ववृत्तियों का सत्यापन शामिल है, जिसे तब तक हासिल नहीं किया जा सकता जब तक कि डेटा को पूरे बोर्ड में साझा नहीं किया जाए और केंद्रीय रूप से एकत्रित नहीं किया जाए। इसलिए, अपराध और आपराधिक ट्रैकिंग नेटवर्क और सिस्टम (सी. सी. टी. एन. एस.) परियोजना 2009 में शुरू की गई थी। सी. सी. टी. एन. एस. भारत सरकार की राष्ट्रीय ई-शासन योजना के तहत एक मिशन मोड परियोजना है और इसका उद्देश्य ई-शासन के सिद्धांत को अपनाने और 'अपराध की जांच और अपराधियों का पता लगाने' के इर्द-गिर्द आई. टी. आधारित सक्षम अत्याधुनिक ट्रैकिंग प्रणाली के विकास के लिए एक राष्ट्रव्यापी नेटवर्किंग बुनियादी ढांचे के निर्माण के माध्यम से पुलिसिंग की दक्षता और प्रभावशीलता को बढ़ाने के लिए एक व्यापक और एकीकृत प्रणाली बनाना है। सी. सी. टी. एन. एस. परियोजना का समग्र दृष्टिकोण एक अत्याधुनिक प्रणाली का निर्माण करना है जो सभी हितधारकों को वास्तविक समय में अपराध और आपराधिक जानकारी तक पहुंच को सुनिश्चित करता है।[30]

4.3. सीसीटीएनएस[31] के उद्देश्यः

क. पुलिस प्रक्रियाओं (एफआईआर, जाँच, चालानों) का कम्प्यूटरीकरण प्राप्त करना।

ख. अपराध और आपराधिक रिकॉर्ड के राष्ट्रीय डेटाबेस पर अखिल भारतीय खोज प्रदान करना।

---

[29] परिचय, डिजिटल इंडिया, भारत सरकार, https://digitalindia.gov.irlintroductiorv पर उपलब्ध है (अंतिम बार 136 जुलाई 2023 को देखा गया)।

[30] सीसीटीएनएस, महिला सुरक्षा प्रभाग, गृह मंत्रालय, भारत सरकार, https://www.mha.gov.in/en/divisionofmha/women-safety-division/cctns पर उपलब्ध है।

(13 जुलाई, 2023 को अन्तिम बार देखा गया)

[31] सीसीटीएनएस परियोजना का संक्षिप्त विवरण और स्थिति, गृह मंत्रालय, भारत सरकार, https://www.mha.gov.in/en/divisionofmha/women-safety-division/cctns पर उपलब्ध है

(13 जुलाई, 2023 को अन्तिम बार देखा गया)

ग. राज्य और केंद्र स्तर पर अपराध और आपराधिक रिपोर्ट तैयार करना।

घ. वेब पोर्टल के माध्यम से नागरिक केंद्रित पुलिस सेवाएं प्रदान करना।

ङ. अधिक प्रभावी न्याय देने के लिए पुलिस स्टेशनों, अदालतों, जेलों, फोरेंसिक और अभियोजन के बीच अपराध और आपराधिक डेटा को साझा करना।

च. अपराध की जांच, अपराध की रोकथाम, कानून और व्यवस्था बनाए रखने और अन्य कार्यों जैसे यातायात प्रबंधन, आपातकालीन प्रतिक्रिया आदि के लिए उन्नत उपकरण प्रदान करना।

छ. सुव्यवस्थित और मानकीकरण के माध्यम से प्रक्रियाओं में अतिरेक को कम करके परिचालन दक्षता में वृद्धि, पुलिस मैसेजिंग, ईमेल, मोबाइल टेलीफोन आदि जैसे अतिरिक्त संचार साधनों तक पहुंच और उपलब्धता प्रदान करके संचार में वृद्धि, सूचना संग्रह, एमआईएस, कार्यप्रवाह आदि जैसे बैक ऑफिस कार्यों को स्वचालित करना।

ज. सूचना और खुफिया जानकारी साझा करने के लिए राष्ट्रीय मंच का निर्माण करना।

4.4. सी. सी. टी. एन. एस.[32] के लाभः

सी. सी. टी. एन. एस. के सफल कार्यान्वयन से निम्नलिखित लाभों की परिकल्पना की गई हैः

(क) पुलिस विभाग को लाभ

I. जाँच के लिए उन्नत उपकरण।

II. उन्नत खोज क्षमताओं के साथ आपराधिक छवियों और उंगलियों के निशान के साथ केंद्रीकृत अपराध और आपराधिक सूचना संग्रह।

III. अपराध पैटर्न और/या कार्यप्रणाली का विश्लेषण करने की क्षमता में वृद्धि

IV. सड़क दुर्घटनाओं और अन्य दुर्घटनाओं का विश्लेषण करने की क्षमता में वृद्धि।

V. क्षेत्र के अधिकारियों तक पहुंचने के लिए विश्लेषण परिणामों (आपराधिक और यातायात) के लिए तेजी से काम कर समय की बचत।

VI. पुलिस थानों की बैक-ऑफिस गतिविधियों जैसे नियमित और तदर्थ रिपोर्ट तैयार करने और स्टेशन रिकॉर्ड प्रबंधन के लिए कम कार्यभार।

VII. एक सहयोगात्मक ज्ञान-उन्मुख वातावरण जहां सूचनाओं को विभिन्न क्षेत्रों और इकाइयों में साझा किया जाता है।

VIII. इलेक्ट्रॉनिक सूचना विनिमय प्रणालियों के कार्यान्वयन के माध्यम से बाहरी हितधारकों के साथ बेहतर समन्वय और संचार।

(ख) नागरिकों को लाभ

I. पुलिस से सेवाओं तक पहुँचने के लिए कई माध्यम।

II. याचिकाओं के पंजीकरण के लिए सरल प्रक्रिया।

III. प्रमाणपत्रों, सत्यापन और अनुमतियों के लिए अनुरोध जैसी सामान्य सेवाओं तक पहुंचने के लिए आसान प्रक्रिया।

[32] सीसीटीएनएस, राष्ट्रीय अपराध रिकॉर्ड ब्यूरो, गृह मंत्रालय, भारत सरकार, https://ncrb.gov.in/en/crime-and-criminal-tracking-network-systems-cctns पर उपलब्ध है। (13 जुलाई, 2023 को अन्तिम बार देखा गया)

IV. विचारण के दौरान मामले की प्रगति पर नज़र रखने की सरल प्रक्रिया और सटीक साधन।

V. लावारिस/बरामद वाहनों और संपत्ति को देखने/रिपोर्ट करने के लिए सरल और सटीक पहुंच।

VI. शिकायत पंजीकरण के लिए सरल प्रक्रिया और माध्यम।

VII. पीड़ितों और गवाहों के लिए बेहतर संबंध प्रबंधन।

VIII. सहायता के लिए किसी भी आपातकालीन स्थिति में पुलिस की ओर से तेज और आश्वस्त प्रतिक्रिया।

(ग) बाहरी विभागों को लाभ

i. नागरिकों को बेहतर सेवा प्रदान करने और बेहतर कानून प्रवर्तन के लिए पुलिस प्रणालियों के साथ निर्बाध एकीकरण।

ii. पुलिस विभाग के साथ सटीक जानकारी का त्वरित आदान-प्रदान।

यूथ बार एसोसिएशन ऑफ इंडिया बनाम भारत संघ[33] में, 'क्राइम एंड क्रिमिनल ट्रैकिंग नेटवर्क एंड सिस्टम (सीसीटीएनएस)' परियोजना के तहत ऑनलाइन शिकायत दर्ज करने पर चर्चा की गई, जिसमें भारत सरकार की ओर से पेश वद्धान अतिरिक्त सॉलिसिटर जनरल तुषार मेहता ने बताया कि केंद्र सरकार 'क्राइम एंड क्रिमिनल ट्रैकिंग नेटवर्क एंड सिस्टम (सीसीटीएनएस)' परियोजना के तहत शिकायतों को ऑनलाइन दर्ज करने के लिए एक तंत्र स्थापित करने के लिए सभी राज्यों का सहायोग कर रही है।

ख. सीसीटीएनएस आर्किटेक्चर

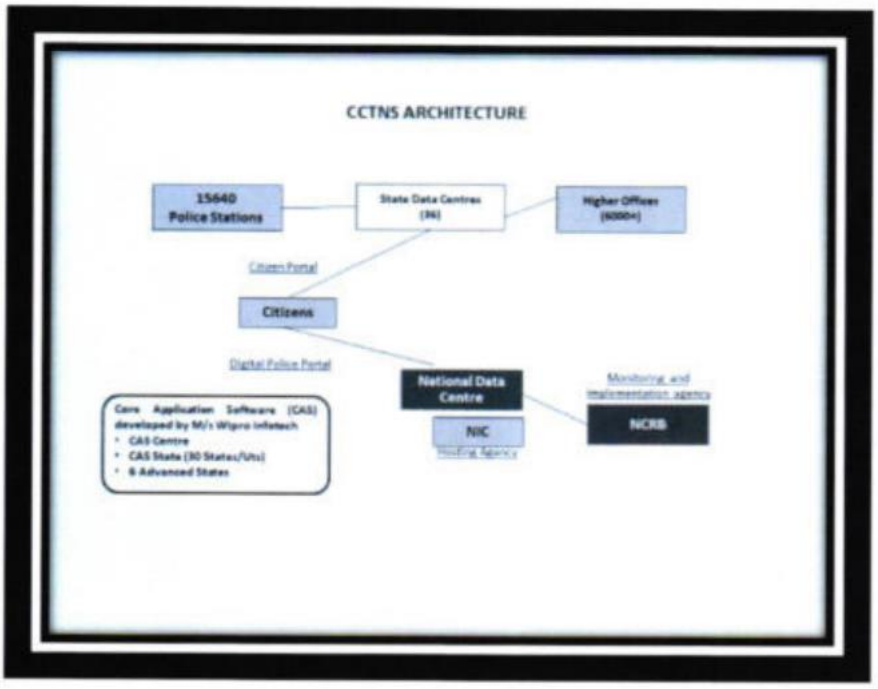

[33] एआईआर 2016 एससी 4136

ग. सी. सी. टी. एन. एस. शिकायत पंजीकरण प्रक्रिया

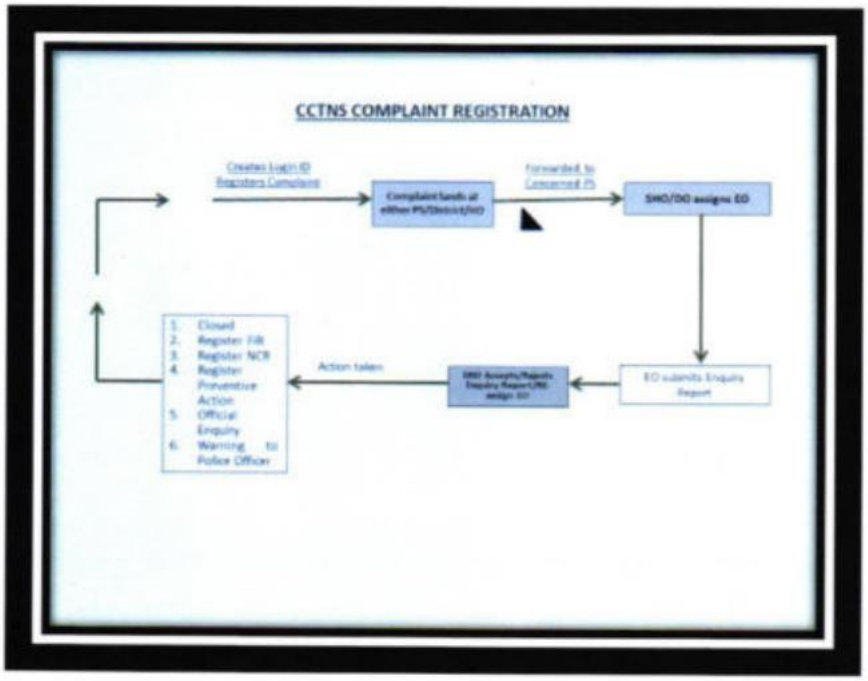

घ. सी. सी. टी. एन. एस. के कार्यान्वयन की वर्तमान स्थिति[34]

4.5. निम्नलिखित आंकड़े सी. सी. टी. एन. एस. सॉफ्टवेयर और इसके उपयोग से संबंधित स्थिति को दर्शाते हैं। पहला आंकड़ा पुलिस स्टेशनों पर सीसीटीएनएस सॉफ्टवेयर के अभिनियोजन से संबंधित है, दूसरा आंकड़ा राज्य डेटा केंद्र (एसडीसी)से जुड़े पुलिस स्टेशनों सेऔर तीसरा पुलिस स्टेशनों द्वारा सी. सी. टी. एन. एस. में 100% एफआईआर दर्ज करने से संबंधित है।

[34] डॉ. प्रशुन गुप्ता और नरेंद्र कुमार कोली, "प्रोजेक्ट मैनेजमेंट ऑफ सीसीटीएनएस" 1 एनसीआरबी जर्नल 80 (नवम्बर, 2022).

चित्र संख्या-1 सीसीटीएनएस सॉफ्टवेयर का पुलिस स्टेशनों पर अभिनियोजन[35]

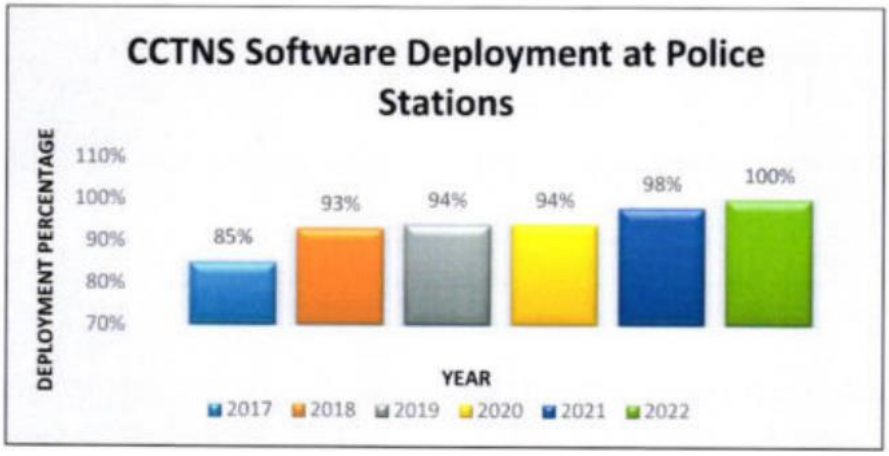

चित्र 2: राज्य डेटा केंद्र (एसडीसी) से जुड़े पुलिस स्टेशन[36]

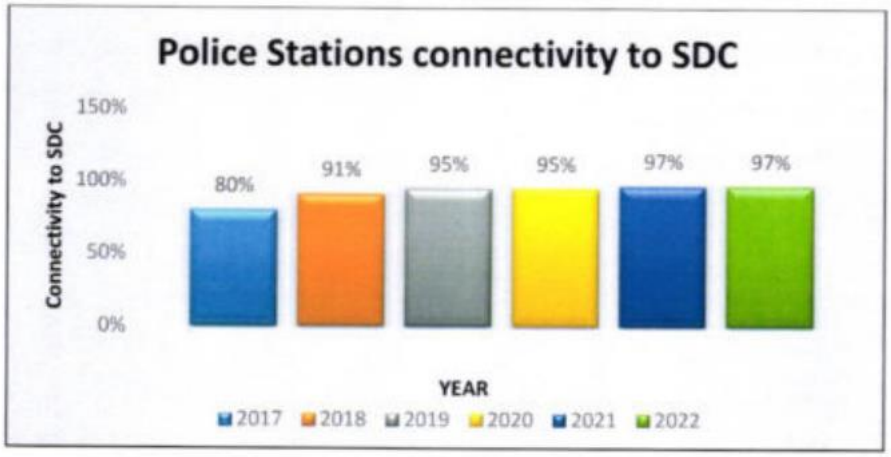

चित्र 3: पुलिस स्टेशनों ने सी. सी. टी. एन. एस. में 100% एफआईआर दर्ज की[37]

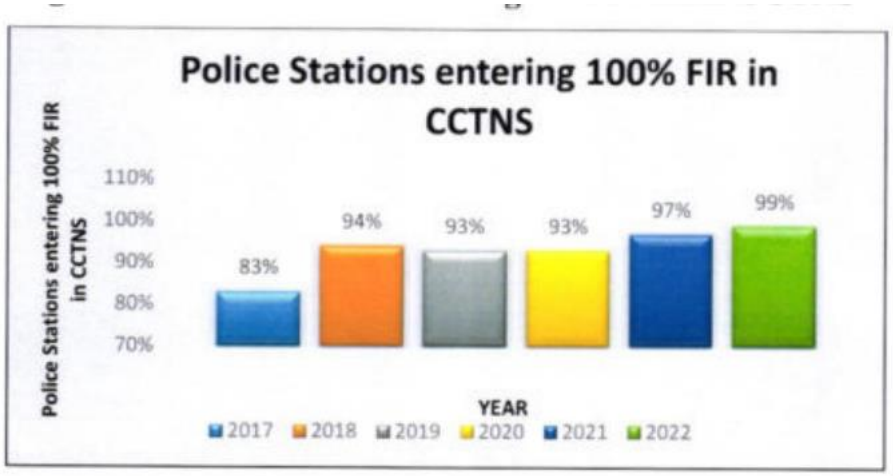

[35] पूर्वोक्त
[36] पूर्वोक्त
[37] पूर्वोक्त

4.6. 31 अगस्त 2018 के एनसीआरबी के डेटा के अनुसार, राज्यों में नागरिकों और पुलिस के लिए निम्नलिखित मोबाइल एप्लिकेशन विकसित किए गए हैं:

क. शिकायत पंजीकरण (तेलंगाना, झारखंड, हिमाचल प्रदेश, पुडुचेरी, जम्मू-कश्मीर, तमिलनाडु, मध्य प्रदेश, महाराष्ट्र, जम्मू-कश्मीर)

ख. मोटर वाहन चोरी और संपत्ति चोरी के लिए ऑनलाइन एफआईआर दर्ज करना (दिल्ली, छत्तीसगढ़, उत्तर प्रदेश)

ग. लापता बच्चों/व्यक्तियों का पता लगाने के लिए (हिमाचल प्रदेश, आंध्र प्रदेश, छत्तीसगढ़, दिल्ली)

घ. अज्ञात शवों की पहचान करने के लिए (छत्तीसगढ़, आंध्र प्रदेश, महाराष्ट्र, मध्य प्रदेश)

ङ. नागरिकों द्वारा सूचना देना (महाराष्ट्र, मध्य प्रदेश)

च. नागरिक सहायता ऐप और ई-एफआईआर - उत्तर प्रदेश गुजरात, मध्य प्रदेश)

ङ. *राज्यों के वेब पोर्टल पर ई-एफआईआर दर्ज करना।*

4.7. 22 मई 2023[38] के पत्राचार के अनुसार, पुलिस अनुसंधान और विकास ब्यूरो ने भारत के विधि आयोग को सूचित किया है कि आठ राज्यों (दिल्ली, गुजरात, कर्नाटक, मध्य प्रदेश, ओडिशा, राजस्थान, उत्तर प्रदेश और उत्तराखंड) ने एनसीआरबी की सीसीटीएनएस परियोजना के तहत ई-एफआईआर का पंजीकरण क्रियान्वित किया है। एनसीआरबी वेबसाइट के नोडल अधिकारी अनुभाग के तहत ई-एफआईआर मॉड्यूल के एसओपी के साथ जावा और माइक्रोसॉफ्ट दोनों में स्रोत कोड उपलब्ध कराए गए हैं। चूंकि पुलिस राज्य का विषय है, इसलिए राज्यों/केंद्र शासित प्रदेशों को ई-एफआईआर मॉड्यूल डाउनलोड करने और कार्यान्वित करने का अनुरोध किया गया।

4.8. हालाँकि, ऑनलाइन शिकायत सुविधा का पंजीकरण सभी राज्यों/केंद्र शासित प्रदेशों में सी. सी. टी. एन. एस. परियोजना के तहत विकसित उनके राज्य नागरिक पोर्टल पर उपलब्ध है।[39]

[38] पत्र संख्या 32/3112022-RD (E-14061) दिनांक 22 मई, 2023 को पुलिस अनुसंधान और विकास ब्यूरो से प्राप्त हुआ।

[39] पूर्वोक्त

5. एफआईआर के पंजीकरण पर संबंधित न्यायिक प्रामाणिक निर्णय

क. यूथ बार एसोसिएशन बनाम भारत संघ[40]

5.1. यूथ बार एसोसिएशन बनाम भारत संघ के मामले में माननीय सर्वोच्च न्यायालय ने राज्यों को भारत के क्षेत्र के भीतर सभी पुलिस स्टेशनों में दर्ज प्रत्येक एफआईआर को अपनी आधिकारिक वेबसाइट पर अपलोड करने का निर्देश जारी करते हुए, अन्य बातों के साथ-साथ निम्नलिखित निर्देश जारी किए:

".....

11.1 अभियुक्त प्रथम इत्तिला रिपोर्ट की प्रति दंड प्रक्रिया संहिता की धारा 207 के अधीन विहित समय से पूर्व प्राप्त करने का हकदार है।

11.2 एक अभियुक्त जिस पर संदेह करने के कारण हैं कि वह आपराधिक मामले में शामिल था और उसका नाम प्रथम इत्तिला रिपोर्ट में आया है, वह अपने प्रतिनिधि/एजेंट/पेरोकार के माध्यम से संबंधित पुलिस अधिकारी या पुलिस अधीक्षक के समक्ष प्रमाणित प्रति प्राप्त करने के लिए ऐसे शुल्क के भुगतान पर आवेदन प्रस्तुत कर सकता है जो अदालत से ऐसी प्रति प्राप्त करने के लिए निर्धारित है। इस तरह का आवेदन किए जाने पर, प्रतिलिपि चौबीस घंटों के भीतर प्रदान की जाएगी।

11.3 एक बार जब प्रथम इत्तिला रिपोर्ट संबंधित मजिस्ट्रेट या किसी विशेष न्यायाधीश को पुलिस स्टेशन द्वारा अग्रेषित की जाती है और अभियुक्त की ओर से प्रमाणित प्रति के लिए आवेदन दिया जाता है तो उसे संबंधित न्यायालय द्वारा दो कार्य दिवसों के भीतरप्रमाणित प्रति उपलब्ध करवाई जाएगी। उपरोक्त निर्देश का सीआरपीसी की धारा 207 के तहत दिए गए वैधानिक आदेश से कोई लेना-देना नहीं है।

11.4 यदि अपराध प्रकृति में संवेदनशील न हो, जैसे यौन अपराध, उग्रवाद से संबंधित अपराध, आतंकवाद और उस श्रेणी के अपराध, पॉक्सो अधिनियम के तहत अपराध और ऐसे अन्य अपराध तो एफआईआर की प्रतिपुलिस वेबसाइट पर अपलोड की जानी चाहिए, और यदि ऐसी कोई वेबसाइट नहीं है, तो राज्य सरकार की आधिकारिक वेबसाइट पर प्रथम इत्तिला रिपोर्ट के पंजीकरण के चौबीस घंटे के भीतर अपलोड की जानी चाहिए ताकि आरोपी या उससे जुड़ा कोई भी व्यक्ति एफआईआर डाउनलोड कर सके और अपनी शिकायतों के निवारण के लिए विधि अनुसार अदालत में उचित आवेदन दायर कर सके। यहां यह स्पष्ट किया जा सकता है कि यदि भौगोलिक स्थिति के कारण कनेक्टिविटी की समस्या है या कोई अन्य अपरिहार्य कठिनाई है, तो समय 48 घंटे तक बढ़ाया जा सकता है। उक्त 48 घंटे को अधिकतम 72 घंटे तक बढ़ाया जा सकता है और यह केवल भौगोलिक स्थिति के लिए संपर्क समस्याओं के संबंध में ही कार्यान्वित है।

[40] एआईआर2016 एससी 4136

11.5 वेबसाइट पर एफआईआर की प्रति अपलोड नहीं करने का निर्णय पुलिस उपाधीक्षक के पद से नीचे के अधिकारी या समकक्ष पद पर आसीन किसी व्यक्ति द्वारा नहीं लिया जाएगा। यदि उन राज्यों में जहां जिला मजिस्ट्रेट की भूमिका है, तो वह उक्त प्राधिकार का उपयोग कर सकता है। संबंधित पुलिस अधिकारी या जिला मजिस्ट्रेट द्वारा लिए गए निर्णय को संबंधित क्षेत्राधिकार मजिस्ट्रेट को विधिवत सूचित किया जाएगा।

11.6 अन्य पहलुओं के अलावा 'संवेदनशील' शब्द, जिसे सक्षम प्राधिकारी द्वारा संवेदनशील माना जा सकता है, जैसा कि पहले कहा गया है, इसमें एफआईआर की प्रकृति के लिए गोपनीयता के संबंध में अवधारणा भी शामिल होगी। संवेदनशील मामलों के संबंध में दिए गए उदाहरण पूरी तरह से उदाहरणात्मक हैं न कि नि:शेष।

11.7 यदि कोई एफआईआर अपलोड नहीं की जाती है, तो कहने की आवश्यकता नहीं है, यह सीआरपीसी की धारा 438 के तहत लाभ प्राप्त करने के लिए अपने आप में एक आधार सुनिश्चित नहीं करेगा।

11.8 यदि मामले की संवेदनशील प्रकृति के आधार पर एफआईआर की प्रति उपलब्ध नहीं कराई जाती है, तो उक्त कार्रवाई से पीडित व्यक्ति, अपनी पहचान का खुलासा करने के बाद, पुलिस अधीक्षक या राज्य में समकक्ष पद धारण करने वाले किसी भी व्यक्ति को अभ्यावेदन प्रस्तुत कर सकता है। पुलिस अधीक्षक द्वारा तीन अधिकारियों की एक समिति का गठन किया जाएगा जो उक्त शिकायत की जांच करेगी। जहाँ तक महानगरों का संबंध है, जहाँ आयुक्त है, यदि पुलिस आयुक्त को एक अभ्यावेदन प्रस्तुत किया जाता है वह तीन अधिकारियों की एक समिति का गठन करेगें। इस प्रकार गठित समिति अभ्यावेदन प्राप्त होने की तारीख से तीन दिन के भीतर शिकायत का निपटारा करेगी और इसे पीडित व्यक्ति को सूचित करेगी।

11.9 ऊपर उल्लिखित सक्षम प्राधिकारी वर्तमान दिवस से आठ सप्ताह के भीतर समिति का गठन करेगा, जैसा कि ऊपर निर्देशित किया गया है।

11.10 जिन मामलों में मामले की संवेदनशील प्रकृति के संबंध में प्रथम इत्तिला रिपोर्ट की प्रतियां न देने के लिए निर्णय लिया गया है, वहां अभियुक्त/उसके अधिकृत प्रतिनिधि/पैरोकार जिस न्यायालय में प्रथम इत्तिला रिपोर्ट भेजी गई है उस न्यायालय के समक्ष प्रमाणित प्रति प्राप्त करने के लिए आवेदन प्रस्तुत कर सकता है, और उसी संबंधित न्यायालय द्वारा आवेदन प्रस्तुत करने के तीन दिनों के भीतरकाफी शीघ्रता से प्रमाणित प्रति उपलब्ध करवानी होगी।

11.11 सभी राज्यों की वेबसाइट पर एफआईआर अपलोड करने के निर्देश 15-11-2016 से प्रभावी होंगे।

ख. लोलिता कुमारी बनाम उत्तर प्रदेश सरकार[41]

5.2. इस मामले में, माननीय उच्चतम न्यायालय ने कुछ मामलों में प्रथम इत्तिला रिपोर्ट दर्ज करने से पहले प्रारंभिक जांच की अनुमति देते हुए कहा किः

> *V. "प्रारंभिक जांच का दायरा प्राप्त जानकारी की सत्यता या अन्यथा को सत्यापित करना नहीं है, बल्कि केवल यह पता लगाने के लिए है कि क्या जानकारी किसी संज्ञेय अपराध का खुलासा करती है।*
>
> *VI. किस प्रकार और किन मामलों में प्रारंभिक जांच की जानी है, यह प्रत्येक मामले के तथ्यों और परिस्थितियों पर निर्भर करेगा। जिन मामलों में प्रारंभिक जांच की जा सकती है, उनकी श्रेणी इस प्रकार हैः*
>
> *क. वैवाहिक विवाद/पारिवारिक विवाद*
>
> *ख. व्यावसायिक अपराध*
>
> *ग. चिकित्सकीय लापरवाही के मामले*
>
> *घ. भ्रष्टाचार के मामले*
>
> *उदाहरण के लिए, ऐसे मामले जहां आपराधिक अभियोजन शुरू करने में असामान्य देरी/विलंब होता है, उदाहरण के लिए, देरी के कारणों को संतोषजनक रूप से बताए बिना मामले की रिपोर्ट करने में तीन महीने से अधिक की देरी।उपर्युक्त केवल दृष्टांत हैं और उन सभी शर्तों का संपूर्ण विवरण नहीं है जो प्रारंभिक जांच की आवश्यकता हो सकती हैं।*
>
> *vii. अभियुक्त और शिकायतकर्ता के अधिकारों को सुनिश्चित करते हुए और उनकी रक्षा करते हुए, प्रारंभिक जांच समयबद्ध की जानी चाहिए और किसी भी मामले में यह 7 दिनों से अधिक नहीं होनी चाहिए। इस तरह की देरी का तथ्य और इसके कारण सामान्य डायरी प्रविष्टि में परिलक्षित होने चाहिए।*

ग. न्यायालय के स्वत: संज्ञान बनाम राज्य[42]

5.3. न्यायालय के स्वत: संज्ञान बनाम राज्य के मामले में, दिल्ली उच्च न्यायालय की खंड पीठ ने एक अभियुक्त के प्रथम इत्तिला रिपोर्ट की प्रति रखने के अधिकार के मुद्दे पर विचार किया और कहा कि प्रथम इत्तिला रिपोर्ट भारतीय साक्ष्य अधिनियम की धारा 74 के तहत परिभाषित एक सार्वजनिक दस्तावेज है और निष्पक्ष और पक्षपात रहित जांच भारत के संविधान के अनुच्छेद 21 का एक पहलू है और एक अभियुक्त की बेगुनाही के संबंध में धारणा एक मानव अधिकार है। इसलिए, जिस व्यक्ति पर आपराधिक कानून के तहत मामला दर्ज किया गया है, उसे आरोपों की प्रकृति जानने का अधिकार है ताकि वह अपनी स्वतंत्रता की रक्षा के लिए आवश्यक कदम उठा सके। विधिसम्मत शासन द्वारा शासित देश में यह अनिवार्य है। न्यायालय ने निम्नलिखित निर्णय दियाः

---

[41] (2014) 2 एससीसी 142 2011 आपराधिक न्याय 347

[42] 2011 आपराधिक न्याय 1347

"(क) एक आरोपी सीआरपीसी की धारा 207 के तहत निर्धारित समय से पहले एफआईआर/सूचना रिपोर्ट की एक प्रति प्राप्त करने का हकदार है।

(ख) एक अभियुक्त जिसे संदेह के आधार पर आपराधिक मामले में शामिल किया गया है और उसका नाम प्रथम इत्तिला रिपोर्ट में दर्ज किया गया है, वह अपने प्रतिनिधि/एजेंट/पैरोकार के माध्यम से संबंधित पुलिस अधिकारी या पुलिस अधीक्षक के समक्ष प्रमाणित प्रति प्राप्त करने के लिए आवेदन प्रस्तुत कर सकता है। इस तरह का आवेदन किए जाने पर, प्रतिलिपि चौबीस घंटों के भीतर प्रदान की जाएगी।

(ग) एक बार पुलिस स्टेशन द्वारा प्रथम इत्तिला रिपोर्ट संबंधित मजिस्ट्रेट या किसी विशेष न्यायाधीश को भेज दी जाती है तो अभियुक्त की ओर से प्रमाणित प्रति के लिए आवेदन दायर किए जाने पर, संबंधित न्यायालय द्वारा दो कार्य दिवसों के भीतर उपरोक्त की प्रति अभियुक्त को दी जाएगी। उपरोक्त निर्देश का सीआरपीसी की धारा 207 के तहत दिए गए वैधानिक आदेश से कोई लेना-देना नहीं है।

(घ) एफआईआर की प्रतियां, जब तक कि अपराध की प्रकृति को ध्यान में रखते हुए दर्ज किए गए कारण न हों कि वह प्रकृति में संवेदनशील है, एफआईआर दर्ज होने के चौबीस घंटे के भीतर दिल्ली पुलिस की वेबसाइट पर अपलोड की जानी चाहिए ताकि अभियुक्त या उससे जुड़ा कोई भी व्यक्ति एफआईआर डाउनलोड कर सके और अपनी शिकायतों के निवारण के लिए कानून के अनुसार न्यायालय के समक्ष उपयुक्त आवेदन दायर कर सके।

(ङ) दिल्ली पुलिस की वेबसाइट पर एफआईआर की प्रति अपलोड नहीं करने का निर्णय पुलिस उपायुक्त के पद से नीचे के अधिकारी द्वारा नहीं लिया जाएगा और वह भी सकारण आदेश के माध्यम से। पुलिस उपायुक्त द्वारा इस प्रकार लिए गए निर्णय के बारे में क्षेत्रीय मजिस्ट्रेट को भी विधिवत सूचित किया जाएगा।

(च) अन्य पहलुओं के अलावा 'संवेदनशील' शब्द, जिसे सक्षम प्राधिकारी द्वारा संवेदनशील माना जा सकता है, जैसा कि पहले कहा गया है, इसमें एफआईआर की प्रकृति के लिए गोपनीयता के संबंध में अवधारणा भी शामिल होगी।

(छ) यदि मामले की संवेदनशील प्रकृति के आधार पर प्रथम इत्तिला रिपोर्ट की प्रति उपलब्ध नहीं कराई जाती है, तो उक्त कार्रवाई से पीड़ित व्यक्ति अपनी पहचान का खुलासा करने के बाद पुलिस आयुक्त के समक्ष एक अभ्यावेदन प्रस्तुत कर सकता है, जो तीन उच्च अधिकारियों की एक समिति का गठन करेगा और समिति अभ्यावेदन प्राप्त होने की तारीख से तीन दिनों के भीतर उक्त शिकायत पर विचार करेगी और पीड़ित व्यक्ति को सूचित करेगी।

(ज) पुलिस आयुक्त आज से आठ सप्ताह के भीतर समिति का गठन करेगा।

(झ) ऐसे मामलों में जहां मामले की संवेदनशील प्रकृति के संबंध में प्रथम इत्तिला रिपोर्ट की प्रतियां नहीं देने का निर्णय लिया गया है, अभियुक्त/उसके अधिकृत प्रतिनिधि/पैरोकार के पास यह विकल्प होगा कि वह उस न्यायालय के समक्ष प्रमाणित प्रतिलिपि के लिए आवेदन दायर करे, जिसे प्रथम इत्तिला रिपोर्ट भेजी गई है और संबंधित न्यायालय द्वारा आवेदन प्रस्तुत करने के यथा संभव तीन दिनों में काफी शीघ्रता से उपलब्ध करवाई जाएगी।

(ञ) दिल्ली पुलिस की वेबसाइट पर एफआईआर अपलोड करने के निर्देश 01 फरवरी, 2011 से प्रभावी होंगे।

घ. ताजिन्दर सिंह एवं अन्य बनाम भारत संघ एवं अन्य[43]

5.4. इस मामले में अदालत ने प्रत्यर्थियों द्वारा संज्ञेय और गैर-संज्ञेय दोनों अपराधों के खिलाफ ई-एफआईआर दर्ज करने के लिए नीतिगत निर्णय लेने के अनुरोध वाली याचिका को खारिज कर दिया और यह कहकर सभी अपराधों के लिए ई-एफआईआर का दायरा बढ़ाने का विरोध किया।

> *"कई प्रकार के अपराधों के लिए ई-एफआईआर की अनुमति पहले से ही प्रत्यर्थियों द्वारा दी गई है, लेकिन हम सभी प्रकार के अपराधों में ई-एफआईआर दर्ज करने की अनुमति नहीं देना चाहते हैं।*

5.5 इस याचिका में न्यायालय ने आगे कहा किः

> *"यह ध्यान में रखा जाना चाहिए कि सभी मामलों में ई-एफआईआर की अनुमति मुख्य रूप से इस कारण से नहीं दी जा सकती है कि कभी-कभी एक पीड़ित जिसे प्रथम इत्तिला रिपोर्ट दर्ज करनी होती है, उसे जुर्माने की बारीकियों के बारे में पता नहीं होता है और इसलिए अपराधों के तत्वों को ई-एफआईआर में शामिल नहीं किया जा सकता है। यदि इसकी अनुमति भी दी जाए तो उस स्थिति में यदि उच्च न्यायालय की अंतर्निहित शक्तियों के तहत अभियुक्त द्वारा शुरू की गई किसी कार्यवाही में, ऐसी किसी कमी के कारण यह अनुमति दी जाती है, तो प्रथम इत्तिला रिपोर्ट दर्ज करने का उद्देश्य ही विफल हो जाएगा। ई-एफआईआर/या ऐसे अन्य प्रकार के मामले जो प्रत्यर्थीयों द्वारा लिए गए नीतिगत निर्णय के अनुसार ई-एफआईआर की अनुमति नहीं है।*

(ड) अरनेश कुमार बनाम बिहार सरकार एवं अन्य[44]

5.6. इस मामले में माननीय सर्वोच्च न्यायालय ने अपील को स्वीकार कर लिया और गिरफ्तारी की शक्ति के प्रयोग पर विस्तृत निर्देश जारी किए और कहा किः

> *"5. गिरफ्तारी अपमानित करती है, स्वतंत्रता को कम करती है और हमेशा के लिए एक बदनामी का द्धब्बा छोडती है। यह कानून निर्माता भी जानते हैं और पुलिस भी।*
>
> ***6...** कोई गिरफ्तारी केवल इसलिए नहीं की जानी चाहिए क्योंकि अपराध गैर-जमानती और संज्ञेय है और इसलिए पुलिस अधिकारियों का ऐसा करना वैध है। गिरफ्तार करने की शक्ति का अस्तित्व एक बात है। इसके प्रयोग का औचित्य बिल्कुल अलग है। गिरफ्तारी की शक्ति के*

[43] तेजिन्दर सिंह एवं अन्य बनाम भारत संघ 2019 एससीसी ऑनलाईन डेल 12143

[44] (2014) 8 एससीसी 273।

अलावा, पुलिस अधिकारियों को अपने कारणों को सही ठहराने में सक्षम होना चाहिए। किसी व्यक्ति के खिलाफ अपराध करने के मात्र आरोप पर नियमित तरीके से कोई गिरफ्तारी/कार्रवाई नहीं की जा सकती है। एक पुलिस अधिकारी के लिए यह विवेकपूर्ण और बुद्धिमानी होगी कि आरोप की वास्तविकता के बारे में कुछ जांच के बाद उचित संतुष्टि के बिना कोई गिरफ्तारी नहीं की जाए।

7. ...

41. जब पुलिस वारंट के बिना गिरफ्तार कर सकती है। - (1) कोई भी अधिकारी मजिस्ट्रेट वारंट के आदेश के बिना किसी व्यक्ति को गिरफ्तार कर सकता है -

*(क) * * * **

(ख)जिसके विरुद्ध एक उचित शिकायत की गई है, या विश्वसनीय जानकारी प्राप्त की गई है, या एक उचित संदेह मौजूद है कि उसने एक संज्ञेय अपराध किया है जिसमें सजा के तौर पर सात साल के कारावास का प्रावधान है या जो सात साल तक बढ़ाया जा सकता है चाहे जुर्माना के साथ या जुर्माना के बिना, यदि निम्नलिखित शर्तें पूरी हो जाती हैं अर्थात्: -

*(i) * * * **

(ii) पुलिस अधिकारी संतुष्ट है कि ऐसी गिरफ्तारी आवश्यक है।

(क) ऐसे व्यक्ति को कोई और अपराध करने से रोकने के लिए; या

(ख) अपराध की उचित जांच के लिए; या

(ग)ऐसे व्यक्ति को अपराध के साक्ष्य को गायब करने या किसी भी तरह से ऐसे साक्ष्य के साथ छेड़छाड़ करने से रोकने के लिए: या

(घ)ऐसे व्यक्ति को मामले के तथ्यों से परिचित किसी व्यक्ति को कोई प्रलोभन, धमकी या वादा करने से रोकने के लिए ताकि उसे अदालत या पुलिस अधिकारी को ऐसे तथ्यों का खुलासा करने से मना किया जा सके: या

(ङ) आवश्यकता पड़ने पर न्यायालय में उसकी उपस्थिति सुनिश्चित करने के लिए की गई गिरफ्तारी और पुलिस अधिकारी ऐसी गिरफ्तारी करते समय अपने कारणों को लिखित रूप में दर्ज करेगा:

बशर्ते कि एक पुलिस अधिकारी उन सभी मामलों में जहां किसी व्यक्ति की गिरफ्तारी उसकी उपधारा के प्रावधानों के तहत आवश्यक नहीं है, गिरफ्तारी नहीं करने के कारणों को लिखित रूप में दर्ज करेगा;

7.1 उपर्युक्त उपबंध के सरल पठन से यह स्पष्ट है कि ऐसे अपराध के अभियुक्त व्यक्ति को, जो सात वर्ष से कम की अवधि के कारावास से दंडनीय है या जो जुर्माने सहित या जुर्माने के बिना सात वर्ष तक विस्तारित हो सकता है, पुलिस अधिकारी द्वारा केवल इस संतुष्टि पर गिरफ्तार नहीं किया जा सकता है कि ऐसे व्यक्ति ने यथापूर्वोक्त दंडनीय अपराध किया था। गिरफ्तारी से पहले ऐसे मामलों में किसी पुलिस अधिकारी को और संतुष्ट करना होगा कि ऐसी गिरफ्तारी ऐसे व्यक्ति को कोई और अपराध करने से रोकने के लिए आवश्यक है: या मामले की उचित जांच के लिए: या अभियुक्त को अपराध के साक्ष्यों को मिटाने या गायब करने से रोकने के लिए; या किसी भी तरह से ऐसे साक्ष्य के साथ छेड़छाड़ करने से रोकने के लिए; या ऐसे व्यक्ति को किसी गवाह को कोई प्रलोभन, धमकी या वादा करने से रोकने के लिए ताकि उसे अदालत या पुलिस अधिकारी को ऐसे तथ्यों का खुलासा करने से रोका जा सके: या जब

तक कि ऐसे अभियुक्त व्यक्ति को गिरफ्तार नहीं किया जाता है, तब तक जब भी आवश्यक हो अदालत में उसकी उपस्थिति सुनिश्चित नहीं की जा सकती है। ये निष्कर्ष हैं, जिन पर तथ्यों के आधार पर पहुंचा जा सकता है।

7.2 कानून पुलिस अधिकारी को ऐसी गिरफ्तारी करते समय तथ्यों को बताने और उन कारणों को लिखित रूप में अभिलिखित करने के लिए अधिदेशित करती है जिनके कारण वह उपर्युक्त उपबंधों में से किसी के अंतर्गत आने वाले निष्कर्ष पर पहुँचा। कानून में आगे पुलिस अधिकारियों को गिरफ्तारी नहीं करने के कारणों को लिखित रूप में दर्ज करने की आवश्यकता है "

5.7. यह सुनिश्चित करने के लिए कि अभियुक्तों को अनावश्यक रूप से गिरफ्तार नहीं किया जाता है और मजिस्ट्रेट आकस्मिक और यांत्रिक रूप से निरोध को अधिकृत नहीं करते हैं, माननीय सर्वोच्च न्यायालय ने निम्नलिखित निर्देश दिएः

"....
11.1 सभी राज्य सरकारों को अपने अपने संबंधित राज्य पुलिस अधिकारियों को यह निर्देश देने चाहिए कि भारतीय दंड सहिंता की धारा 498-क के तहत दर्ज मामलों में स्वत: गिरफ्तारी नहीं करें जब तक कि वे स्वंय यह सुनिश्चित नहीं कर लेते कि सीआरपीसी की धारा 41 के तहत स्थापित मानदण्डों को पूरा करने के लिए यह गिरफ्तारी आवश्यक हो।

11.2 सभी पुलिस अधिकारियों को धारा 41 (1) (ख) (ii) के निर्दिष्ट उपखंडों के साथ एक जांच सूची प्रदान की जाए।

11.3 पुलिस अधिकारी विधिवत फाइल की गई जाँच सूची को अग्रेषित करेगा और उन कारणों और सामग्रियों को प्रस्तुत करेगा जिनसे गिरफ्तारी की आवश्यकता हुई, जबकि अभियुक्त को मजिस्ट्रेट के समक्ष आगे की निरोध के लिए अग्रेषित/प्रस्तुत किया जाएगा;

11.4 मजिस्ट्रेट अभियुक्त के निरोध को प्राधिकृत करते समय पुलिस अधिकारी द्वारा दी गई रिपोर्ट को उपर्युक्त शर्तों में देखेगा और उसका समाधान दर्ज करने के पश्चात् ही मजिस्ट्रेट निरोध को प्राधिकृत करेगा;

11.5 अभियुक्त को गिरफ्तार नहीं करने के निर्णय को मजिस्ट्रेट को मामले की स्थापना की तारीख से दो सप्ताह के भीतर एक प्रति के साथ अग्रेषित किया जाए जिसे जिले के पुलिस अधीक्षक द्वारा लिखित रूप में अभिलिखित किए जाने वाले कारणों के लिए विस्तारित किया जा सके।

11.6 दंड प्रक्रिया संहिता की धारा 41क के संदर्भ में हाजिर होने की सूचना अभियुक्त को मामले की स्थापना की तारीख से दो सप्ताह के भीतर तामील की जाए, जिसे लिखित रूप में दर्ज किए जाने वाले कारणों के लिए जिले के पुलिस अधीक्षक द्वारा बढ़ाया जा सकता है;

11.7 उपर्युक्त निर्देशों का अनुपालन करने में विफलहोने पर संबंधित पुलिस अधिकारियों के विरुद्ध विभागीय कार्रवाई के अलावा, वे क्षेत्रीय अधिकारिता वाले उच्च न्यायालय के समक्ष स्थापित किए जाने वाले न्यायालय की अवमानना के लिए भी दंडित किए जा सकते हैं।

11.8 संबंधित न्यायिक मजिस्ट्रेट द्वारा उपरोक्त कारणों को अभिलिखित किए बिना निरोध को प्राधिकृत करने पर उपयुक्त उच्च न्यायालय द्वारा उक्त मजिस्ट्रेट के विरुद्ध विभागीय कार्रवाई कर सकता है।

5.8. न्यायालय ने ये भी जोड़ा

*·'...उपर्युक्त निर्देश **न केवल** आईपीसी की धारा 498-क या दहेज निषेध अधिनियम की धारा 4 के तहत मामलों पर कार्यान्वित होंगे, **बल्कि** ऐसे मामलों पर भी कार्यान्वित होंगे जहां अपराध एक अवधि के लिए कारावास सात वर्ष से कम या जो सात वर्ष तक बढ़ाया जा सकता है; चाहे जुर्माने के साथ या जुर्माने केबिना।" (जोर देते हुए कहा)*

(च) सतेंद्र कुमार अंतिल बनाम केंद्रीय अन्वेषण ब्यूरो और अन्य[45]

5.9. सतेंद्र कुमार अंतिल बनाम केंद्रीय जांच ब्यूरो और अन्य (2022)[46] के मामले में, माननीय सर्वोच्च न्यायालय ने सीआरपीसी के तहत गिरफ्तारी से संबंधित प्रावधानों को दोहराते हुए, संसद के आशयपर निम्नानुसार चर्चा की -

"20. दंड प्रक्रिया संहिता, एक प्रक्रियात्मक कानून होने के बावजूद, भारत के संविधान के अनुच्छेद 21 और 22 के तहत निहित अलंघनीय अधिकार पर अधिनियमित की गई है। शासन करने वाले प्रावधानों ने संसद के पूर्व में उल्लिखित इरादे को स्पष्ट रूप से प्रदर्शित किया।

21. हालांकि 'जमानत' शब्द को उपरोक्त के रूप में परिभाषित नहीं किया गया है, धारा 2 क एक जमानती और गैर-जमानती अपराध को परिभाषित करती है। गैर-जमानती अपराध एक संज्ञेय अपराध है जो पुलिस अधिकारी को वारंट के बिना गिरफ्तार करने की शक्ति प्रदान करती। उक्त शक्ति का प्रयोग करना संहिता प्रतिबंधों के माध्यम से कुछ प्रतिबंधों का प्रावधान करती है।

"24. यह प्रावधान पुलिस अधिकारी को गिरफ्तारी करते समय अपने कारणों को लिखित रूप में दर्ज करने के लिए अनिवार्य करता है। इस प्रकार, एक पुलिस अधिकारी गिरफ्तारी के कारणों को लिखित रूप में दर्ज करने के लिए बाध्य है। इसी तरह, पुलिस अधिकारी उन कारणों कोदर्ज करेगा जब वह गिरफ्तारी नहीं करने का विकल्प चुनता है। उपरोक्त प्रक्रिया की कोई आवश्यकता नहीं है जब कथित अपराध अन्य कारणों के अलावा सात वर्ष से अधिक का हो।

5.10 धारा 41 और 41क के दायरे और उद्देश्य पर, माननीय उच्चतम न्यायालय ने अभिनिर्धारित किया कि वे स्पष्ट रूप से संविधान के अनुच्छेद 21 के पहलू हैं और **अर्नेश कुमार बनाम बिहार राज्य**[47] में

---

[45] (2022) 10 एससीसी 51

[46] पूर्वोक्त

[47] (2014) 8 एससीसी 273

अपने निर्णय को दोहराया और अभिनिर्धारित किया कि उपरोक्त मामले में दिए गए निर्देशों का जांच और अभियोजन एजेंसियों द्वारा अक्षरशः अनुपालन किया जाना चाहिए और यह कि,

> *"...उपर्युक्त निर्देश न केवल आईपीसी की धारा 498-क या दहेज निषेध अधिनियम की धारा 4 के तहत मामलों पर कार्यान्वित होंगे, बल्कि ऐसे मामलों पर भी कार्यान्वित होंगे जहां अपराध के लिए कारावास की अवधि सात साल से कम या जिसे सात साल तक बढ़ाया जा सकता है, का प्रावधान है, चाहे जुर्माने के साथ या उसके बिना।"*

6. निष्कर्ष

6.1 पुलिस (रेलवे पुलिस और ग्राम पुलिस सहित) सूची I (संघ सूची) की प्रविष्टि 2क के प्रावधानों के अधीन भारत के संविधान की सातवीं अनुसूची की सूची-II (राज्य सूची) की प्रविष्टि 2 के अंतर्गत आती है।[48] पुलिस, जो सरकार के प्रशासनिक तंत्र का एक हिस्सा है, वह कानून व्यवश्था को बनाए रखने, अपराधों को रोकने, पता लगाने और जांच करने और सार्वजनिक सुरक्षा और व्यवस्था बनाए रखने के लिए जिम्मेदार है।[49]

6.2 महत्वपूर्ण कानून और प्रक्रियात्मक कानून एक सहजीवी संबंध साझा करते हैं। मूल कानून के उचित कार्यान्वयन के लिए एक प्रभावी प्रक्रियात्मक शासन आवश्यक है, एक अच्छी तरह से निर्धारित प्रक्रियात्मक कानून के माध्यम से, महत्वपूर्ण कानून को नागरिकों के लिए प्रासंगिक, सार्थक और सुलभ बनाया जाता है।

6.3 अधिकांश आयोगों और समितियों द्वारा कार्यालय के दुरुपयोग और एफआईआर दर्ज न करने के लिए भ्रष्टाचार से उत्पन्न शिकायतों पर प्रकाश डाला गया है और उनके द्वारा समय-समय पर विभिन्न सुझाव दिए गए हैं ताकि पुलिस द्वारा सभी एफआईआर दर्ज की जाएं और सार्वजनिक शिकायतों का पर्याप्त रूप से समाधान किया जा सके। हालाँकि, संज्ञेय मामलों में भी एफआईआर का पंजीकरण न होने की समस्या आज भी जनता द्वारा अनुभव की जाती है और यह जघन्य अपराधों से जुड़े मामलों के निपटान में देरी के मुख्य कारणों में से एक है।

6.4 डिजिटल प्रौद्योगिकी के आगमन ने कागज-आधारित दस्तावेजों की भूमिका को कम कर दिया है और इस तरह देश के प्रक्रियात्मक कानूनों में बदलाव करने की आवश्यकता उत्पन्न हो गई है। दंड प्रक्रिया संहिता, 1973 के तहत प्रथम इत्तिला रिपोर्ट दर्ज करने का कोई प्रावधान नहीं है। हालांकि, आठ राज्यों[50] (दिल्ली, गुजरात, कर्नाटक, मध्य प्रदेश, ओडिशा, राजस्थान, उत्तर प्रदेश और उत्तराखंड) ने प्रथम इत्तिला रिपोर्ट दर्ज करने के लिए एक तंत्र विकसित किया है। वर्तमान में, ये ऑनलाइन पोर्टल वाहन या संपत्ति की चोरी के लिए, खोए हुए सामान जैसे बटुआ/पर्स, पैन कार्ड, पासपोर्ट, स्कूल या कॉलेज मार्कशीट या डिग्री जैसे महत्वपूर्ण दस्तावेज, आधार कार्ड, ड्राइविंग लाइसेंस आदिके लिए ई-एफआईआर के पंजीकरण की सुविधा प्रदान करते हैं। सुप्रीम कोर्ट के निर्देश के अनुसार पुलिस वेबसाइट पर एफआईआर भी अपलोड की जा रही है। निम्नलिखित तालिका उन अपराधों को सूचीबद्ध करती है जिनके लिए उपर्युक्त आठ राज्यों में ई-एफआईआर दर्ज की जा रही हैः

[48] भारत का संविधान, प्रविष्टि 2, सूची II, अनुसूची VII

[49] डिजिटलीकरण, हिताची के माध्यम से पुलिस के कामकाज में परिवर्तन को सक्षम करना, https://social-innovation.hitachi/en-in/knowlcdge-hub/collaborate/transformation-or-po1ice/पर उपलब्ध है (अन्तिम बार 13 जुलाई 2023को देखा गया).

[50] पत्र सं. 32/31/2022-आरडी (ई-14061) ब्यूरो ऑफ पुलिस रिसर्च एंड डेवलपमेंट से दिनांक 22 मई, 2023को प्राप्त हुआ।)

अपराधों की सूची जिनके लिए निम्नलिखित 8 राज्यों में ई-एफआईआर का पंजीकरण किया जा रहा है।

क्र.सं.	राज्य	अपराधों की सूची
I.	दिल्ली[51]	1. संपत्ति चोरी के मामले 2. मोटर वाहन चोरी के मामले
2.	गुजरात[52]	1. मोबाईल चोरी 2. वाहन चोरी
3.	कर्नाटक[53]	चोरी के वाहनों की रिपोर्ट करने के लिए ई-एफआईआर
4.	मध्य प्रदेश[54]	15 लाख तक की वाहन चोरी या एक लाख तक की सामान्य चोरी के मामलों में ई-एफआईआर।
5.	ओडिसा[55]	नागरिक निम्नलिखित परिस्थितियों में मोटर वाहन चोरी के मामलों के लिए इलेक्ट्रॉनिक रूप से प्रथम इत्तिला रिपोर्ट दर्ज कर सकते हैंः (i) अज्ञात अभियुक्त ii) अपराध में वाहन का शामिल नहीं होना (वाहन किसी भी अपराध में शामिल नहीं होना चाहिए। शिकायत अनिवार्य स्व-प्रमाणन देगी कि ई-एफआईआर दर्ज करने के समय वाहन किसी भी अपराध में शामिल नहीं है) iii) अखोजे गए वाहन (ई-एफआईआर दर्ज होने तक वाहन बरामद नहीं होना चाहिए। शिकायतकर्ता इस आशय का अनिवार्य स्वप्रमाणन देगा। वाहन/सारथी आवेदनों से वाहन की जानकारी के सत्यापन का प्रावधान होगा)। iv)वाहन से किसी भी प्रकार की कोई दुर्घटना अथवाकोई हानि या चोट नहीं लगी है।
6.	राजस्थान[56]	केवल वाहन चोरी के मामले
7.	उत्तर प्रदेश[57]	ई-एफआईआर की सुविधा केवल अज्ञात आरोपी के मामलों के लिए उपलब्ध है।
8.	उत्तराखडं[58]	ई-एफआईआर की सुविधा केवल अज्ञात आरोपी के मामलों के लिए उपलब्ध है।

[51] दिल्ली पुलिस, भारत, https://delhipolice.gov.in/viewfir पर उपलब्ध है (अंतिम बार 13 सितंबर, 2023 को देखा गया था)

[52] गुजरात पुलिस, भारत, https://gujhome.gujarat.gov.in/portal/पर उपलब्ध है। (अंतिम बार 13 सितंबर, 2023 को देखा गया था)।

[53] कर्नाटक पुलिस, भारत, https://ksp.karnataka.gov.in/पर उपलब्ध है (अंतिम बार 13 सितंबर, 2023 को देखा गया था)।

[54] जनसंपर्क विभाग, मध्य प्रदेश सरकार, भारत, यहां उपलब्ध हैः https://www.mpinfo.org/Home/TodaySNews?newsid=20211008N92 & fontname = \FontEnglish & LoclD = 32 & pubdate = 10/08/2021 (अंतिम बार 13 सितंबर, 2023 को देखा गया था)।

[55] ओडिशा पुलिस, भारत, https://citizenportal-op.gov.in/citizen/aboutcomplaint. aspx पर उपलब्ध है।(अंतिम बार 13 सितंबर, 2023 को देखा गया था)।

[56] राजस्थान पुलिस, भारत, https://police.rajasthan.gov.in/citizen/indexcitizen.htm पर उपलब्ध है (अंतिम बार 14 सितम्बर, 2023 को देखा गया)

[57] उत्तर प्रदेश पुलिस, भारत, https://uppolicc.gov.in/#Find% 20Your% 20police% 20Station पर उपलब्ध है ((अंतिम बार 13 सितम्बर, 2023 को देखा गया)

[58] उत्तराखंड पुलिस, भारत https://policecitizenportal.uk.gov.in/efir/Login.aspx पर उपलब्ध है (अंतिम बार 13 सितंबर, 2023 को देखा गया) 59 भारत का विधि आयोग की त्वरित जांच और परीक्षण या प्रभावशाली सार्वजनिक व्यक्तियों के खिलाफ आपराधिक मामलों पर 239वीं रिपोर्ट। (31 मार्च 2012)

6.5. भारत ने केंद्रीकृत लोक शिकायत निवारण और निगरानी प्रणाली, ऑनलाइन आर. टी. आई. पोर्टल और ई-पासपोर्ट सेवाओं आदि जैसी कई ऑनलाइन सेवाओं को सफलतापूर्वक कार्यान्वित किया है। इसने न केवल आधुनिक प्रौद्योगिकी के उत्कृष्ट उपयोग और अर्थव्यवस्था के डिजिटलीकरण का प्रदर्शन किया है, बल्कि नागरिकों के लिए अधिक पारदर्शिता और बेहतर सुविधा भी सुनिश्चित की है।

6.6 सूचना प्रौद्योगिकी अधिनियम, 2000 में डिजिटल हस्ताक्षरों की कानूनी मान्यता और प्रमाणीकरण, आरोपण, पावती, इलेक्ट्रॉनिक अभिलेखों के प्रेषण और सुरक्षा, प्रमाणन प्राधिकरणों के विनियमन आदि पर प्रावधान शामिल हैं। भारतीय दंड संहिता, 1860 और भारतीय साक्ष्य अधिनियम आदि के प्रासंगिक प्रावधानों को वर्ष 2000 के इस अधिनियम द्वारा संशोधित किया गया है।

6.7 भारत के विधि आयोग ने अपनी 239वीं रिपोर्ट[59] में "प्रभावशाली लोक व्यक्तियों के विरुद्ध आपराधिक मामलों की त्वरित जांच और विचारण" शीर्षक से यह प्रस्ताव किया है किः
एफ. आई. आर. कंप्यूटर पर दर्ज की जाएगी और उन्हें तुरंत ई-मेल द्वारा मजिस्ट्रेट की अदालतों में भेजा जाएगा। ई-मेल के माध्यम से एफ. आई. आर. भेजने की प्रथा को कानूनी रूप से मान्यता दी जानी चाहिए।

6.8 आयोग ने सभी न्यायालयों के साथ संबंध स्थापित करने के लिए सभी पुलिस थानों की नेटवर्किंग का भी प्रस्ताव किया।

6.9 *यूथ बार एसोसिएशन ऑफ इंडिया बनाम भारत संघ*[60] मामले में उच्चतम न्यायालय ने 15 नवंबर, 2016 से सभी राज्यों की वेबसाइट पर प्रथम इत्तिला रिपोर्ट (जब तक कि अपराध प्रकृति में संवेदनशील न हो, जैसे यौन अपराध, उग्रवाद से संबंधित अपराध, आतंकवाद, पॉक्सो अधिनियम के तहत अपराध और ऐसे अन्य अपराध) अपलोड करने का निर्देश दिया।

6.10 न्यायमूर्ति जे. एस. वर्मा[61] की अध्यक्षता में दंड विधि में संशोधन संबंधी समिति की रिपोर्ट में सिफारिश की गई थी किः

> *(ग) प्रत्येक व्यक्ति को किसी भी पुलिस स्टेशन में प्रथम इत्तिला रिपोर्ट दर्ज करने में सक्षम होने केअलावा, उस अधिकार क्षेत्र के बावजूद जिसमें अपराध की लिखित में शिकायत की गई थी, प्रत्येक व्यक्ति को एक निर्दिष्ट वेबसाइट पर अपनी शिकायत ऑनलाइन दर्ज करने में भी सक्षम होना चाहिए। इसके बाद एक शिकायत संख्या स्वचालित रूप से जेनरेट हो जानी चाहिए ताकि शिकायतकर्ता एफआईआर को ट्रैक कर सके।*

---

[59] भारतीय विधि आयोग, "प्रभावशाली सार्वजनिक हस्तियों के खिलाफ आपराधिक मामलों की शीघ्र जांच और परीक्षण पर 239वीं रिपोर्ट" 3। मार्च 2012)।

[60] यूथ बार एसोसिएशन बनाम यूनियन ऑफ इंडिया एआईआर 2016 एससी 4136।

[61] भारत सरकार "आपराधिक कानून में संशोधन पर समिति की रिपोर्ट 355-356 (भारत सरकार 23 जनवरी, 2013).

वही शिकायत तब निकटतम पुलिस स्टेशन में दर्ज की जाएगी और इसकी एक प्रति प्रत्येक जिले में स्थित लोकपाल कार्यालय को प्रदान की जाएगी। यह ध्यान दिया जाना चाहिए कि एक प्रथम इत्तिला रिपोर्ट गुमनाम रूप से दर्ज नहीं की जा सकती है और जिस व्यक्ति ने ऑनलाइन प्रथम इत्तिला रिपोर्ट दर्ज की है, उसे अपनी पहचान और प्रथम इत्तिला रिपोर्ट को सत्यापित करने के लिए किसी भी पुलिस स्टेशन जाना होगा। दिल्ली पुलिस के पास पहले से ही ऑनलाइन पंजीकरण और एफआईआर पर निगरानी रखने की सुविधा है। इस प्रकृति के कुछ को दोहराया जाना चाहिए और पूरे देश में शुरु किया जाना चाहिए। शिकायतकर्ता की आसानी के लिए राष्ट्रीय ऑनलाइन डेटाबेस पर भी प्रथम इत्तिला रिपोर्ट दर्ज की जानी चाहिए।

6.11 प्रौद्योगिकी में प्रगति, न्याय और कानून प्रवर्तन प्रणालियों के विकास के कारण, पुलिसिंग एक बड़े परिवर्तन से गुजर रही है। भारत इंटरनेट का उपयोग करने वाली दूसरी सबसे बड़ी आबादी होने के नाते कोई अपवाद नहीं है।[62] और जैसे-जैसे प्रौद्योगिकी दैनिक जीवन में प्रवेश कर रही है, पुलिस प्रणाली कानून प्रवर्तन और कानूनी प्रणाली की बदलती प्रकृति के साथ तालमेल रखने के लिए अत्याधुनिक तकनीकों के लिए तेजी से अनुकूल हो रही है। जैसे-जैसे डिजिटल इंडिया प्रगति कर रहा है, पारंपरिक प्रशासनिक और शासन संरचनाओं को आईसीटी-संचालित ई-शासन प्रतिमान द्वारा प्रतिस्थापित किया जा रहा है। आई. टी. और डिजिटल प्रौद्योगिकियां पुलिसिंग, संचालन के आधुनिकीकरण और पुलिस सेवाओं की उपलब्धता, प्रभावकारिता और गुणवत्ता में सुधार के लिए अधिक से अधिक एकीकृत हो रही हैं। सूचना और संचार प्रौद्योगिकी (आई. सी. टी.) का उपयोग पहले से ही विभिन्न स्तरों पर पुलिस अभियानों में किया जा रहा है। पुलिस बल के आधुनिकीकरण के प्रयास में, गृह मंत्रालय ने वर्ष 2009 के दौरान भारत सरकार की पहल राष्ट्रीय ई-शासन योजना (एनईजीपी) के तहत एकमिशन मोड परियोजना के रूप में अपराध और आपराधिक ट्रैकिंग नेटवर्क और सिस्टम (सीसीटीएनएस) परियोजना की अवधारणा की। इसने पुलिस के आधुनिकीकरण पर ध्यान केंद्रित किया ताकि अपराध की जांच, आपराधिक पहचान, सूचना एकत्र करने और देश भर में विभिन्न पुलिस संगठनों और इकाइयों में इसके प्रसार और नागरिकों के लिए सेवाओं को बढ़ाया जा सके।[63]

6.12 भारत सरकार का डिजिटल इंडिया कार्यक्रम भारत को एक डिजिटल रूप से सशक्त समाज और ज्ञान अर्थव्यवस्था में बदलने की दृष्टि से शुरू किया गया है जिसमें अपराध और आपराधिक ट्रैकिंग नेटवर्क और सिस्टम (सीसीटीएनएस) शामिल हैं। देश भर में विभिन्न स्तरों पर ई-गवर्नेंस परियोजनाओं के कार्यान्वयन को सुविधाजनक बनाने के लिए ई-एफआईआर का पंजीकरण सबसे महत्वपूर्ण कदमों में से एक होगा। पारदर्शिता में सुधार के अलावा, यह नागरिकों और पुलिस के लिए समान रूप से समग्र दक्षता और सुविधा में सुधार करेगा। ई-एफ. आई. आर. के पंजीकरण द्वारा सुरक्षित डेटा तैयार किया जाएगा और परीक्षण के दौरान साक्ष्य पर बेहतर रुप से निगरानी की जा सकेगी।

6.13 दंड प्रक्रिया संहिता की धारा 154 का उसके अप्रचलित रूप में कार्यान्वयन न केवल संभव है अपितु वांछनीय भी है। एफआईआर के पंजीकरण की प्रक्रिया को जानकारी प्रदान करने के कई तरीकों की

[62] संजय माथुर और डॉ. प्रसून गुप्ता का "साइट्रेनः साइबर क्राइम ट्रेनिंग पोर्टल विद सिमुलेटेड लर्निंग" आईएनसीआरबी जर्नल 1-10 (नवम्बर, 2022).

[63] डॉ. प्रसून गुप्ता और नरेंद्र कुमार कोली "", प्रोजेक्ट मैनेजमेंट ऑफ सीसीटीएनएस "। एनसीआरबी जर्नल 76-84 (नवम्बर, 2022).

अनुमति देकर सरल बनाया जा सकता है। भारत के अधिकांश राज्यों ने नागरिकों को शिकायत दर्ज कराने के लिए ऑनलाइन पोर्टल उपलब्ध कराए हैं। सभी शिकायतों की जांच की जाती है और अंतिम रिपोर्ट तैयार की जाती है। ई-एफआईआर पंजीकृत करने के लिए उसी या इसी तरह की प्रणाली का उपयोग किया जा सकता है। भारत सरकार पहले ही सभी राज्यों को सीसीटीएनएस सुविधाएं प्रदान कर चुकी है। अधिकांश स्थानों पर पर्याप्त हार्डवेयर और सॉफ्टवेयर पहले ही प्रदान किए जा चुके हैं। ई-एफआईआर के मुफ्त पंजीकरण को बढ़ावा देने के लिए इन सुविधाओं के उपयोग से दांडिक न्याय प्रक्रिया को वैधता मिलेगी और कानून में आम आदमी का विश्वास बढ़ेगा। जब तक नागरिकों को दांडिक न्याय प्रणाली तक निर्बाध और समान पहुंच की अनुमति नहीं दी जाती है, जिसके लिए प्रथम इत्तिला रिपोर्ट दर्ज करना पहला कदम है, कानून के समक्ष समानता या कानून का समान संरक्षण नहीं हो सकता है, जैसा कि भारत के संविधान के अनुच्छेद14[64] में कल्पना की गई है।

6.14 वर्तमान में, बीपीआरएंडडी और एनसीआरबी के साथ पत्राचार के अनुसार, देश भर के राज्य और केंद्र शासित प्रदेश किरायेदारों, घरेलू सहायक और कर्मचारियों के सत्यापन, चरित्र प्रमाण पत्र जारी करने आदि जैसे 09 क्षेत्रों में ऑनलाइन सेवाएं प्रदान कर रहे हैं। हालांकि, केवल 08 राज्य ई-एफआईआर पंजीकृत कर रहे हैं। सभी सीसीटीएनएस पोर्टलों से डेटा संबंधित राज्य डेटा सेवा केंद्रों में संग्रहीत किया जाता है। सीसीटीएनएस से इंटरऑपरेबल क्रिमिनल जस्टिस सिस्टम (आईसीजेएस) की तैनाती में भी मदद मिलने की उम्मीद थी, जिसका उद्देश्य सीसीटीएनएस के तहत पुलिस डेटा को जेल डेटा, अभियोजन, फोरेंसिक और अदालतों के साथ एकीकृत करना था। सीसीटीएनएस की अवधारणा पुलिस के काम को स्वचालित करने के लिए की गई थी। यह पुलिस थानों में रिपोर्ट किए गए अपराध से संबंधित डेटा की प्रविष्टि की सुविधा प्रदान करता है जिसमें अपराध स्थल, शामिल आरोपी, जब्त की गई संपत्ति और अदालत में दायर अंतिम रिपोर्ट का विवरण शामिल है। यह व्यक्तियों और सम्पतियों के संबंध में एक खोज सुविधा भी प्रदान करता है, जो जांच प्रक्रिया को आसान और तेज बनाता है। एनसीआरबी को मुख्य हितधारकों में से एक के रूप में राष्ट्रीय स्तर पर इस परियोजना की निगरानी और समन्वय का काम सौंपा गया था।

6.15 डेटा का डिजिटलीकरण सिस्टम में सभी हितधारकों तक पहुंच सुनिश्चित करता है जैसे अदालतें, परिवहन प्राधिकरण, अस्पताल, नगरपालिका प्राधिकरणआदि। यह सार्वजनिक व्यवस्था और अपराध नियंत्रण की चुनौतियों का अधिक प्रभावी ढंग से समाधान करने में सहायक है। महत्वपूर्ण रूप से, सी. सी. टी. एन. एस. का कार्यान्वयन एकीकृत सेवा वितरण पर निर्भर करता है। नागरिक-पुलिस इंटरफेस को मजबूत करना इस आधार के साथ इस ओर मजबूती से संकेत देता है। प्रगति डैशबोर्ड (एनसीआरबी द्वारा प्रदान किए गए) के मई, 2023 तक के नवीनतम आंकड़ों के अनुसार यह देखा जा सकता है कि पुलिस स्टेशन में नेटवर्क कनेक्टिविटी में सुधार हुआ है और लगभग 99% पुलिस स्टेशनों में सीसीटीएनएस सॉफ्टवेयर उपलब्ध हैं।

[64] हनीफ कुरैशी, "क्या भारत ऑनलाइन एफआईआर के लिए तैयार है" 65 इंडियन पुलिस जर्नल 73-80 (2018) https://papers.ssrn.com/sol3/papers.cfm?abstract_id=3651230 पर उपलब्ध है (अंतिम बार 13 जुलाई 2023 को देखा गया)

6.16 उन क्षेत्रों में जहां सुरक्षा या अन्य अवसंरचनात्मक समस्याओं के कारण पुलिस स्टेशन का दौरा करना संभव नहीं हो सकता है, ई-एफआईआर दर्ज करना एक वरदान साबित हो सकता है। इसके अलावा, ई-एफआईआर दाखिल करने से पुलिस अधिकारियों द्वारा छोटे अपराधों के मामलों में एफआईआर दर्ज करने के लिए दिखाई गई अनिच्छा को नियंत्रित करने में सहायता मिलेगी। इसके अलावा, यह कम पुलिस और सार्वजनिक अनुपात के परिणामस्वरूप होने वाली कठिनाइयों को दूर करेगा।

6.17 पुलिस स्टेशनों के स्तर पर प्रक्रियाओं और कार्यों को स्वचालित करके और सूचना और संचार प्रौद्योगिकी (आईसीटी) के प्रभावी उपयोग के माध्यम से नागरिक केंद्रित सेवाओं के वितरण में सुधार करके अंतिम लक्ष्य पुलिस के कामकाज को नागरिक के अनुकूल, पारदर्शी, जवाबदेह, प्रभावी और कुशल बनाना है।

7. अनुशंसाएं

क. उन सभी संज्ञेय अपराधों के लिए ई-एफआईआर के पंजीकरण की अनुमति दी जाए जहां आरोपी ज्ञात नहीं है।

7.1. भारत के प्रगतिशील डिजिटल इंडिया मिशन और राष्ट्रीय ई-शासन योजना के अनुरूप, आयोग ने सिफारिश की है कि ऐसे मामलों में जहां आरोपी अज्ञात है, दंड प्रक्रिया संहिता, 1973 की धारा 154 के अनुसार सभी संज्ञेय अपराधों के लिए ई-एफआईआर के पंजीकरण की अनुमति दी जानी चाहिए।

ख. जिन संज्ञेय अपराधों में अधिकतम सजा की सीमा 03 वर्ष है और आरोपी ज्ञात है, उन मामलों में ई-एफआईआर के पंजीकरण की अनुमति दी जानी चाहिए।

7.2. आयोग आगे यह भी सिफारिश करता है कि जहां अभियुक्त को प्रारंभिक स्तर पर ही पहचाना जाता है, वहां सभी संज्ञेय अपराधों के लिए ई-एफआईआर के पंजीकरण की अनुमति दी जा सकती है, जिसमें भारतीय दंड संहिता, 1860 और अन्य कानूनों के तहत निर्धारित सजा तीन साल तक है। प्रारंभिक चरण में ई-एफआईआर योजना के इस तरह के सीमित क्रियान्वयन से यह सुनिश्चित होगा कि फिलहाल गंभीर अपराधों की रिपोर्टिंग और जांच के लिए अपनाई गई प्रक्रिया से संबंधित कोई व्यवधान न हो।

7.3. सतेंद्र कुमार अंतिल बनाम केन्द्रीय अन्वेषण ब्यूरो (2022)[65] में माननीय उच्चतम न्यायालय ने अभियुक्त की निर्दोषता की धारणा पर बल दिया और कहा

> *'... 14 निर्दोषता की धारणा को दुनिया भर में स्वीकार किया गया है। नागरिक और राजनीतिक अधिकारों पर अंतर्राष्ट्रीय प्रसंविदा, 1966 का अनुच्छेद 14(2) और मानवाधिकारों की सार्वभौमिक घोषणा का अनुच्छेद 11 कानून के एक प्रमुख सिद्धांत के रूप में निर्दोषता की धारणा को तब तक स्वीकार करता है, जब तक कि व्यक्ति दोषी साबित नहीं हो जाता।*

7.4. इसके अलावा, अर्नेश कुमार बनाम बिहार राज्य[66] में सर्वोच्च न्यायालय ने गिरफ्तारी की शक्ति के प्रयोग पर विस्तृत निर्देश जारी किए थे और कहा था कि चूंकि गिरफ्तारी के कारण व्यक्ति को समाज में अपमान झेलना पडता है, स्वतंत्रता को कम करती है और हमेशा के लिए एक गहरा धब्बा छोडती है, इसलिए कोई गिरफ्तारी केवल इसलिए नहीं की जानी चाहिए क्योंकि अपराध गैर-जमानती और संज्ञेय है और किसी व्यक्ति के खिलाफ किए गए अपराध के आरोप के आधार पर नियमित तरीके से भी नहीं की जा सकती है। एक पुलिस अधिकारी के लिए यह विवेकपूर्ण और बुद्धिमानी होगी कि आरोप की वास्तविकता के बारे में कुछ जांच के बाद उचित संतुष्टि के बिना कोई गिरफ्तारी नहीं की जाए। अदालत ने यह भी स्पष्ट किया कि इस मामले में दिए गए निर्देश केवल भारतीय दण्ड संहिता की धारा 498-कया दहेज निषेध अधिनियम की धारा 4 के तहत मामलों पर कार्यान्वित नहीं होंगे, उपरोक्त मामलों में,लेकिन यह ऐसे मामलों पर भी कार्यान्वित नहीं होगा जिन

[65] (2022) 10 एससीसी 51

[66] (2014) 8 एससीसी 273.

मामलों मे अधिकतम सजा का प्रावधना 07 वर्ष या 07वर्ष तक चाहे जुर्माने के साथ या जुर्माने के बिना बढाया जा सकता है।

7.5 उपर्युक्त निर्णयों के अनुसार, गिरफ्तारी करते समय सख्त दिशानिर्देशों का पालन किया जाना चाहिए जहां अपराध में अधिकतम सजा सात साल या सात सालजुर्माने के साथ या बिना तक बढ़ाई जा सकती है; इसलिए, सभी संज्ञेय अपराधों के लिए ई-एफआईआर के पंजीकरण की इस योजना को कार्यान्वित करना, जिसमें भारतीय दंड संहिता, 1860 और फिलहाल कार्यान्वित अन्य कानूनों के तहत निर्धारित सजा तीन साल तक है, किसी भी दुरुपयोग के मामलों में आरोपी को गिरफ्तारी से भी बचाएगा क्योंकि पुलिस उक्त दिशानिर्देशों का पालन करने के लिए कर्तव्यबद्ध है।

7.6 इसके अतिरिक्त, भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता, 2023[67] के खंड 283 के उपखंड (2) के अनुसार, मजिस्ट्रेटों को उन सभी या किसी भी अपराध का संक्षिप्त तरीके से मुकदमा चलाने का अधिकार दिया गया है जो मौत या आजीवन कारावास या तीन साल से अधिक की अवधि के कारावास से दंडनीय नहीं हैं (वर्तमान में यह दंड प्रक्रिया संहिता की धारा 260 के तहत दो वर्ष से अधिक की अवधि के लिए मृत्युदंड, आजीवन कारावास या कारावास से दंडनीय अपराधों के लिए अनुमत है।) इसलिए, अभियुक्त को किसी भी दुरुपयोग से बचाने के लिए, इस अनुशंसित योजना को चरणबद्ध तरीके से कार्यान्वित किया जा सकता है और शुरू में उन सभी संज्ञेय अपराधों के लिए कार्यान्वित किया जा सकता है जिनमें भारतीय दंड संहिता, 1860 और अन्य कानूनों के तहत निर्धारित सजा तीन साल तक है।

ग. राज्यों को अपराधों की सूची का विस्तार करने की शक्ति होगी

7.7 उपरोक्त के अलावा, आयोग ने सिफारिश की है कि राज्य उन अपराधों की सूची का विस्तार कर सकते हैं जिनके लिए भविष्य में ई-एफ. आई. आर. पंजीकृत किया जा सकता है, यदि ई-एफ. आई. आर. के पंजीकरण का कार्य प्रभावी होता है।

घ. ई-एफआईआर के पंजीकरण की अनुमति सभी अपराधों के लिए नहीं दी जानी चाहिए।

7.8 ई-एफआईआर के पंजीकरण की वर्तमान योजना को निम्नलिखित कारणों से सभी मामलों में अनुमति नहीं दी जा सकती हैः

1. भारत के *माननीय सर्वोच्च न्यायालय ने लोलिता कुमारी बनाम उत्तर प्रदेश सरकार*[68] के ऐतिहासिक निर्णय में, एफआईआर के पंजीकरण से पहले प्रारंभिक जांच की अनुमति देते हुए, यह अभिनिर्धारित किया है;

[67] बिल नं. 2023 का 123।

[68] (2014) 2 एससीसी 1

v. प्रारंभिक जांच का दायरा प्राप्त जानकारी की सत्यता या अन्यथा को सत्यापित करना नहीं है, बल्कि केवल यह पता लगाने के लिए है कि क्या जानकारी किसी संज्ञेय अपराध का खुलासा करती है।

vi. किस प्रकार और किन मामलों में प्रारंभिक जांच की जानी है, यह प्रत्येक मामले के तथ्यों और परिस्थितियों पर निर्भर करेगा। जिन मामलों में प्रारंभिक जांच की जा सकती है, उनकी श्रेणी इस प्रकार हैः

क. वैवाहिक संबंध/पारिवारिक विवाद

ख. व्यावसायिक अपराध

ग. चिकित्सकीय लापरवाही के मामले

घ. भ्रष्टाचार के मामले

ड़. ऐसे मामले जहां आपराधिक अभियोजन शुरू करने में असामान्य देरी/अड़चनें हैं। उदाहरण के लिए, देरी के कारणों को संतोषजनक रूप से बताए बिना मामले को फिर से खोलने में तीन महीने से अधिक की देरी करना।

उपर्युक्त केवल दृष्टांत हैं और उन सभी शर्तों का संपूर्ण विवरण नहीं है जो प्रारंभिक जांच की आवश्यकता हो सकती हैं।

vii. अभियुक्त और शिकायतकर्ता के अधिकारों को सुनिश्चित करते हुए और उनकी रक्षा करते हुए, प्रारंभिक जांच समयबद्ध की जानी चाहिए और किसी भी मामले में यह 7 दिनों से अधिक नहीं होनी चाहिए। इस तरह की देरी का तथ्य और इसके कारण सामान्य डायरी प्रविष्टि में परिलक्षित होने चाहिए।

7.9. इसके अलावा, ऐसा भी हो सकता है कि आम आदमी इन कानूनी पेचीदगियों से अवगत नहीं हो और सभी मामलों में ई-एफ. आई. आर. के माध्यम से एफ. आई. आर. के पंजीकरण की अनुमति देने से उपयुक्त मामलों में प्रारंभिक जांच करने की अपनी शक्ति को कम करने के अलावा पुलिस पर अत्यधिक जांच का बोझ बढ जाएगा जैसा कि माननीय सर्वोच्च न्यायालय ने अपने स्पष्ट आदेश में इसे आवश्यक बताया है।

ड़. सभी गैर-संज्ञेय अपराधों के लिए ई-शिकायत की अनुमति दी जाए

7.10 दंड प्रक्रिया संहिता, 1973 की धारा 155 के अनुसार सभी गैर-संज्ञेय अपराधों के लिए ई-शिकायत के पंजीकरण की अनुमति दी जानी चाहिए, जैसा कि वर्तमान में सभी राज्यों/केंद्र शासित प्रदेशों में किया जा रहा है।

च. सूचना देने वाले/शिकायतकर्ता का सत्यापन और असत्य जानकारी के लिए सजा।

7.11 ई-शिकायतों/ई-एफआईआर के झूठे पंजीकरण से बचने और सुविधा के रचनात्मक उपयोग के लिए, यह महत्वपूर्ण है कि शिकायतकर्ता या मुखबिर का सत्यापन ई-प्रमाणीकरण तकनीकों का उपयोग करके किया जाए। इसे ई-एफआईआर/ई-शिकायत दर्ज करने के उद्देश्य से ओटीपी के माध्यम से

मोबाइल नंबर सत्यापित करके और आधार या किसी अन्य सरकार द्वारा अनुमोदित पहचान पत्र जैसे वैध पहचान पत्र के प्रमाण को अपलोड करना अनिवार्य करके सुनिश्चित किया जा सकता है।

7.12 सूचना देने वाले द्वारा घोषणा कि ई-एफ. आई. आर. में निहित तथ्य सूचना देने वाले के सर्वोत्तम ज्ञान, जानकारी और विश्वास के लिए सही हैं, को अनिवार्य बनाया जाना चाहिए।

(यह प्रियंका श्रीवास्तव बनाम उत्तर प्रदेश सरकार के मामले में दिए गए निर्णय के अनुरुप भी है।)[69]

7.13 ई-शिकायत या ई-एफआईआर दर्ज करवाने पर न्यूनतम सजा का भी प्रावधान किया जाना चाहिए। भारतीय दण्ड संहिता, 1860 की धारा 182 में संशोधन करके ऐसा किया जा सकता है जैसे

> *"... ऐसे व्यक्ति को अधिकतम दो वर्ष तक के कारावास या अधिकतम दस हजार रुपये तक के जुर्माने या दोनों से दण्डित किया जा सकता है।"*

छ. पक्षों की गोपनीयता सुनिश्चित की जानी चाहिए

7.14 यह सुनिश्चित किया जाना चाहिए कि ऑनलाइन एफआईआर दर्ज करते समय प्रदान किए गए डेटा से समझौता नहीं किया जाए और इसमें शामिल पक्षों की गोपनीयता को बरकरार रखा जाए। केंद्रीकृत राष्ट्रीय पोर्टल पर सूचना देने वाले/शिकायतकर्ता और 'संदिग्ध' के रूप में नामित व्यक्ति की गोपनीयता तब तक सुरक्षित रखी जानी चाहिए जब तक कि सूचना देने वाले/शिकायतकर्ता द्वारा ई-एफआईआर पर हस्ताक्षर नहीं किए जाते। यदि पंजीकृत जानकारी पर निर्धारित समय के भीतर सूचना देने वाले द्वारा जानबूझकर हस्ताक्षर नहीं करते हैं, तो जानकारी को 2 सप्ताह के बाद केंद्रीकृत राष्ट्रीय पोर्टल से हटा दिया जाए। यौन अपराधों के मामले में पीड़ितों की निजता को सभी चरणों में प्रमुखता से ध्यान में रखा जाना चाहिए।

ज. क्षमता निर्माण पर विशेष बल दिया जाए।

7.15 अनुशंसित आई. टी. पहलों के सफल कार्यान्वयन के लिए, विभिन्न स्तरों पर क्षमता निर्माण अत्यंत महत्वपूर्ण है। इसलिए, यह अनुशंसा की जाती है कि पुलिस थाना स्तर पर प्रणाली को अपनाना सुनिश्चित करने के लिए प्रशिक्षण कार्यक्रमों में सी. सी. टी. एन. एस.विशिष्ट कार्यक्रमों के अलावा सामान्य/बुनियादी कंप्यूटर जागरूकता कार्यक्रमों को शामिल किया जाना चाहिए।

7.16 विधि विद्यालयों/महा विद्यालयों/विश्वविद्यालयों में विधिक सेवा क्लीनिकों को इस ऑनलाइन क्रांति को लाने में उत्प्रेरक और सहायक के रूप में कार्य करना चाहिए।

7.17 ई-एफआईआर के पंजीकरण के कार्यान्वयन के लिए जागरूकता को बढ़ावा देने के लिए, इस सुविधा के बारे में जानकारी का व्यापक रूप से प्रसार किया जाए ताकि आम आदमी को प्रक्रियात्मक औपचारिकताओं की बाधाओं का सामना किए बिना अपराधों की रिपोर्ट करने के लिए प्रोत्साहित

[69] (2015) 6 एससीसी 287

किया जा सके।[70] चूंकि जन जागरूकता बढ़ाना एक निरंतर प्रक्रिया है, इसलिए निम्नलिखित तरीकों को अपनाया जा सकता हैः

क. ई-एफआईआर पंजीकरण के पंजीकरण के बारे में जानकारी सरकारी वेबसाइटों और पोर्टलों पर प्रमुखता से प्रदर्शित की जानी चाहिए, जिसमें विस्तृत गाइड, अक्सर पूछे जाने वाले प्रश्न, इन्फोग्राफिक्स और वीडियो ट्यूटोरियल शामिल हों।

ख. ई-एफआईआर के पंजीकरण की प्रक्रिया के बारे में जनता को शिक्षित करने के लिए विभिन्न क्षेत्रों में कार्यशालाएं और वेबिनार आयोजित किए जा सकते हैं।

ग. समाचार पत्रों और पत्रिकाओं मेंविज्ञापन, विशेष रूप से क्षेत्रीय और स्थानीय प्रकाशनों में दिए जा सकते हैं।

घ. जनता को पहल की प्रगति और प्रणाली में किए गए किसी भी सुधार के बारे में सूचित किया जाना चाहिए।

झ. विविध अनुशंसाएं

7.18 सभी ई-एफआईआर को पुलिस की वेबसाइट को ई-कोर्ट पोर्टल से जोड़कर संबंधित न्यायालयों को अग्रेषित किया जाना चाहिए। इसे इंटर-ऑपरेबल क्रिमिनल जस्टिस सिस्टम (आईसीजेएस) का उपयोग करके किया जा सकता है जो ई-एफआईआर पर डिजिटल हस्ताक्षर करने और इसे स्वचालित रूप से अदालत को भेजता है।

7.19 ई-एफ. आई. आर. के पंजीकरण को सुगम बनाने के लिए भारतीय साक्ष्य अधिनियम, 1872, सूचना प्रौद्योगिकी अधिनियम, 2000, भारतीय दंड संहिता, 1860 और अन्य विधानों में उपयुक्त संशोधन करने की अनुशंसा करता है।

7.20 आठ राज्यों में विनिर्दिष्ट अपराधों के लिए आंशिक रूप से कार्यान्वित की जा रही एफ. आई. आर. के इलेक्ट्रॉनिक रजिस्ट्रीकरण के प्रस्ताव (बी. पी. आर. एंड डी. द्वारा प्रदत्त सूचना के अनुसार) ने प्रस्तावित भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता विधेयक के खंड 173 के अधीन एक कदम आगे बढ़ाया है, जो सी. आर. पी. सी., 1973 का स्थान लेगा। हालांकि, नए विधेयक में प्रस्तावित खंड 173 के अनुसार, जहां सूचना को संज्ञेय अपराधों के लिए इलेक्ट्रॉनिक रूप से अधिकार क्षेत्र पर किसी भी बाधा के बिना दिया जा सकता है, पुलिस अधिकारी को पहली जानकारी देने के तीन दिनों के भीतर हस्ताक्षर किए जाने के बाद इसे रिकॉर्ड करना आवश्यक है। इसके अलावा, इसे राज्य सरकार द्वारा निर्धारित पुलिस अधिकारी द्वारा एक पुस्तक में रिकॉर्ड के लिए रखा जाना चाहिए।

[70] कोडुंगल्लूर फिल्म सोसाइटी बनाम यूनियन ऑफ इंडिया, (2018) 10 एससीसी 71

7.21. ई-एफआईआर या ई-शिकायत दर्ज करने के लिए विकसित ऑनलाइन पोर्टल उपयोगकर्ता के अनुकूल होना चाहिए। अनुलग्नक- ख के तहत प्रस्तावित एक केंद्रीकृत प्रणाली को इलेक्ट्रॉनिक संचार के माध्यम का विस्तार करने के लिए सूचना प्रसंस्करण के लिए स्थापित किया जा सकता है। पुलिस अधिकारी इस पोर्टल पर दी गई जानकारी का उपयोग यह जांचने के लिए करेगा कि कोई संज्ञेय अपराध किया गया है या नहीं और तदनुसार आगे की कार्रवाई करेगा।

7.22 ई-एफ. आई. आर. के पंजीकरण के लिए निर्धारित अनुलग्नक-क के अनुसार सुझावात्मक प्रक्रिया अपनाई जा सकती है।

आयोग तदनुसार सिफारिश करता है।

---xxx---

अनुलग्नक-क ई- एफआईआर दर्ज करवाने के लिए प्रक्रिया

(पुलिस एवं अन्य जांच ऐजेन्सियों द्वारा पालन किया जाए)

चरण 1: केन्द्रियकृत राष्ट्रीय पोर्टल से संबंधित पुलिस स्टेशन को सूचना भेजी जाती है।

↓

पोर्टल से ऑनलाइन जानकारी को संभालने वाला पुलिस अधिकारी, मुखबिर/सूचनाकर्ता द्वारा केंद्रीकृत राष्ट्रीय पोर्टल पर दिए गए विवरणों की जांच करेगा और जांच करेगा कि क्या कोई संज्ञेय अपराध हुआ है अथवा नहींजिसमें 3 साल तक की सजा हो सकती है (जैसा कि भारतीय दंड संहिता, 1860 और उस समय लागू अन्य विशेष कानूनके तहत निर्धारितकिया गया है।)

चरण 2: 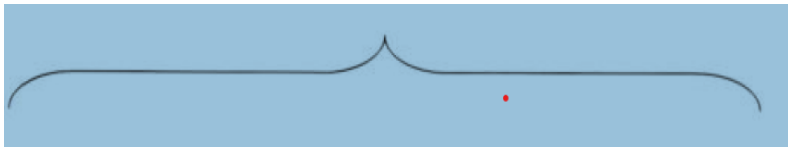

क. संज्ञेय अपराध की स्थिति में

यदि 3 वर्ष तक की सजा का प्रावधान वाला संज्ञेय अपराध किया गया है।

पुलिस अधिकारी सभी प्रासंगिक विवरणों का उल्लेख करते हुए अनुलग्नक-ग में दिए गए निर्धारित प्रारूप में उक्त जानकारी को पंजीकृत करेगाः -

1. शामिल अधिनियम,
2. कानून की प्रासंगिक धाराएँ।
3. घटना का स्थान।
4. घटना का समय,

5-संबंधित पुलिस थाना।

6. बीट नंबर आदि।

यदि 3 वर्ष से अधिक की सजा का प्रावधान वाला संज्ञेय अपराध किया गया है।

पुलिस अधिकारी दंड प्रक्रिया संहिता, 1971 की धारा 15.1 के अनुसार प्राथमिकी दर्ज करने के पारंपरिक तरीके का पालन करेंगे।

ख. गैर-संज्ञेय अपराध की स्थिति में

पुलिस अधिकारी ई-एफ. आई. आर. के रूप में जानकारी दर्ज नहीं करेगा और लिखित रूप में इसके कारण बताएगा। कारणों को 'स्टेटस' टैब के तहत केंद्रीकृत राष्ट्रीय पोर्टल पर भी अपलोड किया जाएगा।

जहां गैर-संज्ञेय अपराध किया जाता है, वहां पुलिस दंड प्रक्रिया संहिता, 1973 की धारा 155 के अनुसार कार्रवाई करेगी।

केंद्रीकृत राष्ट्रीय पोर्टल पर सूचना प्राप्त होने के 3 दिनों के भीतर इसे पुलिस अधिकारी द्वारा पूरा किया जाना चाहिए

चरण 3: निर्धारित एफआईआर प्रारूप में जानकारी दर्ज करने वाला पुलिस अधिकारी मुखबिर सूचना देने वाले को (मोबाइल पर मैसेज के माध्यम से या किसी अन्य इलेक्ट्रॉनिक मोड का उपयोग करके और पोर्टल पर, 'स्टेटस' टैब के तहत) सूचित करेगा।

- ❖ यह प्रत्येक मामले में स्वचालित रूप से चला जाएगा, चाहे जानकारी निर्धारित एफआईआर प्रारूप में दर्ज की गई हो या नहीं।

चरण 4:

यदि एफआईआर पर हस्ताक्षर कर दिए जाते हैं।

↓

ई-एफआईआर पंजीकृत की जाएगी।

↓

उसका सार राज्य सरकार द्वारा विहित प्रपत्र में कार्यालय द्वारा रखे जाने वाली पुस्तक में दर्ज किया जाएगा और ई-एफ. आई. आर. को 24 घंटों के भीतर संबंधित पुलिस थाने की वेबसाइट पर अपलोड किया जाएगा।

यदि एफआईआर पर03 दिनोंमें मुखबिर द्वाराजानबूझकर हस्ताक्षर नहीं किए जाते हैं।

↓

पुलिस अधिकारी को लिखित में कारण दर्ज करने के बाद ई-एफआईआर दर्ज करने की आवश्यकता नहीं है।

दो सप्ताह के बाद, उक्त जानकारी (जैसा कि केंद्रीकृत राष्ट्रीय पोर्टल पर सूचना देने वाले द्वारा प्रदान की गई है) स्वचालित रूप से पोर्टल से हटा दी जाएगी।

- इस सुविधा के बावजूद, मुखबिर/सूचना देने वाला प्रथम इत्तिला रिपोर्ट दर्ज करने के उद्देश्य से पारंपरिक तरीके को अपनाने के लिए स्वतंत्र है।

अनुलग्नक - ख केन्द्रिकृत राष्ट्रीय पोर्टल

(एफआईआरदर्ज करने के लिए उपयोग किया जाए)

चरण 1: चयन करें

राज्य

जिला

पिन कोड

पुलिस स्टेशन (वैकल्पिक)

चरण 2: साईन अप करने की प्रक्रिया

मोबाईल नम्बर,

ओटीपी

पूरा नाम

कैप्चा

चरण 3: उपयोगकर्ता का विवरण उपलब्ध करवाने के चरण:

1. नाम
2. लिंग
3. जन्म तिथि
4. पता
5. मोबाईल नम्बर
6. आधार नम्बरया सरकार द्वारा जारी कोई भी अन्य वैद्य पहचान पत्र
7. वैद्य पहचान पत्र का साक्ष्य अपलोड करना

चरण 4: घटना की प्रकृति

निम्नलिखित एक सुझावात्मक ड्राप डाऊन सूची है जो निम्नलिखित के विरुद्ध होने वाले अपराधों को वृहद रुप से वर्गीकृत करता है:-

1. बच्चों के विरुद्ध
2. सुरक्षा एवं अर्द्धसैनिक बलों के विरुद्ध
3. विभाग के विरुद्ध
4. विदेशी नागरिकों के विरुद्ध
5. व्यक्ति विशेष के विरुद्ध
6. संगठन के विरुद्ध
7. पुलिस अधिकारियों के विरुद्ध
8. लोक सेवकों के विरुद्ध
9. जनता के विरुद्ध
10. वरिष्ठ नागरिकों के विरुद्ध
11. महिलाओं के विरुद्ध
12. सायबर अपराध
13. जंगली जानवरों के मुकद्दमे
14. कोई अन्य मुकद्दमे

चरण 5: घटना का विवरण

1. घटना की तारीख (दिनांक/माह/वर्ष);(___से___तक)
2. घटना स्थल (राज्य-जिला-संभाग आदि)
3. घटना का समय (घंटे:मिन्ट:सैकेण्ड)
4. घटना का विवरण (सम्पूर्ण विवरण)

चरण 6: संदिग्ध का विवरण

क्या आप संदिग्ध को पहचान सकते हैं?

_____

हां	नहीं

1. संदिग्ध का नाम
2. संदिग्धों की संख्या

3. उम्र
4. लिंग
5. यदि संदिग्ध द्वारा किसी वाहन का उपयोग किया गया है तो उसका पंजीकृत नम्बर
6. यदि किसी भी प्रकार का हथियार का उपयोग किया गया है तो उसका विवरण

चरण 7: कोई अन्य विवरण

चरण 8: उद्घोषणा

मैं.....यह घोषणा करता हुं कि उपरोक्त दी गई जानकारी मेरे सर्वोत्म ज्ञान, विश्वास, जानकारीके अनुसार पूर्ण रुपेण सत्य है और किसी भी प्रकार की सूचना को न तो छिपाया गया है और नहीं विकृत किया गया है। यदि मेरे द्वारा दी गई जानकारी असत्य या तुच्छ पाई जाती है तो मेरे ऊपर उस समय लागू कानून के तहत अभियोजन/सजा दीजाए।

चरण 9: हस्ताक्षर

चरण 10: दी गई सूचना पर पुलिस द्वारा की गई कार्रवाई/स्थिति: मुखबिर की सुविधा के लिए एक टैब होना चाहिए जहां पर उपरोक्त सूचना पर पुलिस द्वारा की गई कार्रवाई के बारे में पता किया जा सके।

केन्द्रियकृत राष्ट्रीय पोर्टल पर ई एफआईआर के एक ही एफआईआर में समान घटना के विवरण (जैसे घटना का दिनांक, समय, स्थान, और संदिग्ध का नाम) को बार बार दर्ज होने से रोकने के लिए एक जांच बिन्दु होना चाहिए।

ह0/-

[न्यायमूर्ति ऋतु राज अवस्थी]
अध्यक्ष

ह0/-

[न्यायमूर्ति के.टी. शंकरन]
सदस्य

ह0/-

[प्रो. (डॉ) आनन्द पालीवाल]
सदस्य

ह0/-

[प्रो. डी. पी. वर्मा]
सदस्य

ह0/-

[श्री के. बिस्वाल]
सदस्य सचिव

ह0/-

[डॉ. नितेन चन्द्रा]
सदस्य (पदेन)

ह0/-

[डॉ रीटा वशिष्ठ]
सदस्य (पदेन)

ह0/-

[श्री एम. करुणानिधि]
अंशकालिक सदस्य

ह0/-

[प्रो. (डा.) राका आर्या]
अंशकालिक सदस्य